R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.oksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 07
01 से 15 जनवरी 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

आरक्षण में फंसी 'पंचायत'

अब सबकी निगाहें सुप्रीम आदेश पर...

पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी...

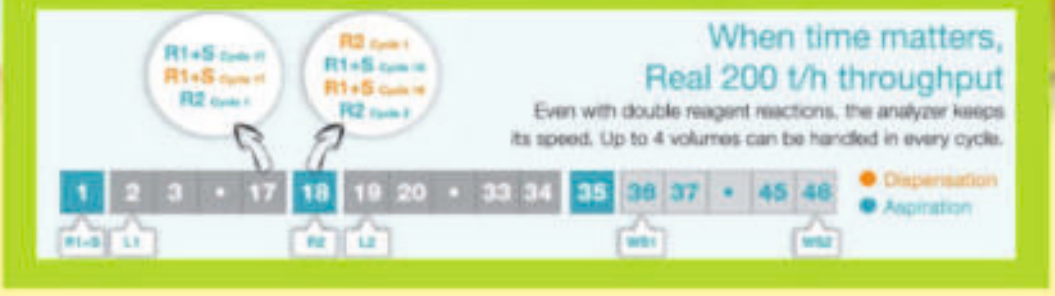

ANU SALES CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology & Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | संगठित अपराध पर होगा कंट्रोल

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा को देखते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए जहां भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, वहीं प्रदेशभर में पुलिस...

राजपथ

10-11 | आत्मनिर्भर मप्र पर फोकस...

आज मप्र देश में सबसे तेजी से विकास करता प्रदेश बना हुआ है, तो इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीति और नीयत है। वे पिछले डेढ़ दशक से प्रदेश को फर्श से उठाकर अर्श पर लाने के अभियान में जुटे हुए हैं...

विकास

12 | अब विकास का बुधनी मॉडल

प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र बुधनी अब देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर रोल मॉडल बनेगा। इसके लिए प्रदेश के आला अफसर कार्य योजना बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किए जा रहे हैं। बुधनी मॉडल...

विडंबना

14 | मास्टर प्लान दूर की कौड़ी

मप्र की राजधानी के विकास की रूपरेखा बिना मास्टर प्लान ही तैयार हो रही है। 28 साल बाद भी मास्टर प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस बार करीब 9 साल से बन रहा भोपाल का मास्टर प्लान जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। प्रस्तावित मास्टर...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र के पंचायत चुनाव के लिए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर शह-मात का ऐसा खेल खेला गया जो पहले कभी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिला। पार्टियों के दफ्तर से लेकर वकीलों के घर, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय, विधानसभा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दांवपेंच चलता रहा, लेकिन लगभग 7 वर्षों के बाद प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव आखिर निरस्त हो ही गए। अब ये चुनाव कब होंगे, इस पर असमंजस बरकरार है।

राजनीति

30-31 | जिताने-हराने का मंसूबा

उप्र में चल क्या रहा है और तस्वीर आखिर है क्या? इस वक्त अगर उप्र चुनाव को लेकर आम लोगों से बातचीत की जाए तो लोग एक क्षण में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाते हैं। दूसरे क्षण अखिलेश यादव, तीसरे क्षण कहने लगेंगे कि बसपा कांग्रेस को बिल्कुल कमजोर...

महाराष्ट्र

35 | नंबरों से छेड़छाड़

महाराष्ट्र में कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक्स और भ्रष्टाचार के मुद्दे ने, विधानसभा के चालू सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया है और इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन, जहां राज्य सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, वहीं, इसका खामियाजा छात्रों...

बिहार

38 | बिहार में टकराव

बिहार में बहार है, 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही ये नारा बदल चुका है, अब तो लगता है जैसे नारा होना चाहिए- बिहार में बवाल है। नौबत ये आ चुकी है कि एनडीए के भीतर संघर्ष का नया दौर बिहार में शुरू हो चुका है।

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

....क्या पता, घर पहुंचे अथवा नहीं

किसी शायर ने क्या खूब कहा है...

घर से निकलो तो पता जेब में डालकर निकलो,
क्योंकि हादसे चेहरे की पहचान मिटा देते हैं...।

यह शेर स्मार्ट सिटी भोपाल की यातायात व्यवस्था और सड़कों पर सटीक बैठता है। शहर का विकास तो तेजी से हो रहा है, लेकिन आम आदमी की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। अब सड़कों को ही ले लें...तो सड़कों पर चलने की पहली प्राथमिकता पैदल चलने वालों की होती है। इसके लिए बकायदा फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण किया जाता है। लेकिन राजधानी में अधिकांश सड़कों के किनारे फुटपाथ ही नहीं है और जहां फुटपाथ है, वहां अतिक्रमण है। जेब्रा क्रॉसिंग का तो अता-पता ही नहीं है। ऐसे में सड़क हादसों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जबकि हर साल सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और सालभर प्लानिंग चलती रहती है। उसके बावजूद शहर सहित प्रदेशभर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी में प्रमुख सड़क से लेकर कॉलोनियों की सड़कों पर हर पांच कदम पर गड्ढे मिल जाएंगे। बीच सड़क या सड़क किनारों पर खुले मेनहोल भी हादसों को न्यौता दे रहे हैं। जब आदमी घर से निकलता है तो उसे खुद ही पता नहीं रहता है कि वह सुरक्षित घर पहुंच पाएगा या नहीं। वैसे ये हाल केवल भोपाल या मप्र का नहीं, बल्कि देशभर का है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में सड़क हादसों में लगभग 72 हजार पैदल राहगीरों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 2020-21 में देशभर में कई माह कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सालाना करीब साढ़े चार लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। आमतौर पर यह एक धारणा बन गई है कि सड़कें वाहनों के परिचालन के लिए हैं, चाहे वे चार पहिए वाले हों या दो पहिए वाले उनका ही सड़कों पर पहला हक है। यह बात केवल शहरों के बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए हाईवे या एक्सप्रेस-वे के लिए ही लागू नहीं है, बल्कि शहरों के अंदर भी पैदल यात्रियों के लिए गाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाई गई सड़कों के दोनों ओर बची जगह ही है, जो जरूरी नहीं कि सही तरह से फुटपाथ के रूप में भी बनी हो। सांसद और विधायक कोष से कांक्रीट सड़कों, गलियों में ज्यादातर में फुटपाथ की सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। शहरों की योजनाओं में गाड़ियों के आवागमन की सुविधा पहले पायदान पर और पैदल यात्रियों की सुविधा निचले स्थान पर जाने लगी है। विगत कुछ दशकों में यही सोच गलियों (जिनमें फुटपाथ का होना संभव ही नहीं या कहें कि जो सही मायने में पैदल के लिए ही है) के लिए भी बन गई है और यह सोच केवल शहरों तक नहीं, बल्कि गांवों में भी वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या और सड़कों का जाल बिछने के कारण वहां भी बढ़ने लगी है। वैसे भी आजकल शहरों और यहां तक कि गांवों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि घर के आसपास से सामान लेने या छोटी दूरी के लिए भी लोग वाहन होने पर पैदल नहीं जाते हैं। ऐसे में यह एक विडंबना की स्थिति है कि एक तरफ जहां पैदल चलना स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है और शहरों में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए लोगों से यह अपील और उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी जीवनशैली में बदलाव लाते हुए निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें। वहीं दूसरी ओर पैदल यात्रियों से यह उम्मीद की जाती है कि सड़कों पर वह स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 जनवरी, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

कैसे रुकेगा अवैध खनन ?

प्रदेश में नर्मदा, चंबल, सोन सहित जितनी नदियां हैं उनमें अवैध रेत का खनन जोरों पर है। सोन नदी में रेत उत्खनन व परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद रेत की निकासी पर रोक नहीं लग पा रही है। इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

● **सृष्टि मिश्रा,** इंदौर (म.प्र.)

सख्त होगी सरकार

दो साल पहले समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूं खरीदकर मप्र देश में रिकार्ड भी बना चुका है। इसी तरह धान का उपार्जन भी प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। मप्र की शिवराज सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मूंग सहित अन्य उपज खरीदने की व्यवस्था को सख्त बनाने जा रही है।

● **देव साहू,** ग्वालियर (म.प्र.)

भगवान भरोसे गौशालाएं

मप्र में बीते एक साल में शुरू की गई गौशालाओं में संचालकों द्वारा अनुदान के नाम पर खेल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद से नई गौशालाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में बिना अनुदान के प्रदेशभर की गौशालाएं भगवान भरोसे चल रही हैं।

● **नीलेश शाक्या,** भोपाल (म.प्र.)

पुलिस कमिश्नर प्रणाली से कई उम्मीदें

मप्र के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। यह एक अच्छा कदम है। यह एक बड़ा प्रयोग है, जिसका इंतजार मप्र पिछले चार दशक से कर रहा था और अब यह जब अमल में आ गया है तो इसे काम करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि जनता और सरकार की उम्मीदों पर पुलिस कितना खरा उतरती है। अगर आम आदमी पुलिस के पास तत्परता से अपनी शिकायत पहुंचा सके और उसकी शिकायतों का तेजी से निराकरण हो सके तो निश्चित तौर पर आम व्यक्ति भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली का स्वागत ही करेगा। वैसे भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही भले ही पुलिस का पावर बढ़ा है, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है।

● **कीर्ति शर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

आत्मनिर्भर होगा मप्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही प्रयास है कि आज मप्र तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। गौरवशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मप्र आज अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में औद्योगिक विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है।

● **सबा खान,** कटनी (म.प्र.)

महिलाओं को आगे आना होगा

देश की आजादी में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी है। जिस तरह महिलाओं ने आजादी आंदोलन में अपना योगदान दिया और भारतीय राजनीति को दिशा दी। वैसे ही आजादी के बाद भी महिलाओं का राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी वर्तमान समय में भी अनेक महिलाएं राजनीति सहित अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना होगा।

● **पवन सिंह,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

चहेते अफसरों की आपसी रार से परेशान योगी

उप्र में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ भाजपा के करीबी रहे अफसरों के माथे में चिंता की लकीरें गहराने लगी हैं। सत्ता गलियारों में खासी चर्चा उन अफसरों को लेकर है जिन्हें मुख्यमंत्री योगी का खासा करीबी माना जाता है। कहा-सुना जा रहा है कि यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ऐसे अफसरों पर नई सरकार की टेढ़ी नजर रहनी तय है। इन चर्चाओं के बीच एक अन्य चर्चा ऐसे अफसरों की आपसी रार को लेकर भी खूब चल रही है। लखनऊ के सत्ता गलियारों में मुख्यमंत्री योगी के खासे करीबी अफसर नवनीत सहगल, अवनीश अवस्थी और एसपी गोयल के मध्य चल रही 'कोल्ड वार' को लेकर नाना प्रकार की अफवाहों का बाजार गर्म है। सूत्रों की मानें ये तीनों अफसर मुख्यमंत्री के तो चहेते हैं, इनमें आपसी संबंध लेकिन बेहद खराब हो चले हैं। ऐसे में ये अफसर एक-दूसरे की बाबत खूब निगेटिव बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और उद्योगपति गौतम अडानी के संबंधों को लेकर कछ धमाकेदार खुलासा एक अन्य अफसर जल्द ही करने का दावा कर रहे हैं। इस सबके चलते मुख्यमंत्री योगी खासे चिंतित बताए जा रहे हैं।

अब महाराष्ट्र भी ममता के निशाने पर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों तेजी से अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का विस्तार करने में जुटी नजर आ रही हैं। दीदी ने गोवा, त्रिपुरा और मेघालय में अपने पांव जमा लिए हैं। अब खबर है कि उनका टारगेट महाराष्ट्र है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें मुंबई में एक प्लॉट आवंटित करे ताकि मुंबई में इलाज करवाने आने वाले पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार एक गेस्ट हाउस का निर्माण कर सके। उनके इस पत्र के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के भीतर बड़ी तोड़-फोड़ करने वाली हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इन दिनों ममता के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, ममता के निशाने पर विदर्भ क्षेत्र के बड़े कांग्रेसी नेता नरेश पुगलिया भी हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके पुगलिया एक बड़े ट्रेड यूनियन नेता भी हैं। खबर यह भी है कि असंतुष्ट कांग्रेसियों को तृणमूल से जोड़ने का काम ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं।

वी जॉर्ज रिटर्न्स

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय 24, अकबर रोड में इन दिनों बड़ी चर्चा है कि राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे-समझे जाने वाले के राजू का जलवा अब समाप्त हो चला है। राहुल के सरकारी आवास 12, तुगलक रोड से अपनी 'सल्तनत' चलाने वाले राजू केंद्र सरकार में सचिव रह चुके हैं। 2013 में आईएएस सेवा से त्यागपत्र दे के राजू कांग्रेस में शामिल हुए थे। राहुल संग करीबियत के चलते उन्हें 'राहुल गांधी का अहमद पटेल' कह पुकारा जाने लगा था। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राजू को एआईसीसी में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का मुखिया बनाया था लेकिन चलती उनकी हर एक मुद्दों पर थी। अब लेकिन कहा जा रहा है के राजू का डाउनफॉल हो चला है और उनके स्थान पर सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे वी जॉर्ज एक बार फिर से ताकतवर हो उभरने लगे हैं। लंबे अर्से तक हाशिए में पड़े जॉर्ज ने आते ही अपने करीबी कांग्रेसियों को मुख्यधारा में लाने का काम शुरू कर डाला है। पिछले दिनों कांग्रेस ने अपनी अनुशासन समिति का पुनर्गठन कर एके एंटोनी की अध्यक्षता में नई कमेटी का ऐलान किया जिसमें वी जॉर्ज की छाप स्पष्ट नजर आई। कमेटी में जॉर्ज के करीबी पी परमेश्वर और अंबिका सोनी का होना साफ करता है जॉर्ज ने अपनी धमाकेदार रिएंट्री करा डाली है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में जॉर्ज का प्रयास पार्टी के लिए अगला अहमद पटेल बनना होगा।

नीतीश-भाजपा में दूरी

कभी गैर भाजपाई दलों की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की कतार में नंबर वन का दर्जा रखने वाले नीतीश कुमार अब मात्र बिहार की राजनीति तक सिमट कर रह गए हैं। पिछले 15 बरस से राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन नीतीश कुमार का जलवा दिनों-दिन कमतर होता जा रहा है। उनकी पार्टी जद(यू) का जनाधार लगातार घट रहा है। गत विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने ही सहयोगी दल भाजपा की कूटनीति के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा और जद(यू) मात्र 43 सीटें पाकर राज्य में तीसरे नंबर पर जा पहुंची। दरअसल, एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही लोक जनशक्ति पार्टी ने बगावत कर जद(यू) के खिलाफ हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार राजद को लाभ पहुंचाने का काम कर डाला। नीतीश समर्थकों का मानना है कि ऐसा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भाजपा के इशारे पर किया। हालांकि भाजपा ने नंबर वन पार्टी होते हुए भी सरकार की कमान नीतीश बाबू को ही सौंपी है लेकिन उनके पर कतर डाले हैं।

बेचारे बाबुल, ना घर के ना...

बाबुल सुप्रियो राजनीति में आकर बड़ी भूल कर बैठे हैं। हिंदी, बंगाली और उड़िया के मशहूर गायक रहे सुप्रियो ने 2014 में राजनीति में प्रवेश किया था। वे भाजपा के टिकट पर संसद पहुंचे और नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री बन बैठे। भाजपा ने उनकी लोकप्रियता को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खासा इस्तेमाल किया। 2019 के आम चुनाव में वे दोबारा सांसद बने। उन्हें एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। उन पर कई बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल समर्थकों द्वारा हमला भी किया गया लेकिन मोदी भक्ति में तल्लीन सुप्रियो घबराए नहीं। वे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों तक ममता बनर्जी की खिलाफत का झंडा बुलंद किए रहे। इन चुनावों में भाजपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। यहीं से उनका 'डाउनफॉल' शुरू हो गया। वे तृणमूल प्रत्याशी के हाथों करारी मात खा गए। इस हार से उन्हें गंभीर सदमा पहुंचा। इसके बाद वे भाजपा से इस्तीफे देकर आए और फिर टीएमसी में चले गए।

पत्नी ने भी दे दिया धोखा

यह लोकोक्ति तो आपने सुनी ही होगी कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी के साथ हुआ है। साहब के जब दिन अच्छे थे तो घर ही नहीं बाहर भी उनकी पूछ-परख खूब होती थी। आलम यह था कि साहब को घर पर भी खूब मान-सम्मान मिलता था। साहब की पत्नी पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी पति के सेवा-सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। साहब के दिन अच्छे चल रहे थे कि अचानक एक मामले में साहब की जांच शुरू हुई। उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यहीं से साहब के दुर्दिन शुरू हो गए। अपने कार्यालय में सबके चहेते रहे साहब को घर बैठा दिया गया। साहब मन मसोसकर घर बैठे ही थे कि वे पत्नी को भी नागवार गुजरने लगे। साहब पर अपना लाड़-प्यार छिड़कने वाली पत्नी को कुछ दिनों बाद साहब खटकने लगे। यही नहीं अब तो मैडम ने साहब को घर से भी चलता कर दिया है। अब साहब की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे न तो घर के रहे और न घाट के। सूत्र बताते हैं कि साहब अब कहते फिर रहे हैं कि जिन लोगों के लिए मैंने रात-दिन एक करके कमाई की, उन लोगों ने ही आज मुझे पीठ दिखा दी। अब साहब की समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। साहब को भरोसा है कि आज नहीं तो कल उनके अच्छे दिन जरूर शुरू होंगे। तब वे पत्नी के धोखेबाजी का जवाब देंगे।

मंत्रीजी के पाप की पोटली पहुंची दिल्ली

प्रदेश में सरकार के मुखिया का पूरा जोर सुशासन पर है। इसके लिए वे रोज नए-नए कायदे-कानून गढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों पर उनके मंत्रिमंडल के ही कुछ सदस्य पानी फेर रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्रीजी की काली करतूतों से भरी पाप की पोटली दिल्ली पहुंच गई है। बताया जाता है कि मंत्रीजी के खिलाफ इतनी शिकायतें पहुंची हैं कि उससे आजीज आकर संगठन मंत्री ने उन्हें गत दिनों दिल्ली तलब किया था। वहां जब मंत्रीजी के सामने उनके पाप का पुलिंदा खोला गया तो मंत्रीजी भौचक्के हो गए। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी को इस बात का अहसास नहीं था कि कोई उनकी एक-एक करतूत पर नजर रखे हुए है। बताया जाता है कि संगठन मंत्री के सामने पहले तो मंत्रीजी नानुकुर करते रहे, लेकिन जब आरोपों के प्रमाण भी उनके सामने रखे गए तो वे बगले झांकने लगे। उन्होंने संगठन मंत्री को आश्वासन दिया है कि आइंदा वे ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे सरकार और पार्टी की छवि धूमिल हो। हालांकि मंत्रीजी के इस आश्वासन पर किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि मंत्रीजी के लिए लक्ष्मीजी से बड़ा कोई नहीं है और लक्ष्मीजी के लिए वे किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं।

माननीय के सामने साहबों की नहीं चली

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेड्स मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। कई मंत्री संघ और संगठन के सामने इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन गत दिनों एक मंत्रीजी ने अफसरों को ऐसा रूप दिखाया कि साहिबान उनके सामने पस्त हो गए। सूत्र बताते हैं कि एक मंत्री विगत दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे, तभी उनके पास एक फोन आया और वे रास्ते से लौट पड़े। वह फोन उनके एक चहेते अधिकारी का था, जिसका तबादला सूची से नाम काट दिया गया था। दरअसल, माननीय ने अपने विभाग के अफसरों के तबादले की अनुशंसा सूची सीएमओ भेजी थी। जहां कार्यालय के प्रमुख सचिव ने उनकी सूची में से एक-दो नाम नजरअंदाज कर दिए। बताते हैं कि ये प्रशासनिक मुखिया का कमाल था। फिर क्या था, मंत्रीजी ने आव देखा न ताव और धड़धड़ाते हुए सीएमओ पहुंच गए। उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा कि आप लोगों को जो भी मनमानी करनी है कर लो, पर मैंने जिन नामों की सूची भेजी है, उसमें से एक भी नाम कम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने धमकाते हुए ये भी कह दिया कि या तो निकालना है तो मैंने जो सूची भेजी है वह पूरी निकाल दो या फिर एक भी नाम कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको जो करना है कर लो। यहां ये बता दें, कि मंत्रीजी को आखिर 200 किमी का रास्ता पार कर वापस आना पड़ा। इसके पीछे कुछ न कुछ तो राज है।

साहब की बलिहारी

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है। यह चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि साहब ने कोई बड़ा काम कर दिखाया है, बल्कि साहब चर्चा में इसलिए हैं कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राजधानी में पदस्थ उक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सीहोर जिले के एक तहसील में जमीन है। उक्त जमीन पथरीली है। साहब ने उपजाऊ बनाने के लिए उसे मिट्टी से भरवाना शुरू कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहब के निजी खेत पर सरकारी वाहनों से मिट्टी डलवाई जा रही है। ये वाहन किसकी अनुमति से ऐसा कर रहे हैं, यह तो कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि साहब का रसूख इतना बड़ा है कि वे स्वयं के आदेश पर भी ऐसा करवा सकते हैं। प्रदेश के मंत्रालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक में यही चर्चा है कि एक तरफ सरकार आर्थिक बदहाली के इस दौर में विभागों से मितव्ययता बरतने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ साहब सरकारी वाहनों से अपने खेत पर मिट्टी डलवा रहे हैं। इससे सरकार को बड़ी चपत लगेगी।

न्याय नहीं वोट की चिंता

मौके की नजाकत को भांपकर कदम उठाना राजनीति का पहला चरित्र होता है। प्रदेश में राजनीति का यह चरित्र उस समय देखने को मिला जब नेमावर नरसंहार में बची एकमात्र लड़की ने 1 जनवरी से न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर लड़की की न्याय यात्रा का पोस्टर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते उसको भरपूर समर्थन मिलने लगा। बात बिगड़ती देख सरकार ने भी नरसंहार की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर डाली। लेकिन सरकार के इस कदम को लोग न्याय की नहीं बल्कि वोट की नजर से देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने आदिवासी वोटबैंक को देखते हुए यह कदम उठाया है। अगर सरकार वाकई इस नरसंहार में पीड़ित को न्याय दिलाना चाहती है तो उसे पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर देनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के साथ ही कई सामाजिक संगठन इसकी मांग कर रहे थे। भले ही इस नरसंहार की सीबीआई जांच के पीछे सरकार की मंशा कुछ भी हो, लेकिन इससे नेमावर नरसंहार कांड की असली वजह सामने आने का रास्ता साफ हो गया है।

अक्स का आईना

उप्र के चुनाव से पहले ही राजनेताओं के करीबियों की तिजोरियां नोट उगलने लगी हैं। बक्सों में भर-भरकर नोट निकल रहा है। यह नोट चुनाव में उपयोग होता, लेकिन जांच एजेंसियों ने विपक्षियों की मंशा पर पानी फेर दिया है।

● **नरेंद्र मोदी**

मैंने समय पर सही फैसला ले लिया है। अगर कांग्रेस में रहता तो मेरा दम घुटता और पंजाब का भी। अब मैं नई पार्टी के साथ पंजाब के विकास की नई कहानी लिखूंगा। आने वाला समय पंजाब का होगा। कांग्रेस में मुझे वह सब करने को नहीं मिल रहा था, जिससे पंजाब का समुचित विकास हो सके। आगामी चुनाव में मेरी गठबंधन की सरकार बननी तय है।

● **अमरिंदर सिंह**

मैंने कभी भी भारतीय टीम में भेदभाव नहीं किया। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय टीम किसी को भी हराने का दम रखती है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और वर्तमान समय में उन प्रतिभाओं को समय पर प्लेटफार्म मिल रहा है। मैं भले ही अब भारतीय टीम के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन उम्मीद है, टीम निरंतर अच्छा प्रदर्शन करेगी।

● **रवि शास्त्री**

भारत आतंकवाद की आड़ में अपने पड़ोसी देशों को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। जबकि भारत के अंदर ही लोग आपस में जाति-धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। ऐसे में भारत को हमारी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करने की जरूरत है।

● **इमरान खान**

साल 2021 ने मुझे यह एहसास कराया कि ऑडियंस चाहती है कि मैं कुछ लीक से हटकर काम करूं, और मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सभी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा और प्यार दिया है। यह एक ऐसा साल रहा है, जिसने ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करने के मेरे भरोसे को मजबूती दी है, जो महत्वपूर्ण रूप से आज की सोच और ट्रेंड से आगे हैं। मैं अपने आपको बहुत लकी महसूस करती हूं कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझ पर भरोसा किया। मेरे फैन्स का भी आभार जिन्होंने मुझ पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा और मुझे मेरा काम करने के लिए इंस्पायर किया।

● **परिणीति चोपड़ा**

वाक्युद्ध

देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसके बावजूद सरकार जनता पर टैक्स पर टैक्स लगा रही है। उधर, प्रधानमंत्री मनगढ़ंत आंकड़े परोसकर आत्मनिर्भर भारत की गाथा गा रहे हैं, जबकि आम आदमी महंगाई, गरीबी, भुखमरी से बेहाल है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या अच्छे दिन का ऐसा ही हाल रहेगा।

● **प्रियंका गांधी**

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। देश में 60 साल से अधिक समय तक उन्होंने राज किया है। अब देश में विकास की गति बढ़ रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरते तो जनता हमें लगातार चुनाव में विजयी नहीं बनाती।

● **अमित शाह**

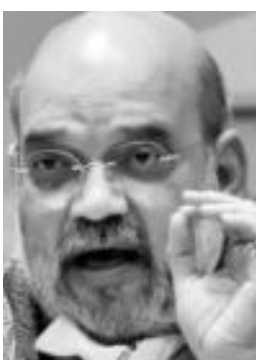

संगठित अपराध पर होगा कंट्रोल

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा को देखते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए जहां भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, वहीं प्रदेशभर में पुलिस प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। इस काम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा लगे हुए हैं। सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली (संशोधन) विधेयक 2021 के बाद अब प्रदेश में दो अन्य बिल लाए जा रहे हैं, ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में **गैंगस्टर विरोधी विधेयक तथा पब्लिक सेफ्टी बिल** लाए जाएंगे।

सरकार नए साल में मप्र गैंगस्टर विरोधी विधेयक (एक्ट) ला रही है। इसमें ऐसे बड़े अपराधी जो शराब का कारोबार करते हैं, जुआ खिलाते हैं, भूमाफिया, वन माफिया, विस्फोटक आदि से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग एक्ट के प्रावधानों को तैयार कर रहा है। इस एक्ट में 2 से 10 साल तक की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। अगर अपराधी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी पर हमला करता है, तो उसमें 2 साल की सजा को 5 साल और 5 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर 30 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। इस एक्ट के तहत गैंगस्टर के सहयोगी पर भी 3 से 10 साल की सजा व जुर्माना होगा। गैंगस्टर के काले कारनामे बेनकाब कर उनकी बेहिसाब संपत्तियां भी राजसात होंगी। इस एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन होगा जिसमें ट्रायल चलेंगे। खास बात यह है कि इसमें गैंगस्टर की अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलेगी और बयान, साक्ष्य आदि एक्चुअल व वर्चुअल, जैसे भी स्थितियां जारी रहेगी। एक्ट में साक्षियों का विशेष ध्यान रखा गया है। इनके बयान जज के समक्ष बंद कमरे में होंगे व पूरी सुरक्षा दी जाएगी।

वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत प्रावधान किया गया है कि जिस संस्थान में **100 या उससे अधिक लोग जुटते हैं, वहां कैमरे लगाना अनिवार्य है।** वहीं अपराध और अपराधियों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए शुरू की गई डायल-100 वाहन व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। मप्र में डायल-100 वाहन अत्याधुनिक कैमरों और सुविधाओं से लैस रहेंगे। डायल-100 वाहनों में डैस बोर्ड कैमरा व स्टाफ के लिए बॉडी वार्न कैमरा लगेगा। इसे लाइव कंट्रोल रूम से देखा जा सकेगा। सरकार की महती योजना डायल-100 में एफआरवी (फ्रंट रिस्पांस व्हीकल) वाहनों की संख्या बढ़ाई जा रही हैं। मौजूदा 1000 वाहनों को बढ़ाकर अब 1200 किया जा रहा है। निविदा अवधि में वाहनों की संख्या 2000 तक बढ़ाने की सीमा भी निर्धारित की गई है। नए वाहन अत्याधुनिक कैमरों और सुविधाओं से लैस रहेंगे।

जानकारी के अनुसार मप्र सरकार ने नए वाहनों को मंजूरी दे दी है और जल्दी इसको लेकर निविदा जारी की जाएगी। डायल-100 सेवा का वर्तमान डाटा सेंटर, स्टेट डाटा सेंटर में शिफ्ट करने का प्रावधान है। मैप आईटी के डिजास्टर रिकवरी सेंटर उपयोग में आने से कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा। सभी एफआरवी वाहनों में डैस बोर्ड कैमरा, ड्यूटी में तैनात स्टाफ के लिए बॉडी वार्न कैमरा लगाया जाएगा। इसे लाइव कंट्रोल रूम से देखा जा सकेगा।

जानकारी के अनुसार योजना के दूसरे फेज में वाइस कॉल के अलावा एसएमएस और सोशल मीडिया पैनिक बॉटम से जानकारी प्राप्त होने पर इवेंट तैयार कर एफआरवी वाहन डिस्पैच किए जाने की सुविधा रहेगी। नागरिकों के लिए सभी आपात सेवाओं पुलिस, फायर, एंबुलेंस के लिए एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा रहेगी। पुलिस अधिकारियों की सतत् निगरानी के लिए अलग मोबाइल ऐप का प्रावधान है। डायल-100 सेवा का अन्य नागरिक सेवाओं जैसे फायर, सीसीटीवी (सेफ सिटी सर्विलेंस सिस्टम) सीसीटीएनएस और वल्लभ भवन के वातावरण के हिसाब से एकीकृत व्यवस्था का प्रावधान है। फोन किए जाने पर बगैर मोबाइल नंबर परिलक्षित हुए, एफआरवी से संपर्क की सुविधा, कॉलर और एफआरवी के मध्य हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की सुविधा रहेगी। स्टाफ के पास कॉलर का नंबर नहीं जाएगा, बल्कि एक वर्चुअल नंबर जाएगा, जिस पर इवेंट के ओपन रहते स्टाफ कॉलर से संपर्क कर सकेगा। कॉलर को पुलिस स्टाफ से बात करनी होगी, तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निजता और गोपनीयता के मकसद से यह व्यवस्था की गई है। वाहनों में स्ट्रेचर का प्रावधान है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। राज्यस्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम कॉलटेकर सीट संख्या 80 प्रति शिफ्ट से बढ़ाकर 100 प्रति शिफ्ट एवं डिस्पैचर संख्या 24 प्रति शिफ्ट से बढ़ाकर 40 प्रति शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है। निविदा अवधि में इनकी संख्या और अधिक बढ़ाने की सीमा निर्धारित की गई है। जीआईएस मैप का उन्नयन, कॉलर की लोकेशन की शुद्धता में सुधार के लिए प्राइवेट मैप प्रोवाइडर की सेवाएं ली जाएंगी।

● **सुनील सिंह**

अब पुलिस के जिम्मे होगा इंटिग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर

स्मार्ट सिटी का इंटिग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जल्द पुलिस के हवाले होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सेंटर में लगे कैमरों की मदद से पुलिस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी करेगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों को ई-नोटिस भेजकर चालानी कार्रवाई करेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी के कामकाज की समीक्षा की थी। इस दौरान भोपाल स्मार्ट सिटी के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि जब चौराहों पर पुलिस ने पहले से ही कैमरे लगा रखे हैं तो स्मार्ट सिटी ने क्यों लगाए? स्मार्ट सिटी चालान बनाएगी तो पुलिस क्या करेगी? स्मार्ट सिटी के कैमरे भी बंद पड़े हैं। इसके बाद ही आईसीसीसी स्मार्ट सिटी के हाथों से जाने का अंदेशा जताया जा रहा था। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। इंदौर सहित अन्य स्मार्ट सिटी को भी इससे जोड़ा गया। आईसीसीसी से शहरों की रियल टाइम मॉनीटरिंग की जाती है।

आत्मनिर्भर मप्र पर फोकस...

आज मप्र देश में सबसे तेजी से विकास करता प्रदेश बना हुआ है, तो इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीति और नीयत है। वे पिछले डेढ़ दशक से प्रदेश को फर्श से उठाकर अर्श पर लाने के अभियान में जुटे हुए हैं और आज उसी का परिणाम है कि मप्र देश के लिए विकास का मॉडल बना हुआ है। मप्र में विकास की रफ्तार तो वर्ष 2005 से शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें 2014 के बाद से गति आई है। इसकी वजह है डबल इंजन की सरकार। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में मप्र में तेजी से विकास हुआ है। अब मुख्यमंत्री और सरकार के सामने एक ही लक्ष्य है आत्मनिर्भर मप्र। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए संकल्पों के साथ नए साल का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए शासन-प्रशासन स्तर पर तैयारी चल रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिमाग में सोते-जागते बस प्रदेश के विकास और आम लोगों का कल्याण ही रहता है। वे हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए अब उनका एक ही लक्ष्य है और वह है आत्मनिर्भर मप्र बनाना। आत्मनिर्भर मप्र के लिए मुख्यमंत्री ने कई कदम उठाए हैं। अब नए साल में नए संकल्प के साथ शिवराज अभियान में जुटेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल की शुरुआत नए संकल्प के साथ करेंगे। वर्ष 2022 में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, विभागों में प्रशासनिक कसावट के साथ योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सर्वाधिक जोर रहेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को न सिर्फ मैदान में उतारा जाएगा बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं भी दौरे करने के साथ समीक्षा करेंगे। समीक्षा का सिलसिला 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा, जो 7 जनवरी तक चलेगा। इसमें सभी विभागों का प्रस्तुतीकरण होगा, जिसमें आत्मनिर्भर मप्र के तहत वर्ष 2022 के लिए विभाग की कार्ययोजना, मुख्यमंत्री की घोषणा आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्ष 2022 में प्राथमिकताएं तय करके काम करेगी। आत्मनिर्भर मप्र की कार्ययोजना के आधार पर विभागों के लक्ष्य निर्धारित होंगे। इसी आधार पर बजट भी तैयार होगा। समीक्षा में मुख्यमंत्री सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद अपनी अपेक्षाएं साझा करेंगे। दरअसल, फरवरी तक पंचायत और इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इससे सरकार कोई नया काम तो प्रारंभ नहीं कर पाएगी पर उसकी तैयारियां जरूरी कर ली जाएंगी ताकि चुनाव के बाद तेज गति के साथ धरातल पर काम होने लगे। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों

> *लक्ष्य बनाना और तय सीमा में उसे साधना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी खूबी है। अपनी इसी खूबी के तहत उन्होंने नववर्ष 2022 की शुरुआत नए संकल्पों के साथ करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका सबसे बड़ा संकल्प है, 2022 में मप्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को भी मिशन मोड में आने का निर्देश दिया है।*

19 माह में रिकार्डतोड़ विकास

शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका था। तब से लेकर अब तक कोरोना का साया मंडरा रहा है, लेकिन महामारी में भी प्रदेश का विकास प्रभावित नहीं हुआ। चौथी बार सत्ता में आने के बाद के इन 19 महीनों में प्रदेश में धुंआधार विकास कार्य हुए हैं। किसानों के लिए फसल बीमा से लेकर उनको अन्य प्रकार से मदद देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। कोरोना की दूसरी लहर को पूरी तरह नियंत्रण में किया है। मप्र कोरोना से डरने के बजाय लड़ता रहा और कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास के भी नए कीर्तिमान गढ़ता रहा। वर्ष 2020 में मप्र गेहूं उत्पादन में सभी राज्यों से आगे रहा और 1.29 करोड़ टन गेहूं का उपार्जन किया। किसानों के खातों में 75 हजार करोड़ रुपए भेजे। पिछले 19 माह में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 77 लाख किसान परिवारों को लगभग 5 हजार 500 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। कोरोनाकाल में राज्य में 5000 किमी नई सड़कों का निर्माण हुआ, जबकि 3500 किमी पुरानी सड़कों का नवीनीकरण हुआ। इसी अवधि में 154 नए पुल भी बनाए गए। भू-माफियाओं के कब्जे से 3 हजार 559 एकड़ भूमि मुक्त कराई है। अब आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार किया गया है। जिसे नए साल में साकार करना है।

के सम्मेलन करने के साथ सर्वाधिक जोर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने पर रहेगा।

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पिछले डेढ़ साल में सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए हैं। अब नए साल में सरकार ने हर हाथ को काम उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगा गया है। अभी तक मिले सुझावों में कहा गया है कि मनरेगा की तरह शहरी युवाओं के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाना चाहिए। छात्रों का काम पढ़ना और अच्छे नंबर लाना है। नौकरियों के सृजन की जिम्मेदारी शासन की है। युवाओं को मुफ्त भत्ता देना विकल्प नहीं है। इसके बजाय सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त नौकरियां हों। प्रदेश सरकार के लगभग सभी विभागों में ढाई लाख पद वर्षों से खाली पड़े हैं, उन्हें तुरंत भरना चाहिए। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयास होंगे तो नौकरियां मिलेंगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएं, उद्यम शुरू करने के अवसर देने का काम तेज करना होगा। सरकार को प्रदेश में स्टार्टअप का माहौल तैयार करना होगा। वहीं तय समय सीमा में सरकारी विभागों में भर्ती, रिजल्ट जारी हों। युवा हल्ला बोल एवं मतदाता कल्याण संघ मप्र के अध्यक्ष राज प्रकाश मिश्र कहते हैं कि प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा संविदाकर्मी, अतिथि शिक्षक, अन्य अनियमित कर्मी कई विभागों में बेरोजगार जैसी स्थिति में हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, वन समेत अन्य में दो से ढाई लाख खाली पदों पर भर्ती होने से लाखों युवाओं को स्थाई रोजगार मिल जाएगा। प्रदेश में खेती-किसानी के विकास पर सरकार का सबसे अधिक जोर है। कृषि बजट को आधुनिकीकरण और किसान के विकास पर खर्च करने की नीति बनाई जा रही है। पारंपरिक खेती के बजाय उन्नत खेती शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। किसान को प्रसंस्करण से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि वह उद्यमी बने। कृषि के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे समय रहते किसान को सही दिशा में ले जा सकते हैं।

प्रदेश सरकार नए साल में लक्ष्य बनाकर काम करने की रणनीति बना रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अफसरों को दिशा-निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शहरों के मास्टर प्लान बनाने की तैयारी करें। बिना मास्टर प्लान के शहरों की प्लानिंग नहीं हो सकती। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों एवं संबंधित अधिकारी मास्टर प्लान तैयार करें। आयुष्मान भारत योजना को बेहतर और प्रभावी बनाकर लागू करें। प्राइवेट अस्पतालों में इस योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन करें। मंत्रियों से कहा है कि वे राजस्व वृद्धि के प्रयास करें। केंद्र से 31 मार्च के पहले अधिक से अधिक राशि विभिन्न योजनाओं में लाएं। अफसरों के साथ दिल्ली जाएं। लंबित राशियों के प्रस्ताव फिर से भेजें। केंद्र की घोषणाओं व योजनाओं पर निगाह रखें। ज्यादा से ज्यादा राशि लाएं और बेहतर प्रदर्शन करें। जीएसटी में त्वरित कार्यवाही करें। मिलेट मिशन को प्राथमिकता से करें। उद्यानिकी फसलों व जैविक फसलों को बढ़ावा दें। नए साल में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री और सख्त होने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अफसरों से कहा है कि ब्रेन स्ट्रार्मिंग कर लें। समस्याओं का आंकलन करें। जहां जो जरूरत हो वो कदम उठाएं। नक्सलवाद, अपराध, महिला अपराध सहित हर समस्या पर ध्यान दें। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की प्रशंसा की है। लेकिन, इस योजना में अब हमें ड्रोन की कमी महसूस होती है। ड्रोन के भविष्य के हिसाब से काम हो।

मुख्यमंत्री ने नए साल में नए सैनिक स्कूल खोलने, नई टाउनशिप बसाने, लोक अदालतों का आयोजन करने, स्टार्टअप पर ध्यान देने, सरकारी सिस्टम को पारदर्शी बनाने, निवेश बढ़ाने के प्रयास करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हर काम निर्धारित समयसीमा में हो, ईज ऑफ बिजनेस व ईज ऑफ लिविंग के लिए प्राथमिकता से कार्य हो, विदेशी मुद्रा लाने के लिए निर्यात पर ध्यान दिया जाए, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट पर तेज गति से कार्य करें, कौशल विकास के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो, जेम पोर्टल का इस्तेमाल अधिकाधिक हो, एक जिला एक उत्पाद को लेकर काम करें, कच्चा माल, कृषि उत्पाद, निर्यात पर ध्यान दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत-रोजगार योजना पर ध्यान देकर कार्य करें, मेडिकल में हिन्दी पढ़ाई के लिए कार्ययोजना बनाएं, भू-अधिकार योजना के अंतर्गत प्लाट देने का अभियान शुरू कर दें, स्वस्थ बच्चा स्पर्धा करें।

● **कुमार राजेन्द्र**

नए साल में ताबड़तोड़ बैठकें

2022 में मप्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल में लगातार 5 दिन विभागों की समीक्षा करेंगे और टारगेट देंगे। मंत्रालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समीक्षा के लिए बनी कार्ययोजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी को सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्यिक कर, राजस्व, खेल एवं युवक कल्याण, परिवहन, वन और श्रम की समीक्षा करेंगे। उसके बाद 4 जनवरी को उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विधि एवं विधायी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सहकारिता, कृषि, मछुआ कल्याण, पशुपालन, ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, 5 जनवरी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय विकास एवं आवास, सामाजिक न्याय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, पर्यटन और संस्कृति विभाग, 6 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा 7 जनवरी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, खनिज साधन, पर्यावरण और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान सरकार का पूरा फोकस आत्मनिर्भर मप्र पर रहेगा।

अब विकास का बुधनी मॉडल

प्रज्ज्वल बुधनी बनाने यह विभाग करेंगे सहयोग

जानकारी के मुताबिक प्रज्ज्वल बुधनी के तहत मॉडल टाउन व आदर्श विधानसभा तैयार करने में नगरीय प्रशासन के अलावा, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, वन विभाग, आर्थिक सांख्यिकी, परिवहन, स्कूल शिक्षा, कुटीर व ग्राम उद्योग, वित्त विभाग, नर्मदा घाटी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष पीएचई, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, खनिज, पशु पालन, जनजाति गृह विभाग सहित अन्य विभागों को शामिल किया जाएगा जिससे कि निर्माण व विकास कार्य में कोई विभाग बाधक ना बने। इस संबंध में एसडीएम डीएस तोमर ने बताया कि प्रज्ज्वल बुधनी के तहत कई निर्माण व विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। कई कामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने का इंतजार है। नए साल में कई निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इन कामों के होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। बता दें कि पिछले कांग्रेस के शासनकाल में छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चाएं काफी होती रही लेकिन अब लोग छिंदवाड़ा मॉडल भूल जाएंगे क्योंकि बुधनी मॉडल उसे न सिर्फ टक्कर देगा बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर बनेगा। ज्ञात हो कि पंद्रह महीने की कमलनाथ सरकार में नाथ पर अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा के मॉडल को संपूर्ण मप्र में लागू करवाने की तैयारियां की गई थी। यही नहीं कमलनाथ ने अधिकांश विकास कार्य, मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाएं अपने विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा को ही दिए। यही वजह रही कि उनकी इस कार्यप्रणाली पर उनके अपने ही मंत्री-विधायकों ने अलग-अलग समय पर सवाल भी खड़े किए। हालांकि पंद्रह माह में ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा सरकार पुनः सत्ता पर काबिज हो गई।

प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र बुधनी अब देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर रोल मॉडल बनेगा। इसके लिए प्रदेश के आला अफसर कार्य योजना बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किए जा रहे हैं। बुधनी मॉडल धरातल पर उतरने के बाद उसी के आधार पर प्रदेश में विकास किया जाएगा। मप्र जिस तरह देशभर के लिए विकास का मॉडल बना हुआ है, उसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी को मप्र का विकास मॉडल बनाने जा रहे हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को टक्कर देने के लिए शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी को विकास का मॉडल बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में बुधनी में कई बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को टक्कर देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी के प्रज्ज्वल बुधनी मॉडल के विकास कार्यों का बजट पास किया जाएगा। 1 साल से प्रज्ज्वल बुधनी मॉडल के साथ तैयारी जोरशोर से की जा रही थी। अब बजट सत्र में प्रज्ज्वल बुधनी के प्रस्ताव पत्र को रखा जाएगा जिसको बजट में पास करने के लिए चर्चा की जाएगी। मप्र सरकार ने अगले साल के बजट को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। विधानसभा में बजट फरवरी माह में पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में वेतन मद में 3 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है लेकिन इस बजट सत्र में खास फोकस मुख्यमंत्री की बुधनी विधानसभा में रहेगा क्योंकि आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रज्ज्वल बुधनी है।

प्रज्ज्वल बुधनी के प्रोजेक्ट के तहत नसरुल्लागंज में 10 ट्रेड के लिए आईटीआई ग्लोबल स्किल पार्क एवं मॉडल कैरियर सेंटर के लिए भवन निर्माण किए जाने हेतु अनुपूरक बजट 2022-23 सम्मिलित किए जाएंगे। वहीं बुधनी में 50 बिस्तर का नया समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल नसरुल्लागंज में नवीन मेटरनिटी एवं मुख्यालय, नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, संबंध टिचिंग चिकित्सालय का निर्माण करने के लिए 2022-23 वित्तीय बजट में सम्मिलित किए जाएंगे। बुधनी शहरी, रेहटी शहरी, शाहंगज शहरी, नसरुल्लागंज शहरी में विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के सुंदरीकरण के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। जैत घाट, बांद्राभान घाट, छिपानेर घाट और नीलकंठ घाट के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किए जाने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। शिवराज ने कहा कि हर विभाग अपने बजट का समय पर उपयोग कर लें। इसके बाद जो विभाग पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, उनके बजट का पैसा दूसरे विभागों को दे दिया जाएगा।

प्रज्ज्वल बुधनी के तहत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र को देश की एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी व शाहगंज नगर को योजना के तहत विकास शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई पंचायतों का चयन किया गया है जिससे ग्रामीणों को भी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रज्ज्वल बुधनी के तहत मुख्यमंत्री ने बीते एक वर्ष के दौरान अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए राशि भी जारी की जा रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यमंत्री के लक्ष्य के तहत लगभग चारों नगरों के विकास में 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। योजना का कार्य पूर्ण होने पर गोपालपुर से लेकर बकतरा तक एक जैसा नजारा देखने को मिलेगा जिसके चलते पिछले दिनों निकायों द्वारा कई कार्यों के टेंडर भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। प्रज्ज्वल बुधनी योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 35 करोड़ रुपए के निर्माण नगरीय क्षेत्र में चल रहे हैं। जो कार्य नगर में चल रहे हैं उनमें सीसी सड़क व आरसीसी नाली, आश्रय स्थल, हॉकर्स कॉर्नर, वेंडर मार्केट, एमआरएफ सेंटर निर्माण, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, उत्कृष्ट विद्यालय में सीसी सड़क, सब्जी बाजार का सीसी आदि हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

मप्र में मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा इस तैयारी में सबसे आगे है। 2018 में मिली हार से सबक लेते हुए भाजपा ने संगठन को सक्रिय करने के लिए कई स्तरों पर प्लानिंग की है। इसी के तहत पार्टी बूथ पर सबसे अधिक फोकस कर रही है। बूथों को मजबूत करने के लिए अब विस्तारकों को सक्रिय किया जाएगा। वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी विस्तारक बनाया जाएगा।

बूथ को मजबूत करने में जुटी भाजपा

इन दिनों भाजपा का पूरा जोर संगठन और मतदाताओं में अपना प्रभाव बढ़ाने पर है। इसके लिए संगठन स्तर पर चिंतन व मनन के बाद नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह पूरी कवायद दो साल बाद होने वाले विधानसभा और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। इसके लिए अब संगठन विस्तारकों को बूथ स्तर तक उतारने की तैयारी कर चुकी है, तो वहीं असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने की भी मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके लिए संगठन द्वारा पूरी कार्ययोजना बना ली गई है। इसके लिए पार्टी के प्रति नए लोगों में रुझान पैदा करने के लिए चेन मार्केटिंग पैटर्न को भी लागू करने की योजना है। इसके माध्यम से संगठन विस्तार का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें बूथ स्तर तक की व्यूहरचना होगी। बूथ स्तर तक विस्तारक बनाएंगे, जो आगे और लोगों को जोड़कर नेटवर्क तैयार करेंगे। दरअसल, भाजपा के संगठन को मजबूत और उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। यही वजह है कि बीते कई दिनों में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मप्र में न केवल डेरा डाल चुके हैं, बल्कि कमजोर कड़ी को तलाशकर उस पर काम करने की नसीहत भी दे चुके हैं। इसके लिए उनके द्वारा नए सिरे से दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। अब प्रदेश संगठन इन निर्देशों के तहत ही आगे बढ़ रहा है।

प्रदेश संगठन के मुखिया वीडी शर्मा भी जल्द बूथ स्तर तक निकलने वाले हैं। इसके पीछे उनका मकसद मंडल और बूथ स्तर पर नए लोगों को जोड़कर संगठन का विस्तार करना है। पहले चरण में निचले स्तर तक सात-सात लोगों की टीम बनाई जाएगी, जिसके बाद यह लोग सभी आगे दो-दो लोगों को जोड़ेंगे। फिर आगे जोड़े गए लोग भी ऐसा ही आगे करते जाएंगे। इस चेन मार्केटिंग के फंडे को ही अब भाजपा लागू करने जा रही है। इसके अलावा संगठन द्वारा एक बूथ दस यूथ के प्लान पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही संगठन द्वारा अपने पुराने उन कार्यकर्ताओं का असंतोष दूर करने पर भी फोकस किया जाने वाला है जो अब पार्टी के लिए सक्रिय नहीं रह गए हैं। उनकी नाराजगी दूर कर उन्हें फिर से सक्रिय किए जाने की योजना भी बनाई गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से सतत् व बेहतर समन्वय और संवाद का फॉर्मूला लागू करने की योजना तैयार की गई है। दरअसल संगठन महामंत्री, सह-संगठन मंत्री प्रदेश में संपर्क-संवाद और समन्वय का काम करते रहते हैं, फिर भी कई कार्यकर्ता उन तक नहीं पहुंच पाते। यही नहीं कई कार्यकर्ताओं का भोपाल तक आना भी संभव नहीं होता। उन्हें अपने क्षेत्र के मंत्रियों-विधायकों के नहीं सुनने और मेल मुलाकात नहीं करने की शिकायतें भी रहती हैं। इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है, जिससे बचने के लिए ही नया फॉर्मूला लागू करने की कवायद की जा रही है।

भाजपा के रणनीतिकारों ने संगठन को मजबूत करने के लिए पहले चरण में संघ की तर्ज पर संगठन को ढालने की तैयारी कर ली है। इसके तहत प्रदेश को तीन भागों में विभाजित कर संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। अब संघ की ही तरह प्रदेश को मध्यभारत, महाकौशल और मालवा प्रांत में विभाजित किया जाएगा। इसके तहत संघ से भेजे गए तीन प्रचारक या विस्तारक बतौर संगठन मंत्री क्षेत्रीय स्तर पर काम करेंगे। इन **तीनों ही प्रांतों** के तहत आने वाले प्रत्येक संभाग स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। संगठन मंत्रियों की निगरानी में कोर ग्रुप स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुद्दों और समस्याओं का निराकरण करेंगे। जब भी प्रभारी या विभागीय मंत्री दौरा करेंगे तब समन्वय और संवाद का कार्य भी इनके जिम्मे रहेगा। इसके पीछे संगठन की मंशा जमीनी कार्यकर्ता, पार्टी और सरकार के बीच सेतु का काम करना है।

भाजपा का उन बूथों पर खासतौर पर फोकस है जिन पर बीते आम चुनाव में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा संगठन अजा-जजा वर्ग पर भी फोकस कर रहा है। इसके लिए बूथ मैपिंग कर काम शुरू किया गया है। पिछले चुनाव में आदिवासी वोटबैंक का भरोसा हासिल न करने के कारण भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। अब इसी हिसाब से विस्तार प्लान में भी व्यूह रचना हो रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

नहीं मिल पा रही सत्ता में भागीदारी

मप्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी नाराजगी की वजह सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने की वजह से है। पिछली सरकार में भी शिव सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं को सत्ता की भागीदारी से दूर रखा गया था, जिसकी वजह से चुनाव के समय कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ मेहनत नहीं की थी। चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को इसका फायदा मिला। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने रिक्त पड़े तमाम आयोगों और निगम मंडलों में अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया था। यही नहीं अन्य उन संस्थाओं में भी नियुक्तियां कर दी गई थीं, जिनमें राजनीतिक स्तर पर तैनाती की जाती है। इस बार भी करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में अब तक शिव सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।

मास्टर प्लान दूर की कौड़ी

पिछले मास्टर प्लान की 26 सड़कें नहीं बन पाईं

प्रदेश की राजधानी भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 2005 में आया था। इस मास्टर प्लान में तय की गई करीब 26 सड़कें आज तक नहीं बन पाईं। इन मास्टर प्लान की सड़कें अतिक्रमण और भू-अर्जन की वजह से अटकी हुई हैं। हालांकि इसे लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन ज्यादातर काम नहीं हो सका। बरखेड़ा से अवधपुरी को जोड़ने वाली एक सड़क पर एक स्कूल बाधा बना हुआ है। मास्टर प्लान में बावड़िया कला रेलवे क्रॉसिंग का आरओबी बन गया है। इसके अलावा अभी एक और आरओबी प्रस्तावित है। वहीं मिसरोद फेज-2 तक की तीन सड़कें नहीं बन पाईं। सिंगारचोरी रेलवे क्रॉसिंग से बैरसिया रोड 4-47 किलोमीटर तक की सड़क पर अवैध कॉलोनियां कट चुकी हैं। आशिमा मॉल से पारस एम्पायर तक एक किलोमीटर की सड़क नहीं बन सकी। औरा मॉल से शाहपुरा सी-सेक्टर की 1-56 किमी तक की सड़क पर प्लॉटिंग हो गई है। इसके अलावा कुछ निर्माण और भी हो चुके हैं।

मप्र की राजधानी के विकास की रूपरेखा बिना मास्टर प्लान ही तैयार हो रही है। 28 साल बाद भी मास्टर प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस बार करीब 9 साल से बन रहा भोपाल का मास्टर प्लान जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट में अब कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसकी संभावना कम है। क्योंकि इस बार भी मास्टर प्लान में कई ऐसी विसंगतियां हैं जिन्हें धरातल पर उतारना नामुमकिन है। भोपाल में पिछले 16 साल से मास्टर प्लान नहीं बना है। साल 2005 में जो मास्टर प्लान बना था, उसके अनुसार ही 2021 तक शहर का विकास हुआ।

पिछले साल नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने वर्ष 2031 के हिसाब से ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा था। इसमें डेढ़ साल में दो बार बदलाव हुए। इस बीच केंद्र ने अमृत योजना में शामिल सभी शहरों के मास्टर प्लान वर्ष 2035 के हिसाब से बनाने की गाइडलाइन दी। इस कारण एक बार फिर भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हाल ही में राज्य सरकार ने भोपाल को छोड़कर अन्य शहरों में वर्ष 2035 के हिसाब से मास्टर प्लान बनाने का फैसला लिया, जबकि भोपाल में प्रस्तावित 2031 के ड्राफ्ट को ही लागू करने का मन बना लिया है।

केंद्र की गाइडलाइन के बाद नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) ने 28 शहरों के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट लागू करने के बाद प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार अगले 14 साल तक सुनियोजित विकास के हिसाब से लागू होने जा रहे मास्टर प्लान में केवल लैंड यूज नहीं, बल्कि पाइपलाइन, सीवरेज, टेलीफोन लाइन और बैंक-एटीएम जैसी सुविधाओं का जिक्र रहेगा। अभी तक एक जैसे मास्टर प्लान लागू नहीं थे। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार आबादी व क्षेत्र के हिसाब से सुविधाओं का मानक निर्धारित होगा। इस बार सारे नए प्लान में अस्पताल, स्कूल, खेल मैदान, कॉलेज, पुलिस, थाना पार्किंग, सीवरेज, ड्रेनेज, पेयजल, टेलीफोन, सड़क के लिए मानक तय होंगे। गाइडलाइन भविष्य के शहरों का मास्टर प्लान जनगणना के हिसाब से तैयार करने की है। वर्ष 2031 में जनगणना होगी, इसलिए 2035 के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित हो चुका है, इसलिए अब इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। जनवरी तक मास्टर प्लान लागू कर देंगे। केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से अमृत योजना में शामिल अन्य बड़े-छोटे शहरों के मास्टर प्लान वर्ष 2035 के हिसाब से लागू किए जाएंगे।

करीब 16 वर्षों की मशक्कत के बाद पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान 5 मार्च को मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ था लेकिन सरकार बदलने और फिर कोरोना संक्रमण के चलते प्लान पर दावे-आपत्ति में देरी हुई। इसके चलते जुलाई में नए सिरे से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें 1731 आपत्तियां आईं। सुनवाई के आधार पर टीएंडसीपी ने अपनी रिपोर्ट के साथ ड्राफ्ट शासन को भेज दिया। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार दावे-आपत्तियां बुलाएगी। इसके बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस मामले को लेकर सिटीजन फोरम के पूर्व डीजी अरुण गुर्टू हाईकोर्ट भी गए हैं। इसे लेकर सुनवाई होना बाकी है। उनके मुताबिक बिना मास्टर प्लान के जरिए जिस तरह से विकास हो रहा है, उसकी वजह से भोपाल धीरे-धीरे स्लम की तरह विकसित हो रहा है। भोपाल में वीआईपी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से धीरे-धीरे लैंड यूज बदल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार मास्टर प्लान लाना ही नहीं चाहती है। यही वजह है कि इतने वर्षों में मास्टर प्लान नहीं लाया जा सका। पिछली कमलनाथ सरकार मास्टर प्लान का ड्राफ्ट लेकर आई थी लेकिन सत्ता बदलते ही फिर इस पर अड़ंगा लग गया। सरकार मास्टर प्लान के नाम पर लोगों को फूल बना रही है।

केंद्र के हिसाब से नए प्लान में हॉस्पिटल, स्कूल, स्पोर्ट्स, ग्राउंड, कॉलेज, पुलिस थाना, पार्किंग, सीवरेज, पेयजल, सड़क के लिए स्टैंडर्ड और योजना शामिल होना चाहिए। लेकिन भोपाल अभागा है जिसका अगले 10 साल का प्लान पुराने ढर्रे पर बना होगा। मास्टर प्लान को लेकर सरकारें कितनी संजीदा रही हैं इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि 1995 में भोपाल के मास्टर प्लान में 241 किमी सड़कें प्रस्तावित की गई थीं, लेकिन इनमें से सिर्फ 52 किलोमीटर सड़कें ही बन पाईं। नए मास्टर प्लान में 795 किलोमीटर सड़कें प्रस्तावित की गई हैं जिन्हें बनने में शायद एक सदी लग जाए। एक तरफ भोपाल में सीपीए को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दूसरी तरफ नया मास्टर प्लान लागू हो रहा है। विकास की रफ्तार इतनी धीमी है कि इस साल बजट में घोषित 264 करोड़ के चार आरओबी और एक फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हो सका है। होशंगाबाद रोड के समानांतर रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर बावड़िया कला के तरफ एक रोड बनाई जानी थी। यह सड़क पिछले एक दशक से प्रस्तावित है लेकिन आज तक इस सड़क का काम नहीं हो सका। आशिमा मॉल के सामने प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज भी कई साल से अपने निर्माण की राह देख रहा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

तालाब बदलेंगे गांव की तस्वीर

मप्र सरकार ने तालाबों के महत्व को समझते हुए उन्हें ग्रामीण विकास की धुरी बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार प्रदेशभर के गांवों में ऐसे पुराने तालाबों का पुनरुद्धार कर रही है, जो अनुपयोगी हो गए थे। इनमें मछली पालन और सिंघाडा उत्पादन जैसी आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सरकार का अनुमान है कि इस मॉडल से गांव में करीब 3000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था आकार लेगी। सरकार ने इसे 'पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान' नाम दिया है। सरकार इस योजना से बड़े राजनीतिक फायदे भी देख रही है।

मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गांवों के आर्थिक विकास के लिए यह योजना तैयार की है। राज्यभर में पुराने और अनुपयोगी हो चुके करीब 40,000 तालाबों की पहचान कर ली गई है। यह संख्या 50,000 तक पहुंचने का अनुमान है। पुनरुद्धार में प्रति तालाब पचास हजार से दो लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इनका काम मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा। योजना के ज्यादातर तालाबों की पहचान आदिवासी बहुल जिलों में की गई है। इसमें उमरिया, बड़वानी, शहडोल, बालाघाट और बैतूल प्रमुख हैं। उपयोग के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे तालाब हैं जो केवल सिंचाई के काम आएंगे। दूसरे में मछली पालन और तीसरे में सिंघाड़ा उत्पादन किया जाएगा। तालाबों का सबसे ज्यादा उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। अनुमान है कि इनसे करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ये ऐसे क्षेत्र होंगे जहां फिलहाल सिंचाई सुविधा नहीं है।

तालाबों का उपयोग तय करने और उनका संचालन सहित सारे अधिकार पंचायतों के पास होंगे। पंचायतों ने तालाबों की पहचान करने के साथ ही संचालन करने वाले समूह भी तय कर लिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि यह अभियान ग्राम स्वराज को नए सिरे से परिभाषित करेगा। अभियान की रूपरेखा बनाने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव कहते हैं, तालाब हमेशा गांव के विकास की धुरी रहे थे, हमने उस मॉडल को भुला दिया। तालाबों का नष्ट होना राष्ट्रीय क्षति है। हमारा प्रयास है कि उस पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। इसमें समुदाय के हितों के लिए गांव की पूंजी, ज्ञान और कौशल को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है।

उमराव तालाबों से गांव के विकास का एक सफल प्रयोग पहले कर चुके है। कलेक्टर रहते हुए उन्होंने देवास में खेत तालाब बनाने का अभियान शुरू किया था। इसमें स्वयं के खर्च पर किसान को तालाब बनाना होता था। उस समय देवास में ट्रेन से पानी की सप्लाई होती थी। आज वहां के किसान समृद्ध श्रेणी में आते हैं। वहां अब तक 20,000 से अधिक तालाब बन चुके हैं जिन पर किसानों ने स्वयं करीब 6000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इनसे तीन लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है। इस मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था।

सफल देवास मॉडल के आधार पर ही इस अभियान की रूपरेखा तय की गई। इसमें पुराने तालाबों को चुना गया और व्यक्ति के बजाय सामुदायिक विकास को धुरी बनाया गया। पुराने तालाब चुने जाने के पीछे उमाकांत उमराव कहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बनाए गए थे। अभियान के अंतर्गत कई जिलों में पुनरुद्धार का काम शुरू किया जा चुका है। उनका कहना है कि इस अभियान से आर्थिक विकास के साथ गांवों को जल संकट से भी मुक्ति मिल जाएगी। भूजल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे गांवों के कुएं भी जिंदा हो जाएंगे।

सरकार इसमें अपने लिए बड़ा राजनीतिक फायदा भी देख रही है, क्योंकि इसकी सफलता को चुनावों में भुनाया जा सकता है। गांवों में काम करने वाले स्वसहायता समूहों को ज्यादा से ज्यादा काम सीधे दिए जा रहे हैं। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान से पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान की रूपरेखा जिस तरह तय की गई है, यदि उसी रूप में अमल हुआ तो वह विधानसभा चुनावों में शिवराज सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा।

● **राजेश बोरकर**

जंगलों के आसपास बनाएंगे तालाब, फसलें भी बचेंगी

जंगलों में पानी के स्रोत कम या खत्म होने पर वन्य प्राणियों का जंगल से सटे गांवों-कस्बों में आना शुरू हो जाता है। इससे जहां ग्रामीणों की जान पर संकट होता है, वहीं शाकाहारी वन्य प्राणी उनकी फसलें भी चौपट कर देते हैं। यह समस्या अमूमन देश के हर राज्य में है, किंतु मप्र ने इसका हल निकालने के लिए एक प्रयोग करने की तैयारी की है। इसके तहत गांव से सटे जंगलों में वन्य प्राणियों के लिए तालाब, स्टापडैम बनवाए जाएंगे। इससे जहां जंगल में पानी मिलने से वन्य प्राणी जंगलों में ही रहेंगे, वहीं जल संरचनाओं के कारण उन क्षेत्रों का जल स्तर बेहतर होगा। जल संरचनाओं का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से होगा। वन विभाग स्थल चयन में सहयोग करेगा। आमतौर पर जंगलों से सटे गांवों में किसान वन्य प्राणियों द्वारा फसल को चौपट करने से परेशान रहते हैं। इसके लिए वे बागड़ भी लगाते हैं पर यह कदम अधिक कारगर साबित नहीं होता है। विधानसभा में यह वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को चौपट करने का विषय उठता रहता है। दरअसल, वन्य प्राणी पानी की तलाश में भटककर खेतों में आ जाते हैं। इससे फसल को तो नुकसान पहुंचता ही है ग्रामीणों की जान पर संकट भी होता है। वन विभाग वन क्षेत्रों में छोटे तालाब आदि का निर्माण भी कराता है पर इतनी संख्या सीमित होती है।

आखिरकार चुनावी वर्ष से करीब दो साल पहले भाजपा ने मैदानी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्ति दे दी है। इस नियुक्ति में क्षेत्रीय के साथ ही जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा ने सिंधिया के साथ पार्टी में आए नेताओं को भी महत्व दिया है। इस बार जिन नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्ति दी गई है, उनमें संघ और सिंधिया समर्थकों का दबदबा है। यह इस बात का संकेत है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कितनी संवेदनशील है।

संघ-सिंधिया का पलड़ा भारी

सियासी सबक का असर

इन थोकबंद नियुक्तियों में सियासी सबक का भी असर दिखता है। वजह ये कि 2018 में भाजपा चुनाव हार गई थी। तब, अनेक निगम-मंडल के पद खाली पड़े थे। इससे पहले दो दशक में कभी भी सारे निगम-मंडलों के पद नहीं भरे गए। न कभी इस प्रकार थोकबंद नियुक्तियां की गईं। इसमें भाजपा सरकार के साथ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी कभी पूरे पदों को भरने में रूचि नहीं ली। इसलिए इस बार शिवराज सरकार ने सियासी सबक को ध्यान में रखकर थोकबंद नियुक्तियां की हैं। सिंधिया समर्थक नेताओं में चुनाव हारने वालों को पुनर्वास दिया गया है। इनमें तीनों तत्कालीन मंत्री सहित अन्य विधायक शामिल हैं। सिंधिया समर्थक इमरती देवी को लघु उद्योग निगम और गिर्राज दंडोतिया को ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। इनके साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए एंदल सिंह कंषाना को भी मप्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष का पद मिला है। ये तीनों ही मंत्री रहते हुए उपचुनाव हार गए थे। वहीं मुन्नालाल गोयल, मजू दादू, रणवीर जाटव, रघुराज कंषाना, जसवंत जाटव आदि को भी हार के बाद पुनर्वास के तौर पर निगम-मंडल दिए गए हैं। इनके अलावा विनोद गोटिया को पर्यटन निगम अध्यक्ष बनाया है। इन्हें राज्यसभा चुनाव हारने के बाद अब संगठन की ओर से मौका दिया गया है।

विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक दो साल पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश की सियासी नब्ज को थामने राज्य के निगम-मंडलों में थोकबंद नियुक्तियां कीं। इन नियुक्तियों के जरिए सारे सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। मुख्य रूप से एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेताओं को नवाजा गया है, तो दूसरी ओर संघ के नेताओं को भी सिर-माथे पर रखकर जगह दी गई। साथ ही उपचुनाव के समय किए वादों को भी पूरा किया गया है। इन नियुक्तियों में कई कारण हावी रहे हैं।

संघ के जिन संभागीय संगठन मंत्रियों को कुछ समय पूर्व हटाया गया था, उनमें चार नेताओं को निगम मंडलों में जगह दी गई है। इसके अलावा उपचुनाव के समय किए वादों को पूरा करने के लिहाज से भी निगम-मंडल में पुनर्वास किया गया है। इनमें कुछ को चुनाव न लड़ने तो कुछ को चुनाव के समय साथ देने का ईनाम मिला है। इसमें सावन सोनकर को उपचुनाव के समय वादे के तहत अध्यक्ष, मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बनाया है। वहीं संघ के जरिए जयपाल चावड़ा इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं।

एक साल 9 महीने इंतजार के बाद शिवराज सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां हो गई हैं। सरकार ने निगम-मंडलों के 16 अध्यक्ष और 9 उपाध्यक्षों की सूची गत दिनों पहले जारी कर दी। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों को जगह मिली है। उनकी कट्टर समर्थक इमरती देवी डबरा से विधानसभा उपचुनाव हारी थीं। इमरती को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे साफ है कि सरकार में सिंधिया का दबदबा कायम है। यही वजह है कि इमरती देवी के अलावा गिर्राज दंडोतिया, जसवंत जाटव, मुन्नालाल गोयल और रघुराज कंषाना को भी निगम अध्यक्ष बनाया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोटे से 6 नेताओं को सरकार में राजनीतिक पद मिले हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले एंदल सिंह कंषाना व रणवीर जाटव भी उपचुनाव हार गए थे, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें सरकार में जगह दी गई है। इसी तरह, संघ की पृष्ठभूमि से आए आशुतोष तिवारी भी शिवराज कोटे से हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं।

भाजपा के एक नेता ने बताया कि आशुतोष तिवारी को भोपाल और ग्वालियर संभाग का संगठन मंत्री रहते हुए सत्ता-संगठन में बेहतर तालमेल बनाने के ईनाम में यह पद मिला है। इसके अलावा, नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद वे उपचुनाव जीतीं। इस दौरान पूर्व विधायक मंजू दादू को सत्ता या संगठन में एडजस्ट करने का आश्वासन दिया गया था, जिसे अब पूरा किया गया है। उपचुनाव के समय नाराज मंजू दादू के निर्दलीय लड़ने की अफवाह भी थी। शिवराज के समर्थक राजकुमार कुशवाहा को बीज निगम के उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है।

सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उनके दो समर्थकों को पद देकर खुश किया है। शैलेंद्र शर्मा को मप्र कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि, पार्टी के एक नेता के मुताबिक शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से भी सिफारिश की गई थी। बोर्ड में उमा भारती के कट्टर समर्थक नरेंद्र बिरथरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी विनोद

गोटिया को मप्र पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जेपी नड्डा के करीबी तपन भौमिक को शिवराज सरकार ने इस निगम की कमान सौंपी थी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले भाजपा के 3 संभागीय संगठन मंत्रियों जितेंद्र लिटोरिया, शैलेंद्र बरुआ और आशुतोष तिवारी को सरकार में पद देने के लिए चार महीने पहले कोलार डैम में हुई सत्ता-संगठन की संयुक्त बैठक में निर्णय हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ, जब भाजपा के जिलों में तैनात संगठन मंत्रियों को पहले हटाया गया और अब उन्हें सरकार में जगह दी गई है।

प्रदेश में जो नियुक्तियां की गई, उनमें मप्र लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष इमरती देवी को बनाया गया है। इनके अलावा मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, मप्र ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष गिर्राज दंडोतिया, संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष रणवीर जाटव, मप्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष एंदल सिंह कंषाना, मप्र पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष रघुराज कंषाना, विनोद गोटिया को मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, मप्र पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र बरुआ, राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष सावन सोनकर, निर्मला बारेला को मप्र अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त, अमिता चपरा को मप्र महिला वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष, जयपाल चावड़ा को इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, आशुतोष तिवारी को मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल का अध्यक्ष, मप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जीतेंद्र लटोरिया, मप्र कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है।

वहीं पर्यटन विकास निगम का उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष रमेश खटीक, राजेंद्र सिंह मोकलपुर को मप्र खनिज विकास निगम का उपाध्यक्ष, मंजू दादू को मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उपाध्यक्ष, अजय यादव को मप्र पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का उपाध्यक्ष, मप्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का उपाध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा, मप्र कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे, मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और मप्र पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष प्रहलाद भारती को बनाया गया है। पिछले साल मार्च में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद से ही कोरोनाकाल चल रहा था। इस बीच, कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सरकार बनाने में मदद करने वाले ऐसे नेताओं की फजीहत हो गई थी, जो उपचुनाव में सफल नहीं हो सके थे। इनके पुनर्वास को लेकर सुगबुगाहट काफी दिन से चल रही थी। अब जाकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इन नेताओं पर ध्यान दिया है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

11 प्रतिशत वोट बढ़ाने का टारगेट

मिशन 2023 के लिए भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 51 प्रतिशत वोट बैंक के लक्ष्य के बाद अब राज्यवार विभिन्न चरणों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न आयोजनों के माध्यम से लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए भी कहा गया है। भोपाल में हुई बैठक में संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा जिला स्तर पर बनाई गई प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। बैठक में राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिवप्रकाश ने सभी से बात की। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कितनों को मिल पा रहा है, इस संबंध में जानकारी रखें और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का फायदा भी दिलाया जाए। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महामंत्री सुहास भगत ने भी संबोधित किया। सभी से कहा गया कि जिलों की कार्यकारिणी तकनीकी रूप से अपडेट हो इसका भी ध्यान रखा जाए। बैठक में सभी जिला समितियों को 11 प्रतिशत वोट बैंक बनाने का लक्ष्य दिया गया है। पहले चरण में बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से 11 प्रतिशत वोट बैंक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। चरणबद्ध चलने वाले इन कार्यक्रमों में आजीवन सहयोग निधि अभियान और अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी भी पदाधिकारियों को दी गई।

सत्ता-संगठन की नसीहत, बूथ स्तर तक जाओ, जनता से कनेक्ट रहो

भाजपा विधायकों को सत्ता-संगठन ने नसीहतों के डोज दिए। इसमें भाजपा विधायकों को लगातार जनता के बीच रहने और चुनावी मोड में काम करने के लिए कहा गया। विधायकों को साफ कहा गया कि अब 100 घंटे या 10 दिन क्षेत्र में रहो। बूथ विस्तार योजना के तहत सभी विधायकों को क्षेत्र दिए जाएंगे, उनमें बूथ स्तर तक जाना होगा। गांव में रात बिताने से लेकर लगातार प्रवास के लिए जुटने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने विधायकों को आगे की कार्ययोजना बताई। मुख्यमंत्री निवास पर हुई विधायक दल की बैठक में विधायकों को साफ कहा गया कि विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद अब फील्ड में पार्टी का पक्ष रखें। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरी स्थिति जनता को बताएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण पर उठाए अब तक के कदम और कानूनी पहलुओं को समझाया। यह भी बताया कि सदन में पारित संकल्प को भी जनता को समझाएं। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप हम सभी समाज और देश को बदलने के काम में प्रभावी भूमिका निभाएं।

मप्र में नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू होगा। इसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) से अब बड़े काम कराए जाएंगे। अभी तक पीआईयू मेंटेनेंस का काम करता था, लेकिन अब यह कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट आदि का निर्माण करेगा। अभी तक पीआईयू के तहत दो-ढाई हजार करोड़ का काम होता था, जो अब 10 हजार करोड़ का निर्धारित किया गया है। इससे प्रदेश में विकास की नई लहर आएगी।

पीआईयू भी निर्माण करेगा

मप्र में सरकार की मंशानुसार तेजी से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसको देखते हुए लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कवायद शुरू की है। इसके तहत अब मप्र बीडीसी भी बिल्डिंग निर्माण कार्य देखेगा। इसके लिए उसे क्रियान्वयन एजेंसी बनाया है। सड़कों के निर्माण कार्य व मेंटेनेंस के साथ ही उसे बिल्डिंग निर्माण दिए गए हैं। बिल्डिंग निर्माण कार्य देखने वाले पीआईयू भी बिल्डिंग निर्माण करते रहेंगे। पीआईयू और एमपी बीडीसी दोनों के क्षेत्र तय होंगे। इसमें यह तय होगा कि कितनी राशि तक के निर्माण कार्य पीआईयू कर सकेगा और कितनी राशि तक के निर्माण कार्य एमपी बीडीसी देखेगा। सरकारी बिल्डिंग के निर्माण के लिए गत दिनों एमपी बीडीसी यानी एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है।

नई सरकारी कंपनी के क्रियाशील होने तक एमपीआरडीसी को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ स्वीकृत पदों पर नियुक्ति व प्रतिनियुक्ति तथा संविदा एवं सेवा प्रदाता के रूप में चयन किया जाएगा। पीआईयू भी सरकारी बिल्डिंग निर्माण देखता रहेगा। उसे कार्य का कुछ प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। एमपीआरडीसी के संभागीय महाप्रबंधक एसके मनवानी का कहना है सरकारी बिल्डिंग के लिए एमपी बीडीसी के गठन की स्वीकृति शासन स्तर पर हुई है। कुछ दिनों में पूरा आदेश आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कितनी राशि तक के निर्माण एमपी बीडीसी देखेगा और कितनी राशि के पीआईयू।

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि मुख्यमंत्री ने विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य तेज करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) का गठन वर्ष 2010 में किया था। इससे शासकीय भवनों के निर्माण का कार्य मितव्ययी तरीके से और समय सीमा में होने लगा है। यह पिछले डेढ़ दशक का क्रांतिकारी परिवर्तन है। भार्गव ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री इसकी कल्पना नहीं करते तो आज शिक्षा जगत में भवनों की उपलब्धता की यह आदर्श स्थिति निर्मित हो ही नहीं सकती थी।

जानकारी के अनुसार बीडीसी में अधिकारी-कर्मचारी संविदा पर रखे जाएंगे और यह कंपनी केवल हजार से दो हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के ही काम करेगी। यही नहीं प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए टेंडर निकाले हैं, जो आगामी दिनों में मप्र में काम करेंगे। इनमें देश की बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। बताया जाता है कि सरकार की मंशा है कि ऐसा करने से अनावश्यक रूप से होने वाले खर्च रुकेंगे। ये कंपनियां सिवनी, छतरपुर, मंदसौर, राजगढ़, नीमच सहित प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगी। वर्तमान समय में इन निर्माणों पर जो लागत लगती है, उससे 20 प्रतिशत कम दर पर बड़ी कंपनियां मप्र में भवनों का निर्माण करेंगी।

दरअसल, अभी तक प्रदेश में जो निर्माण कार्य हो रहे थे, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। इसको देखते हुए मप्र सरकार ने जहां एक तरफ बीडीसी जैसी कंपनी का निर्माण किया है, वहीं कई अन्य बड़े निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। लोक निर्माण विभाग के सूत्रों का कहना है कि इससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता तो आएगी ही, साथ ही कम दर पर कम समय में बड़े-बड़े भवन निर्मित हो जाएंगे। इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और आत्मनिर्भर मप्र का सपना साकार होगा।

● **विकास दुबे**

कर्मचारियों को अब बड़े मकानों की मिलेगी सौगात

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। अब उन्हें बड़े मकानों की सौगात मिलेगी। कर्मचारियों के मकान का एरिया 40 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा, जबकि अधिकारियों के मकानों में 14 से 20 फीसदी एरिया में वृद्धि होगी। लोक निर्माण विभाग ने अनुमति के लिए प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों में सबसे निचला तबका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का होता है। इस तबके के कर्मचारियों को अभी तक बनने वाले मकान का एरिया करीब 350 वर्ग फीट होता है। ऐसे मकानों में छोटे-छोटे एक-एक कमरे, छोटा सा किचन व कामन लेटबाथ होते हैं। अब प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के बनने वाले मकानों के एरिया में चालीस फीसदी की वृद्धि कर रही है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मकान का एरिया अब करीब 500 वर्ग फीट रहेगा, जबकि अधिकारियों के मकान का वर्तमान में क्षेत्रफल 2120 वर्ग फीट है। अधिकारियों के मकान का क्षेत्रफल 19 फीसदी बढ़ाते हुए 2530 वर्ग फीट किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्रफल में सर्वेंट क्वाटर्स, गैरेज एवं बरांदा का क्षेत्रफल शामिल नहीं है। वर्ष 2016 में स्वीकृत प्लान के अनुसार बी एवं सी टाईप क्वाटर्स में आफिस रूम दिए जाने की अनुशंसा की गई है। सी टाईप से ई टाइप तक के बंगले में दो सर्वेंट क्वार्टर दिए जाने की अनुशंसा की गई है।

शिप्रा को उद्धार का इंतजार

मोक्षदायिनी क्षिप्रा को प्रदूषण से मोक्ष का इंतजार है। यह इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा। इसका कारण क्षिप्रा को स्वच्छ रखने के लिए उठाए गए कदमों का कामयाब नहीं होना। बीते सालों में क्षिप्रा को स्वच्छ व प्रवाहमान बनाने के लिए करोड़ों रुपए के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। अब एक बार फिर से क्षिप्रा को प्रदूषण से मुक्ति की कवायद शुरू हुई लेकिन देखना है कि यह कितनी सफल होगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि पिछले 20 सालों में जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए क्षिप्रा को स्वच्छ रखने के लिए पानी की तरह बहाए गए हैं...उसका क्या होगा।

सिंहस्थ 2016 में करीब एक अरब रुपए खर्च कर खान डायवर्सन योजना बनाई गई। इसमें पाइप लाइन के माध्यम से खान का गंदा पानी राघोपिपलिया से कालियादेह पैलेस के आगे निकाला जाना है। योजना से उम्मीद थी कि क्षिप्रा का जल अब साफ होगा और श्रद्धालु आचमन भी कर सकेंगे, लेकिन यह योजना भी कारगर साबित नहीं हुई। यह योजना सिर्फ 5 क्यूमेक्स पानी को डायवर्ट करने के लिए बनी थी पर वर्तमान में खान में इससे दोगुना पानी आ रहा है। जबकि योजना बनाते वक्त बताया गया था कि जून से सितंबर की अवधि में बारिश के कारण खान का गंदा पानी क्षिप्रा में मिलेगा। वर्तमान खान नदी के जलस्तर बढ़ोतरी होने से राघोपिपल्या पर बने स्टॉपडैम से पानी ओवरफ्लो होकर त्रिवेणी पर क्षिप्रा में मिल रहा है।

शहर का सीवरेज वाटर को क्षिप्रा में मिलने से रोकने नदी संरक्षण योजना बनी थी। इसमें शहर के 11 नालों के पानी को ट्रीटमेंट कर क्षिप्रा में छोड़ा जाना था। इसके लिए तीन जगह सीवरेज पानी को ट्रिट करने के बाद ही नदी में छोड़ा जाना था। बताया जा रहा है इस योजना के संचालन के लिए नगर निगम को राशि नहीं मिल रही। इससे यह योजना कारगर नहीं हो पाई। इसके अलावा रुद्रसागर में जमा गंदा पानी रामघाट पर पहुंचने से रोकने के लिए भी चार करोड़ की योजना बनाई गई थी। दूषित पानी को रामघाट से आगे छोड़ा जाता है।

क्षिप्रा को प्रवाहमान और स्वच्छ बनाए रखने के लिए 432 करोड़ रुपए से नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना बनाई गई। नदी में नर्मदा जल के अपव्यय के चलते दोबारा से करोड़ों रुपए खर्च कर पाइप लाइन डाली गई। त्रिवेणी के यहां पर पाइप लाइन के माध्मय से क्षिप्रा में नर्मदा जल डाला जा रहा है। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना से उम्मीद थी कि इससे नदी में न केवल भरपूर पानी रहेगा बल्कि स्वच्छ पानी से श्रद्धालु आचमन भी कर सकेंगे। खान नदी के प्रदूषित पानी मिलने से यह योजना कामयाब नहीं हो पा रही है।

इन योजना पर नहीं हुआ काम

त्रिवेणी संगम पर कच्चा स्टाप डैम की जगह पक्का स्टॉप डैम बनाया जाना। जलसंसाधन विभाग ने तैयार प्रस्ताव किया था। इसमें 5 से 7 मीटर ऊंचाई तथा 80 मीटर लंबा स्टाप डैम बनाने का प्रस्ताव था। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टाप डैम की कार्ययोजना को मंजूरी नहीं मिली। हालांकि इस स्टॉप डैम को राघोपिपलिया के यहां बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। खान नदी के पानी को नहर से निकालने के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई है। करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट को भी संभागायुक्त के माध्यम से शासन को भेजा गया है। लेकिन इस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्षिप्रा नदी पर सांवराखेड़ी डैम बनाने की योजना आकार नहीं ले रही है। जलसंसाधन विभाग ने डैम बनाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा है। अगर क्षिप्रा नदी पर डैम बन जाता है तो इससे साफ पानी के साथ क्षिप्रा स्वच्छ होने के साथ प्रवाहमान भी बनी रहेगी। जानकारों के अनुसार क्षिप्रा के प्रमुख घाट के किनारों पर अगर बड़े बोरवेल कर दिए जाएं तो क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाया जा सकता है। पर्व स्नान के हफ्ते भर पहले बोरवेल से पानी डालकर दूषित पानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जानकार इसे स्थायी समाधान नहीं मान रहे हैं।

खान नदी के शुद्धिकरण के लिए इंदौर नगर निगम ने अमृत परियोजना, जेएनएनयूआरएम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नदी किनारे बनाए हैं। साथ ही नदी में मिलने वाले सीवरेज के गंदे पानी को भी नगर निगम ने प्राइमरी लाइनों के जरिए एसटीपी तक ले जाकर उसे साफ किया जा रहा है। यही साफ पानी दोबारा खान नदी में छोड़ा जाता है। बावजूद रास्ते में कई जगह उद्योग व नालों को पानी खान नदी में मिलने से यह प्रदूषित हो रही है। हाल ही में प्रदूषित पानी रोकने इंदौर जिला प्रशासन ने कमेटी भी बनाई है लेकिन इसका क्या असर होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

क्षिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर संतों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जलसंसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास तथा नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव ने खान नदी का निरीक्षण किया था। इसमें खान को क्षिप्रा में मिलने से रोकने के लिए तीन विकल्प रखे गए हैं, जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है। खान के पानी को नहर के माध्यम से क्षिप्रा नदी के मुख्य घाट से बायपास करके कालियादेह महल निकाला जाए। इससे नदी का पानी पूरी तरह से डायवर्ट होगा। किसानों को भी पानी मिल सकेगा। हालांकि योजना पर फिर से करोड़ों खर्च होंगे।

खान के प्रदूषित पानी को सांवेर से पहले रोकने के लिए स्टॉप डैम बनाया जाए। इससे खान का पानी उज्जैन आने से पहले रुक जाएगा। यहां रुके पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा। खान नदी को स्वच्छ रखने के लिए इसमें सीवरेज के पानी का ट्रीट कर ही नदी में डाला जाएगा। इससे उज्जैन तक खान का स्वच्छ पानी ही पहुंचेगा। ऐसा होने से नहर या स्टॉपडैम बनाने की जरूरत नहीं होगी। स्वच्छ पानी होने से क्षिप्रा में मिलने से भी परेशानी नहीं आएगी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

सफेद हाथी बने सार्वजनिक उपक्रम

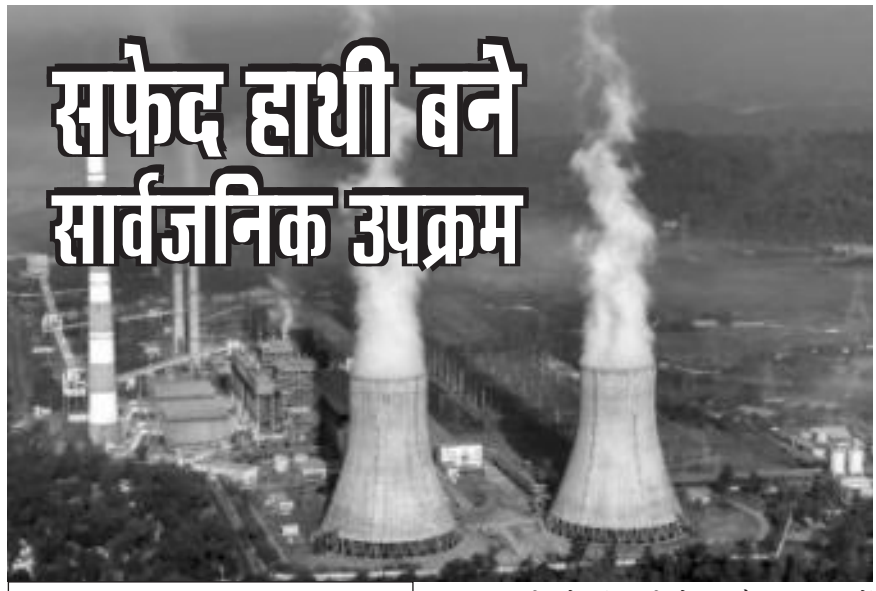

प्रदेश में अफसरशाही के मायाजाल को कैग रिपोर्ट ने नकार दिया है। कैग रिपोर्ट्स के मुताबिक मप्र सरकार के 71 सार्वजनिक उपक्रम यानी सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों में 54 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा 2019 की स्थिति में है। इसमें भी मुख्यत: 2016-17 से दिसंबर 2019 तक का आंकलन किया गया है। दिलचस्प ये कि इन 71 सार्वजनिक उपक्रमों में 11 बिजली सेक्टर के हैं। इनमें तीन बिजली कंपनियों का घाटा ही करीब 7158 करोड़ का है। इन तीन बिजली कंपनियों का घाटा इसी बिजली सेक्टर की उन कंपनियों को भी डूबा रहा है, जो फायदे में है। इसके पीछे अफसरशाही का कुप्रंधन, गलत नीतियां और लापरवाही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश कैग रिपोर्ट्स से घाटे की इस रोशनी और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति उजागर हुई है।

सबसे पहले बिजली सेक्टर के 11 सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें तो तीन कंपनियां घाटे में हैं। इनमें तीनों बिजली वितरण कंपनियां शामिल हैं। यानी कैग रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियां 2016 से दिसंबर 2019 की स्थिति में 7158.48 करोड़ रुपए के घाटे में है। वहीं पॉवर जनरेटिंग कंपनी, पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी और बाणसागर थर्मल पॉवर कंपनी उलटे 216 करोड़ रुपए के लाभ में हैं। वहीं दादा धूनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड कंपनी महज 3 करोड़ के मामूली नुकसान में हैं। जबकि, चार कंपनियां ऊर्जा विकास निगम, पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, शाहपुरा थर्मल पॉवर और सिंगाजी पॉवर लिमिटेड कंपनी न घाटे में है और न फायदे में हैं। वहीं यदि इन सभी बिजली के 11 सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें, तो इन्होंने कुल 77 हजार करोड़ का कारोबार किया था।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का कारोबार 77 हजार 617.28 करोड़ रुपए था, जो मध्य क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 9.59 प्रतिशत था। इन उपक्रमों में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य 87 हजार 154.15 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016-17 में एक हजार 405.93 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 में छह हजार 944.74 करोड़ का नुकसान उठाया गया। इस साल 11 में से तीन उपक्रम लाभ में रहे, जबकि विद्युत वितरण कंपनियां सात हजार 158.48 करोड़ के घाटे में चली गईं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 452.32 करोड़ रुपए के 155 ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए 19 ठेके किए। इसमें कंपनी किफायती खरीद नहीं कर सकी। पिछली खरीद की तुलना में समान क्षमता के ट्रांसफार्मर उच्च मूल्य पर खरीदे गए। कंपनी दूसरे बोलीदार से पहली बोली पर की गई खरीद की दर को प्रतिबंधित करने में भी विफल रही।

मप्र विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कई विभागों की भर्राशाही और भ्रष्टाचार सामने आया है। रिपोर्ट में सार्वजनिक उपक्रमों को सफेद हाथी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में बिजली सेक्टर के 11 सार्वजनिक उपक्रमों में से 3 कंपनियां घाटे में चल रही हैं।

बिजली दर बढ़ाने की तैयारी

मप्र में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है। बिजली कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.71 प्रतिशत दर बढ़ाने को लेकर दायर याचिका को मप्र राज्य नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर आम बिजली उपभोक्ताओं के दावे-आपत्तियों को सुना जाएगा। इसके बाद नियामक आयोग अंतिम निर्णय करेगा। कंपनियों की डिमांड के मुताबिक दरें बढ़ाई गईं तो बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। प्रति यूनिट 58 पैसे तक बढ़ सकते हैं। बढ़े हुए बिजली बिल पर 12 प्रतिशत सर्विस टैक्स भी लगेगा। यह तीसरा मौका होगा जब प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी। प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (पूर्व, मध्य और पश्चिम) की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है। इसमें सबसे अधिक 19 हजार 428 करोड़ रुपए पश्चिम क्षेत्र कंपनी खर्च करेगी। वहीं, सबसे कम खर्च पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी करेगी। जबकि इस कंपनी के कार्यक्षेत्र में 20 जिले शामिल हैं।

दूसरी ओर बिजली सेक्टर के 11 उपक्रमों के अलावा बाकी 60 सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें, तो वे भी घाटों की घटा में घिरे हैं। इनमें से अधिकर सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियां बेहद खराब हालत में हैं। इनमें निष्क्रिय कंपनियां भी शामिल हैं। इसी कारण इनका घाटा 54 हजार करोड़ पार कर गया है। इन 60 उपक्रमों में 16 उपक्रप पूरी तरह निष्क्रिय हैं। यानी सरकार इनको बंद करने का फैसला कर चुकी है अथवा यह कागजों पर ठप पड़े हैं। वहीं 44 कार्यशील उपक्रम है। इनमें से नौ को हानि हुई हैं। वहीं लाभ में रहने वाले उपक्रमों में स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिकस कारपोरेशन और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन शामिल हैं। औद्योगिक विकास निगम में भूमि आवंटन में हानि दर्शाई गई हैं। वहीं अन्य 31 सार्वजनिक उपक्रमों को जीडीपी में अकाउंटेबल माना गया है। इनमें से भी कुछ सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के दौरान मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी वसूली में पिछड़ गईं। असर यह हुआ कि नवंबर 2019 तक दोनों कंपनियों का उपभोक्ताओं पर बकाया दो हजार 619 करोड़ 96 लाख रुपए हो गया। ऐसा सरकारी विभागों से सामंजस्य बनाने में विफलता और बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं से संपर्क नहीं करने का परिणाम है। हालांकि, इस अवधि में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति में सुधार आया। उसकी संग्रहण दक्षता 86.25 से बढ़कर 87.43 प्रतिशत हुई। मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी के निर्माण में ठेकेदारों को जुर्माना लगाए बगैर कार्य की समयसीमा बढ़ाने की अनुमति दे दी।

● **अरविंद नारद**

मप्र सहित आधा दर्जन से अधिक राज्यों में नक्सली गतिविधियां दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। ऐसे में राज्यों ने संयुक्त रुप से नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरु कर दिया है। इससे नक्सली जहां के तहां छिपकर बैठ गए हैं।

नक्सलियों पर नकेल

जंगल के रास्ते गांवों में प्रवेश करने वाले नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। तीन राज्यों की पुलिस नक्सली उन्मूलन के लिए साझा ऑपरेशन चला रही है। मप्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी समन्वय स्थापित कर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताकि नक्सली जिले में प्रवेश न कर सकें। बालाघाट जिले में नक्सली संगठन की कमान संभाल रहे लीडर मिलिंद तेलतुमड़े की महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली में एनकाउंटर में मौत हो गई है। जिसके कारण बालाघाट जिले में नक्सली संगठन पहले की अपेक्षा थोड़ा कमजोर हुआ है। अपने कमजोर हुए संगठन और ग्रामीणों में ढीली हुई पकड़ को मजबूत करने नक्सली बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं।

हालांकि, पुलिस लगातार नक्सलियों पर नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार जिले में नक्सली लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों ने बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी में दो ग्रामीणों की मुखबिरी के शक में हत्याकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। इधर, नक्सलियों की समूल नष्ट करने के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव और बालाघाट जिले की पुलिस द्वारा साझा ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले की नक्सल उन्मूलन में लगी पुलिस और बालाघाट पुलिस द्वारा भी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

जिले में एक सैकड़ा से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी बनी हुई है। पुलिस भी नक्सलियों की मौजूदगी से इनकार नहीं कर रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली की घटना के बाद से नक्सलियों ने जिले में पनाह लेना शुरू कर दिया है। हालांकि, पुलिस ने नक्सलियों के आवागमन के रास्ते, जंगल और सीमावर्ती क्षेत्रों में नजर लगाए हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये नक्सली अन्य राज्यों से यहां पहुंचे हैं। जिले में पहुंचे ये नक्सली अपनी पैठ बढ़ाने के साथ-साथ सक्रियता भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

नक्सली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के जंगलों से जिले में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा, कबीरधाम से कान्हा नेशनल पार्क और दक्षिण बैहर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य से लांजी, देवरबेली चौकी क्षेत्र से भी जिले में प्रवेश करते हैं। जिसके बाद ये नक्सली जिले के बिठली, सोनगुड्डा, डाबरी, सालेटेकरी, चौरिया, चिलौरा, चिलकोना, राशिमेटा, दड़कसा, डाबरी, पितकोना, कोद्दापार, कोरका, बोंदारी, अडोरी, नवी, जगला, जालदा, हर्राडीह, खमारडीह, सायर संदुका, टेमनी, गढ़ी सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी सक्रिय हो जाते हैं।

बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी कहते हैं कि बालाघाट जिले में एक सैकड़ा से अधिक नक्सलियों के होने की संभावना है। हालांकि, मप्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य की नक्सली उन्मूलन में लगी पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन किया जाता है। ताकि नक्सलियों को प्रवेश से रोका जा सके। महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली में नक्सली लीडर मिलिंद की मौत के बाद जिले के नक्सली संगठन में इसका असर पड़ा है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

नशे का काला कारोबार खड़ा कर रहे नक्सली

मप्र सहित नक्सल प्रभावित राज्यों में तस्करों ने नशे के कारोबार का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन तस्करों को नक्सलियों का संरक्षण प्राप्त है। मप्र के कई जिलों में लंबे समय से मादक पदार्थो की खेती की जा रही है। अफीम की खेती करने वाले तस्कर पड़ोसी राज्यों से लेकर दूसरे देशों तक डोडा, अफीम और ब्राउन शुगर का काला करोबार कर रहे हैं। इसका खुलासा अभी हाल ही में पकड़ाए तस्करों की जांच-पड़ताल में हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ साल से मप्र तस्करी का हब बन गया है। प्रदेश के रास्ते बड़ी मात्रा में गांजा, डोडा, अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। मप्र पुलिस की सतर्कता से पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी मात्रा में तस्कर से गांजा, डोडा, अफीम और ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। जिसमें यह बात सामने आई है कि नशे के ये सामान ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मप्र के रास्ते तस्कर नक्सलियों द्वारा पैदा किए गए गांजे और अफीम दूसरे राज्यों में पहुंचाते हैं। प्रदेश में हर साल अरबों रुपए का नशे का कारोबार होता है। कई बार पुलिस छापेमारी कर अफीम, डोडा व ब्राउन शुगर जब्त करती है, लेकिन नशे के इस काले कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रही है। अरबों रुपए के इस काले कारोबार से नक्सलियों और आतंकवादियों की फंडिंग हो रही है, जिससे वह हथियार खरीदकर समाज में अशांति और दहशत फैलाते हैं। युवाओं का नशे के दलदल में फंसकर अपना भविष्य चौपट कर लेना इस कारोबार का एक और स्याह व खतरनाक पक्ष है। पुलिस सूत्रों की मानें तो मप्र में ग्वालियर-चंबल के बीहड़ों, बालाघाट और मंडला के जंगलो के साथ ही ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में नक्सली जंगल की जमीन में अफीम की खेती करवा रहे हैं। वहीं कुछ इलाकों में ग्रामीणों को प्रलोभन देकर व बंदूक की नोक पर डरा-धमका कर अफीम की खेती करने को बाध्य किया जा रहा है। तस्कर इसे दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उप्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भेजते हैं।

जैविक खेती करके मालामाल हो रहे किसान

मप्र में जैविक खेती किसानों की पसंद बनती जा रही है। इसकी वजह यह है कि जैविक फसलों को उत्पादन कर किसान मालामाल हो रहे हैं। इससे प्रदेश में जैविक खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है कि आज मप्र में 16 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। यही कारण है कि जैविक खेती के मामले में मप्र नंबर वन राज्य बन गया है। प्रदेश में इस समय लाखों किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। धान, गन्ना, गेहूं, सरसों, मसूर किसानों की पहली पसंद बने हुए हैं। प्रदेश के हर जिले में सैकड़ों किसानों ने जैविक खेती करनी शुरू कर दी है। इसी तरह प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार हो रहा है और आज देश में नंबर एक पर है। पंजाब, राजस्थान सहित अन्य जगह से व्यापारी आकर उत्पाद खरीदते हैं और निर्यात करते हैं। सर्वाधिक मांग बासमती चावल, शरबती गेहूं की है। सरकार ने भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रकोष्ठ गठित किया। अब कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का क्षेत्रीय कार्यालय भी खुल गया है।

प्रदेश में आज 16 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र ऐसा है, जहां जैविक खेती होती है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परंपरागत रूप से जैविक खेती होती है। इसे और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मप्र को 110 करोड़ रुपए भी दिए थे। इससे किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ जैविक खाद बनाने और प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित की जानी थीं। वहीं, सामान्य क्षेत्रों में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूर्व कृषि संचालक जीएस कौशल कहते हैं कि 1998 से जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम शुरू हुआ। सभी सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों में जैविक खेती प्रारंभ की गई। प्रत्येक विकासखंड में एक जैविक गांव बनाया गया और ये बढ़ते-बढ़ते एक हजार 565 हो गए। जैविक गांव बनाने का मकसद यही था कि किसान फार्म देखें और प्रेरित हों, पर यह काम आसान नहीं था क्योंकि जैविक खेती को लेकर भ्रांतियां बहुत हैं। धीरे-धीरे जैविक उत्पाद की मांग बढ़ने लगी तो किसानों को भी इसका महत्व समझ आने लगा और रकबा बढ़ने लगा।

प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती तो करते ही हैं, वहीं जैविक उत्पाद भी बनाते हैं जिनकी मांग विदेश में भी है। नरसिंहपुर के रविशंकर रजक 2013 से पूरी 13 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। गन्ना बेचने की जगह गुड़ बनाते हैं, पर इसे बेचने के लिए मंडी नहीं जाते हैं। खरीदार आते हैं और गुड़ ले जाते हैं। शाजापुर के राधेश्याम परिहार कहते हैं कि खेती करने के साथ प्रसंस्करण का काम भी शुरू कर दिया है। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर बनाकर बेचे जा रहे हैं। शाजापुर, नीमच से राजस्थान के कैलाश चौधरी जैविक उत्पाद खरीदकर दुबई सहित अन्य देशों में निर्यात करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना कि हर देश में जैविक उत्पाद की मांग है और यह लगातार बढ़ रही है।

कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश से अधिक से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात हो, इसके लिए निर्यातकों को सुविधा दिलाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट प्रकोष्ठ का गठन किया है। साथ ही अब प्रदेश में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय भी खुल गया है। इससे भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। एपीडा के डायरेक्टर चेतन सिंह कहते हैं कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। मप्र में क्षेत्र भी बढ़ा है और जैविक उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। यहां के शरबती गेहूं और चावल की सर्वाधिक मांग है। रतलाम, मंदसौर का लहसून, प्याज और मैथी दाना बाहर भेजा जाता है।

मप्र में जैविक खेती के प्रति किसानों का लगाव तेजी से बढ़ रहा है। खासकर आदिवासी बहुल जिलों में जैविक खेती का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया, दमोह, सागर, आलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, सीहोर, श्योपुर और भोपाल में जैविक खेती अधिक होती है। यही नहीं प्रदेश में उत्पादित जैविक अनाजों की देशभर में मांग बढ़ रही है। इस कारण प्रदेश जैविक खेती और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात में देश में अव्वल है।

● **राकेश ग्रोवर**

पांच लाख टन जैविक उत्पाद का निर्यात

प्रदेश में जैविक खेती का रकबा तो बढ़ रहा है पर उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग न होने से उत्पादकों को फायदा नहीं मिल पाता है। इसे देखते हुए कृषि विभाग अब किसान और व्यापारियों को एक मंच पर लाने की दिशा में काम कर रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश से पांच लाख टन जैविक उत्पाद का निर्यात हुआ, जो ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक का था। जैविक खेती करने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या एक लाख से अधिक है। सोयाबीन, चना, मसूर, तुअर और उड़द के उत्पादन में मप्र देश में नंबर एक पर है। वहीं, रामतिल और मूंग में दूसरा और गेहूं और बाजरा के उत्पादन में तीसरा स्थान है। अपर मुख्य सचिव कृषि एवं सहकारिता अजीत केसरी का कहना है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार मप्र जैविक खेती के मामले में देश में अव्वल है। प्राकृतिक तौर पर मप्र में जैविक खेती का क्षेत्र सर्वाधिक है। वहीं, किसान भी लगातार प्रेरित हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 में उत्पादन 13 लाख 92 हजार 95 टन रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उप्र का नंबर आता है। जैविक उत्पाद के निर्यात की दृष्टि से देखें तो देश-दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। मप्र से वर्ष 2020-21 में पांच लाख 636 टन जैविक उत्पाद निर्यात किए गए। इसका मूल्य दो हजार 836 करोड़ रुपए होता है।

‘जंगल के कानून’ पर डाका

‘प्रदेश में एक तरफ वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वन विभाग खुद जंगल के कानून पर डाका डाल रहा है। वन विभाग जंगली हाथियों को पकड़कर उन्हें पालतू बना रहा है। जानकारों का कहना है कि वन विभाग का यह कदम जंगल के कानून के खिलाफ है।’

वन विभाग की कार्यप्रणाली भी गजब की है। वह वन्य प्राणियों को सुरक्षा मुहैया कराने में तो पूरी तरह से नाकाम है। उधर, रिहाइशी क्षेत्रों में पकड़े जाने वाले वन्य प्राणियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार नियम-निर्देशों के खिलाफ है। विभागीय अधिकारियों हरकतें, वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम की लक्ष्मण रेखा पार करने वाली कही जाएंगी। विभाग की तरफ से अधिनियम की धज्जियां उड़ाने वाला वाकया जबलपुर इलाके में भटककर आए हाथी के साथ पेश आया। विभाग उसे पकड़कर वापस वन क्षेत्र में छोड़ने के बजाय कब्जे में लेकर पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए प्रशिक्षित करवा रहा है। इससे पहले भी हाथियों को उत्पाती बताकर इसी तरह नेशनल पार्कों में काम पर लगा दिया गया है।

विभाग के इस गैरजिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ वन्य प्राणी प्रेमियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया है। उन्होंने अखिल भारतीय सर्विस के अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से अनुमति भी मांगी है।

मंडला वन परिक्षेत्र से भटककर दो जंगली हाथी एक साल पहले जबलपुर वन परिक्षेत्र में पहुंच गए थे। इन हाथियों को स्थानीय लोगों ने राम-बलराम नाम दिया। हाथियों को सुरक्षा देने में वन विभाग पूरी तरह नाकाम रहा। उनमें से एक बलराम की बरगी मौहास के जंगल में शिकारियों के फैलाए करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। शिकारियों के चंगुल से बचे हाथी को जैसे-तैसे हकाल कर मंडला के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया। वन विभाग के अफसरों ने उसे जंगल में छोड़ने के बजाय कैद कर पालतू बनाने की ट्रेनिंग दी गई और महावतों के हवाले कर दिया। अब उसे अन्य पालतू हाथियों की तरह गश्ती दल, पयर्टकों के जंगल में भ्रमण आदि में तैनाती की व्यवस्था की जा रही है। हाथियों को पालतू बनाने की अनुमति विभागीय आला अधिकारियों ने लिखित में दी थी। पिछले महीने उमरिया के खितौली से एक जंगली हाथी को रेस्क्यू के बाद कान्हा ले जाया गया। उसे भी प्रशिक्षण देकर पर्यटन और टाइगर ट्रैकिंग के गुर सिखाए जाएंगे।

एक अन्य मामले में कुछ समय पहले सिवनी जिले के मुख्य वन संरक्षक ने नरसिंहपुर के वन मंडलाधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए उत्पाती हाथियों को पकड़ने का आदेश दिया। भटककर सीधी क्षेत्र में आने वाले जंगली हाथियों को पकड़कर जंगल में छोड़ने के बजाय बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उनका बाद में पर्यटकों को बाघों के दीदार कराने में इस्तेमाल होने लगा। जानकारों के अनुसार एक्ट उल्लंघन के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन, विभागीय आला अधिकारी तर्क देते हैं कि जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों को बचाने के लिए पकड़कर प्रशिक्षण के बाद बाघों के अनुश्रवण कार्य में लगाया जाता है। इसे सामाजिक कार्यकर्ता सरासर अधिनियम का उल्लंघन बता रहे हैं। अधिकारियों की ओर से इस मसले पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में वे कानूनी चुनौती देने की तैयारी में भी हैं।

जानकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों का कारनामा वाइल्ड लाइफ प्रोटक्शन एक्ट की धारा-55 का सीधा उल्लंघन है। इसलिए जबलपुर प्रकरण सहित अन्य मामलों में नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट (डीओपीटी) से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी जाएगी। वन्य प्राणियों के हित में कार्य करने वालों ने कहा है कि वे इन मामलों की विभागीय सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शहडोल सीसीएफ पीके वर्मा का कहना है कि हाथियों का रेस्क्यू गाइडलाइन के अंतर्गत ही किया जाता है। वाइल्ड लाइफ और संबंधित नेशनल पार्क की टीम मिलकर इसे करते हैं।

● **बृजेश साहू**

जबलपुर-शहडोल संभाग में हाथियों का मूवमेंट

विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में लगातार मानवीय दखल बढ़ रहा है। अवैध कटाई और खनन से हाथी और वन्यजीवों का मूवमेंट एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ रहा है। वन भूमि में सरकार काबिज ग्रामीणों को पट्टे भी दे रही है। संभाग के उमरिया बांधवगढ़ क्षेत्र व अनूपपुर के छत्तीसगढ़ से सटे गांवों में हाथियों का मूवमेंट बढ़ गया है। इधर, कटनी के बरही तहसील के मचमचा, निपनिया, बिचपुरा, करौंदीकला, बगदरा, करेला व कुआं सहित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे दूसरे गांव में भी हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है। उमरिया और अनूपपुर के पिछले तीन साल के आंकड़ों के अनुसार, 3066 ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टा दिया गया है। उमरिया में 2039 और अनूपपुर में 1027 ग्रामीणों को वनाधिकार दिया है। शहडोल संभाग में 100 से अधिक जंगली हाथियों का मूवमेंट है। सेफ जोन की तलाश में मप्र में हाथी-मानव के बीच द्वंद्व की स्थिति बढ़ी है। बांधवगढ़ में 45 से ज्यादा हाथियों के स्थायी ठिकाने के बाद पिछले दिनों अनूपपुर में 40 से ज्यादा हाथियों का दूसरा झुंड छत्तीसगढ़ से पहुंचा है।

आरक्षण में फंसी 'पंचायत'

मप्र के पंचायत चुनाव के लिए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर शह-मात का ऐसा खेल खेला गया जो पहले कभी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिला। पार्टियों के दफ्तर से लेकर वकीलों के घर, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय, विधानसभा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दांवपेंच चलता रहा, लेकिन लगभग 7 वर्षों के बाद प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव आखिर निरस्त हो ही गए। अब ये चुनाव कब होंगे, इस पर असमंजस बरकरार है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही गैरदलीय आधार पर होते हैं, लेकिन इस बार घोषित फिर निरस्त किए गए चुनाव में राजनीति चरम पर दिखी। पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर शह-मात का ऐसा खेल खेला गया जो पहले कभी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिला। पार्टियों के दफ्तर से लेकर वकीलों के घर, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय, विधानसभा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दांवपेंच चलता रहा, लेकिन लगभग 7 वर्षों के बाद प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव आखिर निरस्त हो ही गए। इन चुनाव में परिसीमन रोटेशन और आरक्षण को लेकर तरह-तरह के दावे-आपत्तियां पेश की गईं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जिस अध्यादेश के तहत यह चुनाव हो रहे थे वह अध्यादेश भी सरकार ने वापस लिया और अंततः लीगल ओपिनियन लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज के चुनाव निरस्त कर दिए।

अब पंचायत चुनाव कब और कैसे होंगे इसको लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। यानी 27 फीसदी **ओबीसी आरक्षण के पेंच में पंचायत चुनाव** इस कदर फंस गया है कि इससे निकालने का रास्ता फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है। दरअसल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की घोषणा के साथ ही दावे-आपत्तियों का दौर शुरू हो गया था खासकर परिसीमन रोटेशन और आरक्षण संबंधी मामले इतने ऊलझा दिए गए की बीच में स्थिति यह हो गई थी कि आधे गांव में चुनाव होंगे और आधे गांव में नहीं। खासकर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे थे, जबकि प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस पिछड़े वर्ग को ना केवल आरक्षण दिए जाने बल्कि एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में दिखाई दिए और इसी के चलते विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया और फिर सरकार ने वह अध्यादेश भी वापस ले लिया जिसके तहत चुनाव हो रहे थे और इसी आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने **विधि विशेषज्ञ** से सलाह लेकर आखिरकार पंचायती राज के चुनाव स्थगित कर दिए। इसी के साथ ही गांव-गांव में जहां सन्नाटा पसर गया, आवभगत का अभूतपूर्व दौर निकल गया। वहीं अब राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक पंचायती चुनाव को लेकर पंचायतें होती रहेंगी, क्योंकि दोनों ही दल एक-दूसरे को इस परिस्थिति के लिए दोषी ठहराते रहेंगे।

कब होंगे चुनाव?

बहरहाल लंबे अरसे बाद होने जा रहे पंचायती राज के चुनाव निरस्त होने के बाद अब कब हो पाएंगे कहना मुश्किल है। इतना रायता फैल गया है जो आसानी से सिमटने वाला नहीं है, क्योंकि **रोटेशन तय करना परिसीमन करने और आरक्षण** में इतने कानूनी दांवपेंच आसानी से नहीं सुलझने वाले। इनको सुलझाते-सुलझाते प्रदेश में 2023 के विधानसभा के आम चुनाव आ जाएंगे और फिर 2024 के लोकसभा के

अब सबकी निगाहें सुप्रीम आदेश पर

मप्र में पंचायत चुनाव के भविष्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आगामी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के आदेश से जारी आदेश में साफ किया गया कि क्योंकि मप्र की सरकार ने 26 दिसंबर को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य संशोधन अध्यादेश 2021 तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है और इसके चलते अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए किए गए परिसीमन और आरक्षण का स्टेटस गड़बड़ा रहा है, इसीलिए चुनाव निरस्त किए जाते हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा कि पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है और इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो चुका है। आयोग के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जल्द चुनाव करवाए जाना आवश्यक है और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 दिसंबर को दिए गए आदेश के पालन करते हुए यथा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई है। राज्य सरकार भी ओबीसी आरक्षण को निरस्त किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने का आग्रह कर रही है। वहीं केंद्र सरकार भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे चुनाव टालने की बात कह रही है। यानी अब गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सबकी निगाहें 3 जनवरी पर रहेंगी जब सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अब पंचायत चुनावों पर छाया कोहरा साफ हो पाएगा। गौततलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया था।

चुनाव और उसके बाद ही चुनाव के होने की संभावना बनेगी। फिलहाल पिछले 1 महीने से गांव-गांव में इन चुनावों को लेकर सरगर्मी थी और जहां पर पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को था वहां नामांकन पत्र वापस लेने का समय भी निकल गया था और चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा था लेकिन अब गांव-गांव में असमंजस की स्थिति बन गई है। राजनीति की नर्सरी हरियाली आने के पहले उजड़ गई। गांव की पंचायतें पंचपरमेश्वर के लिए कब तक इंतजार करेंगी कहा नहीं जा सकता।

सवा 2 लाख की मेहनत बेकार

उल्लेखनीय है कि ओबीसी आरक्षित पदों को छोड़कर जिन अन्य सवा तीन लाख पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रखी थी, वहां पहले और दूसरे चरण के नामांकन पर्चे भरने, नाम वापसी तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इन पदों के लिए 2,15,035 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पर्चे भरे थे। इनमें से जिला पंचायत सदस्य के लिए 3541, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 14 हजार 814, सरपंच पद के लिए 60 हजार 415 और पंच पद के लिए 1 लाख 36 हजार 265 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है। हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने नाम वापसी भी की थी और करीब सवा लाख से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव में बचे थे। इनमें से औसत रूप से प्रत्याशियों ने करीब पांच से दस हजार रुपए चुनाव प्रचार व अन्य खर्चों में कर दिया था।

मप्र में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब नामांकन पत्र दाखिल करके चुनाव प्रचार शुरू करने वाले लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा है। रतलाम जिले में एक जनपद प्रत्याशी ने सीएम हेल्पलाइन में आत्महत्या की चेतावनी दे डाली है। वहीं, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को भाजपा का राजनीतिक स्वार्थ करार दिया है तो भाजपा पंचायत चुनाव निरस्त होने पर कांग्रेस को दोषी बता रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए जाने

के बाद 24 दिन चली चुनाव प्रक्रिया पर करोड़ों रुपए का खर्च बेकार साबित हुआ है। वहीं, नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी के बाद जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उन्होंने चुनाव प्रचार सामग्री, दीवार लेखन आदि शुरू कर दिया था। अचानक चुनाव निरस्त होने से उनका हजारों रुपए का खर्च बेकार हो गया है। इससे लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के साथ भरी गई राशि वापस करने के आदेश किए हैं लेकिन प्रचार सामग्री और अन्य खर्चों से प्रत्याशियों की नाराजगी बढ़ी है। गौरतलब है कि एक ग्राम पंचायत में तो 44 लाख रुपए में सरपंची की कुर्सी आपसी समझौते में एक प्रत्याशी ने बोली में खरीद भी ली थी।

रतलाम जिले के एक जनपद प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में धमकी दी है। उन्होंने पंचायत चुनाव निरस्त होने से उनके हजारों रुपए खर्च होने की शिकायत दर्ज कराना चाही थी। मगर सीएम हेल्पलाइन से जब उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया गया तो वे नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव खर्च के बेकार जाने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने मंत्री भूपेंद्र सिंह पर विधानसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे उनके स्तर के नेता नहीं हैं लेकिन इतने बड़े नेता ने विधानसभा में भ्रामक व गलत जानकारी दी कि मेरे और जया ठाकुर द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म करने की मांग अदालत में रखी गई। इस गलत बयानी के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। वहीं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. हितेष बाजपेयी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसकी वजह से ही पंचायत चुनाव निरस्त हुए हैं जिससे पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने वाले लाखों लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

शुरू से बैकफुट पर सरकार

पंचायत चुनाव पर शिवराज सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसकी शुरुआत एक माह पहले हो गई थी, जब शिवराज सरकार ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को रद्द करने और नए रोटेशन के बिना 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने का अध्यादेश जारी किया था। कांग्रेस इसे कोर्ट में चुनौती देगी? सरकार को पता था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नतीजा, पंचायत चुनाव टालने का निर्णय लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित करने का आदेश दिया था। तब सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था- **आग से मत खेलिए।** कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाइए। सरकार और भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा दिया था। इसके बाद मामला न्यायालयीन और सरकारी होने के साथ ही राजनीतिक हो गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर हमला भी किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के खिलाफ है।

राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद सरकार ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। भाजपा की तरफ से कहा जाने लगा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। कांग्रेस की वजह से ही ओबीसी का हक मारा गया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि हमने रोटेशन प्रणाली पर सवाल उठाया था। ओबीसी आरक्षण के पक्ष में राज्य सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रख पाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों तीन चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन भी हो गए थे। इसी बीच, ओबीसी आरक्षण में रोटेशन प्रणाली को लेकर पेंच फंस गया था। कई लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाकर चुनाव रद्द करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। मप्र हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग (सुनवाई) से इनकार कर दिया था। इसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य कर दिया। अगले दिन इन सीटों पर चुनाव स्थगित करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जेंट हियरिंग नहीं होने से सरकार को झटका लगा।

विधानसभा में भी बवाल

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हुआ। सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग

अब नए सिरे से होगा परिसीमन

सरकार ने कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर समाप्त कर दिया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गत दिनों जारी की गई है। अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। फरवरी के अंत तक परिसीमन का काम पूरा कर लिया जाएगा। पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा। इससे पहले सरकार ने एक महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को लागू परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था, जिसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था। कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह, 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 22 नंवबर को ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए थे। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया था। यानी 2014 में हुए चुनाव के दौरान थे। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती दी थी।

रहा था। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं चुनाव को तत्काल रोका जाए। मामला बढ़ता देख शिवराज सिंह चौहान ने सदन में सफाई दी। सदन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। हमारी सरकार लगातार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं। सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव को लेकर आक्रोश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सदन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके यह ऐतिहासिक फैसला करे कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम तो यही कह रहे थे कि सदन से संकल्प पारित किया जाए। अगले दिन फिर इसे लेकर सदन में बवाल हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि अब राज्य में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे। वहीं, कांग्रेस ने भी कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में हम भी सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई भी है।

अपनों के निशाने पर सरकार

ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर शिवराज सरकार असहज हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसे लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल तक ने इशारों-इशारों में निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा था- बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने शिवराज सिंह से बात की थी। इसके बाद प्रहलाद पटेल ने कहा कि पिछड़ों को आग में ना झोंकें तो अच्छा होगा। साथ ही, जरूरी कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ऐसे में शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसी वर्ग से आते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज सरकार किसी भी कीमत पर इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता है। अंत में सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को टालने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने कैबिनेट के फैसले की फाइल एक घंटे बाद ही राजभवन भेज दी थी। उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी हो गई।

चुनौती है ओबीसी आरक्षण

शिवराज सिंह चौहान के लिए ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। उनकी सरकार में आरक्षण कम होता है तो नुकसान पार्टी को भी होगा। लिहाजा वे पंचायत चुनाव के आरक्षण के जरिए अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। यद्यपि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया रोके जाने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है। आयोग विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। सरकार द्वारा परिसीमन को बहाल किए जाने का आदेश उस वक्त आया है जब केवल मतदान की प्रक्रिया शेष बची है। ऐसे में चुनाव नहीं भी रूकते तो भी शिवराज सिंह चौहान यह तो कह ही सकते हैं कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को रोकने का प्रयास तो किया। कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो आरक्षण बरकरार रहता। पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित की गईं थीं, उन पर अभी चुनाव नहीं हो रहा है। इन सीटों पर चुनाव उसी स्थिति में संभव है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग में बदली जाएं।

उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर रोक लगाए जाने के मामले में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उनके आबादी के आंकड़े जुटाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के संदर्भ में दिए गए इस आदेश की वजह

निर्वाचन आयोग को लौटाने होंगे अब 20 करोड़ रुपए

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही अब निरस्त हो गए हैं, लेकिन अब भी सरकार, राजनीतिक दल और प्रत्याशी इसमें बुरी तरह से उलझे हुए हैं। इसमें सरकार के बाद अगर कोई सर्वाधिक उलझा है तो वह है इन चुनावों में नामाकंन करने वाले ग्रामीण। दरअसल यह चुनाव ऐसे समय निरस्त किए गए हैं जबकि, प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोर पकड़ चुका था। यही वजह है कि अब आयोग को प्रत्याशियों द्वारा जमा कराई गई जमानत की राशि तो लौटानी ही पड़ रही है, साथ ही इन चुनावों की विभिन्न तैयारियों पर खर्च की गई राशि का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके उलट उन प्रत्याशियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है जिन्होंने चुनावी प्रचार के लिए अपनी संपत्ति बेचकर या फिर उसे गिरवी रखकर राशि का इंतजाम किया था।

दरअसल प्रदेश में यह चुनाव तीन चरणों में 6 जनवरी से होने जा रहे थे, जो सरकार की नाकामी की वजह से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विवाद की भेंट चढ़ गए हैं। यह चुनाव ऐसे समय निरस्त किया गया है जब पहले चरण के मतदान के लिए महज 9 दिन का समय ही रह गया था। इसकी वजह से अब पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल कर चुके करीब 2.15 लाख उम्मीदवारों की फीस वापसी की कवायद करनी होगी।

से पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के चुनाव पर रोक लग गई है। आगे भी यदि ओबीसी को आरक्षण का लाभ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में देना है तो उसके लिए आबादी का आधार देना होगा। इसमें भी कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक तभी हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति दे। इसके लिए कोर्ट के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। इसके मद्देनजर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का काम प्रारंभ किया है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि 7 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और पंचायतवार व वार्डवार जानकारी शासन को भेजी जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई रोक को बहाल कराने के लिए शिवराज सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा चुकी है। इस पर 3 जनवरी को सुनवाई प्रस्तावित है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की।

जुटाए जा रहे जातिगत आंकड़े

प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर मचे घमासान के बीच सरकार बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार फिलहाल ओबीसी को 22 फीसदी आरक्षण देने के मसौदे पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश में पहली बार ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराई जा रही है। इसके लिए सभी कलेक्टरों को 23 दिसंबर को पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया है। वहीं दूसरे राज्यों की स्ट्रेटजी पर सरकार की नजर है। यह जानकारी भी जुटाएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मप्र की तरह अन्य राज्य पुनर्विचार याचिका दायर करने जैसे विकल्पों पर जा रहे हैं या नहीं?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री

ने पिछड़ा वर्ग आयोग से कहा है कि वैकल्पिक तौर पर ओबीसी वर्ग की सीट वार गणना करने का रोडमैप भी बनाएं। इधर, ओबीसी को लेकर सरकार की तैयारी 22 प्रतिशत आरक्षण देने की दिख रही है। इसके लिए सांख्यिकी विभाग को आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश की पंचायतों में ओबीसी वोटर्स की गिनती कराने का आदेश देने के बाद राज्य सरकार अब यह जानकारी जुटा रही है कि प्रदेश की पंचायतों में अनारक्षित सीटों पर पिछले सालों में कितने ओबीसी नेता निर्वाचित हुए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग इस जानकारी के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में ओबीसी नेताओं के पिछड़ेपन का अध्ययन करना चाहता है। साथ ही ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने के मामले में कोर्ट में यह जानकारी देने की तैयारी है कि इसी के चलते इस वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।

मप्र पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन के स्वरूप, रीति और कारणों के अध्ययन की जानकारी मांगी है जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की राजनीतिक हिस्सेदारी में बाधा उत्पन्न होती है। कलेक्टरों से कहा गया है कि जिलों की सभी ग्राम पंचायतों की वार्ड इकाई वार और पंचायत वार अनारक्षित वर्ग के लिए निश्चित सीटों के विरुद्ध चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों की जानकारी दस दिन में एक्सेल शीट में प्रस्तुत करें। यह जानकारी 7 जनवरी तक मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के दफ्तर में पहुंचाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आदेश देने के बाद राज्य सरकार पंचायतों में निवास करने वाले ओबीसी वर्ग के वोटर और उनकी अलग-अलग जातियों की जानकारी मांग चुकी है। इसके लिए पंचायत सचिवों को जल्द जानकारी भेजने के लिए कहा गया है।

इसके पहले नवंबर माह में मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सचिव द्वारा जारी निर्देश में कलेक्टरों से मांगी गई जानकारी में कहा गया था कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने तथा इन वर्गों का कल्याण करने के लिए सुझाव और अनुशंसाएं आयोग को देना है। इसलिए शासन की विभिन्न योजनाओं और विभागों की संरचना में ओबीसी वर्ग की भागीदारी का अध्ययन किया जाना है। आयोग ने कलेक्टरों से जिला स्तर पर नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत तृतीय, चतुर्थ श्रेणी तथा संविदा-आउटसोर्स और अन्य नियुक्त ओबीसी वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी भेजी जाए।

...फिर सरपंच होंगे पंचायतों के मुखिया!

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने के साथ ही अब फिर से ग्राम पंचायतों की कमान सरपंचों को सौंपने की तैयारी है। चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बाद पंचायत संचालनालय ने पंचायतों की कमान सचिव एवं पंचायत समन्वय अधिकारी (पीसीओ) को सौंप दी थी। अब फिर से सरपंचों को कमान सौंपी जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर पर फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव निरस्त करने का ऐलान करने के अगले ही दिन पंचायत संचालनालय की ओर से पंचायत संचालन संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। जिसमें मौजूदा स्थिति में सचिव एवं पीसीसी से पंचायत संचालित कराने के साथ-साथ पूर्व की भांति सरपंचों को पंचायत सौंपने का प्रस्ताव भी शामिल है। हालांकि अभी इसका फैसला राज्य शासन को करना है कि पंचायतों की कमान फिर से सरपंचों को सौंपी जाए या फिर सचिव एवं पीसीओ के पास ही अधिकार रहें। चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव निरस्त करने के साथ ही प्रदेशभर में लागू आचार संहिता अप्रभावी हो गई है। ऐसे में सचिव एवं पीसीओ से पंचायतों की कमान वापस लेकर सरपंचों को सौंपी जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सरकार किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहती है। क्योंकि पंचायतों के अधिकार सरपंचों को सौंपने को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत संघ मांग कर चुका है और आंदोलन की चेतावनी भी दे चुका है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सरपंचों को ही मुखिया बनाने की तैयारी में है।

मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर

बृहद अर्थशास्त्रीय आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर है। निवेशकों व उद्योग क्षेत्र के आशावाद और सरकारी खर्च के कारण वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.5 से 10 फीसदी तक हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के बारे में कमोबेश यही अनुमान व्यक्त किया है। अगर हमारी आर्थिक विकास दर इतनी होती है, तो फिर भारत 50 खरब डॉलर की, और अगले दशक में 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

वित्त वर्ष 2022 के लिए ताजा सकल मूल्य वर्धित अनुमान बताता है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में न्यूनतम सकल मूल्य वर्धित पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के -20.2 फीसदी की तुलना में 26.8 प्रतिशत रहा है। बेशक पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक बदहाली का कारण कोविड-19 महामारी और उससे निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन था। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 31.7 फीसदी था, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से पहले के दौर की स्थिति में अभी नहीं पहुंच पाई है और इसका कारण है कोविड की दूसरी लहर के दौरान लगे आंशिक लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर असर।

क्षेत्रवार विश्लेषण बताता है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 5.7 फीसदी वृद्धि के मुकाबले 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उस कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सहारा है, जिस पर 43 प्रतिशत श्रमबल की निर्भरता है। इसी अवधि में उद्योग क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की -38.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 67.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। जबकि आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाने वाले सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के -19 प्रतिशत की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 17.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। बेशक, इस साल आर्थिक विकास दर के बढ़े हुए आंकड़े कमोबेश अतिरंजित लगते हैं, जिसका मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर में आई भारी गिरावट रही, उसमें भी खासकर पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही को महामारी का तात्कालिक असर झेलना पड़ा था। इस लिहाज से मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के विश्लेषण से अर्थव्यवस्था की कहीं सटीक तस्वीर सामने आएगी।

सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन आदि उप-क्षेत्र का प्रदर्शन लचर है। दरअसल हवाई यात्रा, अतिथि-सत्कार तथा होटल, रेस्टोरेंट्स व ढाबे महामारी में सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस साल महामारी की दूसरी लहर भी इस क्षेत्र को झेलनी पड़ी, लिहाजा इसकी आर्थिक विकास दर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। बैंकिंग उप-क्षेत्र में भी उम्मीदजनक वृद्धि देखी जा रही है। विगत सितंबर तक बैंक जमाराशियों में पिछले वर्ष की तुलना में 9.3 फीसदी और कर्ज में 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ये दरें उत्साहजनक तो हैं, लेकिन उच्च विकास दर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी नहीं हैं। मार्च, 2018 तक बैंकों में कुल गैरनिष्पादित परिसंपत्ति का आंकड़ा 12 प्रतिशत था, जो मार्च, 2021 में घटकर 8 फीसदी रह गया है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे-ब्याज दरों में महामारी के पहले की तुलना में डेढ़ से दो फीसदी की कमी की गई है। ऐसे ही, होम लोन की ब्याज दर अभी सबसे कम करीब 6.5 फीसदी है, जबकि महामारी से पहले ब्याज दर औसतन 8.5 प्रतिशत थी।

अर्थव्यवस्था के व्यापक संकेतक भी उतने ही गौरतलब हैं। मुद्रास्फीति कम हो रही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त के 5.3 फीसदी के मुकाबले सितंबर में घटकर 4.35 प्रतिशत रह गया। उद्योग क्षेत्र का प्रदर्शन भी सुधरा है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अगस्त में 11.8 फीसदी रहा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर के साथ सर्वकालीन ऊंचाई पर है। वित्त वर्ष 2021 में 82 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी एक रिकॉर्ड है। कॉरपोरेट क्षेत्र भी मजबूती से उभर रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक रही। ज्यादातर कंपनियों ने रिकॉर्ड अवधि में कर्ज चुकाए और कॉरपोरेट कर्ज में भी कमी आई। कॉरपोरेट कर को घटाकर 25 फीसदी पर ले आने का भी फायदा हुआ है।

● **कुमार विनोद**

व्यापार घाटा 78 अरब डॉलर हो चुका

विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा है। पिछले साल के 125 अरब डॉलर की तुलना में विगत सितंबर तक हमारा निर्यात 198 अरब डॉलर का हो चुका है। हालांकि इसी अवधि में पिछले साल की तुलना में हमारा आयात भी बढ़ा है। नतीजतन व्यापार घाटा भी पिछले साल के 26 अरब डॉलर से बढ़कर 78 अरब डॉलर हो चुका है। व्यापार घाटा बढ़ने का एक कारण कच्चे तेल के मूल्य में आई तेजी भी है। अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक संकेतक कर संग्रह में वृद्धि भी है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगस्त तक कर संग्रह पिछले साल की समान अवधि के 5.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.59 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस वित्त वर्ष में अगस्त तक राजकोषीय घाटा पिछले साल के 8.7 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 4.68 लाख करोड़ रुपए ही रहा। दरअसल राजकोषीय घाटा सरकारी खर्च पर निर्भर करता है। सरकार खर्च बढ़ाने का फैसला लेती है, तो इससे उपभोग और विकास बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास में गति आती है। हमारे शेयर बाजार का मूल्य निर्धारण करें, तो यह करीब 260 लाख करोड़ रुपए बैठता है, जो मौजूदा जीडीपी 210 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। भारतीय शेयर बाजार की यही रफ्तार रही, तो इस साल यह ब्रिटेन के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दुनिया के शीर्ष चार देशों में पहुंच जाएगा। इस साल देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

जिताने-हराने का मंसूबा

उप्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उप्र की राजनीतिक तस्वीर समझना बहुत मुश्किल नहीं है। उसे हिंदुत्व, महंगाई, गरीबी, बेकारी, कोरोना आदि-आदि चीजों में मत तलाशिए। जमीन पर लोगों से बात करिए। पता चल जाएगा। कोई क्यों जीत रहा है या कोई क्यों हार रहा है।

उप्र में चल क्या रहा है और तस्वीर आखिर है क्या? इस वक्त अगर उप्र चुनाव को लेकर आम लोगों से बातचीत की जाए तो लोग एक क्षण में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाते हैं। दूसरे क्षण अखिलेश यादव, तीसरे क्षण कहने लगेंगे कि बसपा कांग्रेस को बिल्कुल कमजोर मत आंकिए। विधानसभा भंग रहेगी। त्रिशंकु। और चौथे पल यह भी बताना नहीं भूलते कि जीते चाहे जो, पर आएगी तो भाजपा ही। पूछिए कैसे? प्रक्रिया और पूरी डिटेल सामने रख देंगे। जाहिर है कोई भी उप्र की तस्वीर समझने की बजाय जलेबी में फंस जाएगा। जबकि उप्र का चुनाव भले पेंचीदा दिख रहा हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं कि चीजें बहुत धुंधली हैं और उसे खुली आंखों से देखा ही नहीं जा सकता।

उप्र में भले कई क्षत्रप हों मगर जो सबसे साफ आवाज निकल रही है, वो भाजपा-सपा को जिताने-हराने की। कुछ लोग भाजपा को जिताना चाहते हैं और कुछ लोग हराना। ठीक इसी तरह सपा को भी। लेकिन भाजपा-सपा को जिताने-हराने के पीछे का उनका मंसूबा राजनीतिक होने की बजाय निजी ज्यादा है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग ढंग से। उदाहरण के लिए उप्र का मुसलमान किसी भी सूरत में भाजपा को हारते देखना चाहता है। उसे सपा की हार से ज्यादा फर्क भाजपा की जीत से पड़ रहा है।

मुसलमानों की वजहें निजी हैं। नागरिकता कानून, तीन तलाक, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा आदि-आदि की वजह से भाजपा से नाराज है। असल में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढहने के बाद से ही मुसलमानों ने तय कर लिया है कि सिर्फ भाजपा को हराना है। महंगाई, बेकारी, अशिक्षा, आरक्षण के दायरे से दलित मुसलमानों का बाहर होना, पसमांदा मुसलमानों की चिंताओं या फिर विधानसभा लोकसभा में मुसलमानों की भागेदारी को लेकर उसने कभी सवाल ही नहीं पूछे। उसने कभी सवाल नहीं पूछा कि सरकारी नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी लगातार न्यूनतम क्यों होती जा रही है। जबकि पिछले 30 साल से सभी गैर भाजपाई सरकारें उसकी देन है। कम से कम उप्र में तो नहीं ही पूछा। जो पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने दौड़ी ना तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं।

ये सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों ने इन चीजों को कभी बड़ा मुद्दा ही नहीं माना। या यह भी हो सकता है कि पार्टियों ने मुसलमानों का ध्यान ही इस ओर जाने नहीं दिया। उन्हें बस भाजपा सरकारों को ढहाने में लगाए रखा। यहां तक कि 5 साल पहले अखिलेश राज में मुसलमानों ने सबसे बड़ा दंगा झेला। कैम्पों में रहे, लेकिन चुनाव में उनके लिए यह भी कोई खास मुद्दा नहीं है। 2017 में भी मुसलमानों के लिए मुद्दा नहीं बन पाया था तो अब क्या ही होगा। बाबरी के बाद मुसलमानों ने जिस तरह भाजपा को हराने की कसम उठाई है, लगातार राजनीतिक अवसरवाद का शिकार होते रहे हैं। इसका खामियाजा यह रहा कि 2014, 2017 और 2019 के उप्र चुनावों के बाद राजनीतिक प्रासंगिकता लगभग गंवा चुके हैं। मुसलमान 30 साल से लगभग ऐसे ही वोट दे रहा है, भाजपा को हराने वालों के साथ जाना है। कोई भी हो- उसे शिवसेना को भी वोट देने में कोई गुरेज नहीं।

सपा के बेस वोट से कहीं ज्यादा वोट मायावती के नेतृत्व में बसपा के पास है। और निश्चित ही कुछ जगहों पर कांग्रेस के पास भी है। 2022 के चुनावों में भी अगर मुसलमानों का वोट पैटर्न नहीं बदला तो वह निश्चित ही बसपा और कांग्रेस के पास भी जाएगा। तो उप्र चुनाव में मुसलमानों को सिर्फ सपा के खूंटे की गाय ना माना जाए।

अब सपा को हराने वाली ताकतों से बात करिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने उनके लिए काम किया या नहीं। दो तरह की ताकतें सपा को हारते देखना चाहती हैं। एक तो इसमें धार्मिक कट्टरता का शिकार समूह है जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने मुसलमानों को अच्छा सबक सिखाया है। उसमें ज्यादातर सवर्ण जातियां और बाकी खाया-अघाया ओबीसी समुदाय का संपन्न तबका है। हैरान मत होइए। इसमें व्यापक रूप से यादव समुदाय भी है जो पिछड़ा होने की बजाय अब हिंदू के रूप में खुद को ज्यादा सहज पाने लगा है।

सपा को हारता देखने वाली दूसरे तरह की ताकतों में राजनीतिक रूप से दलित-पिछड़ों की असंगठित जातियां हैं। उप्र के समाज की ऐसी जातियां जिनके पास मसल पावर नहीं है। जिनकी अपनी पार्टियां नहीं हैं या हैं तो कोई करिश्मा दिखाने लायक नहीं। उप्र में एक नैरेटिव चलता रहता है, सपा की सरकार आती तो

उप्र के यादव बहुल क्षेत्रों में भाजपा की मौजूदगी

उप्र का वोट पैटर्न देखिए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव वोटर भाजपा के साथ गए। सपा उन्हीं चुनिंदा सीटों को जीत पाई जो मुस्लिम बहुल थीं। लोकसभा चुनाव छोडिए, हालिया पंचायत चुनाव देख लीजिए। जिन क्षेत्रों पर सपा का स्ट्रांगहोल्ड है वहां से जीतने वाले यादव चेहरे कौन हैं? वे भाजपा के साथ क्यों गए? सपा अगर ईमानदार थी तो पिछले पांच साल में मुसलमानों का मुद्दा उठाने की कोशिश करते क्यों नहीं दिखी? आप सपा के मूल वोट बैंक से बात करिए। वो 2022 के लिए तो अखिलेश की बात कर रहा है मगर 2024 में मोदी के खिलाफ नहीं है। ऐसा क्यों है? वो बहुत शातिर तरीके से या तो राहुल गांधी को खारिज करता दिखेगा या किसी काल्पनिक तीसरे मोर्चे की बात करता दिखेगा।

मुसलमानों के वोट के बदले सपा सरकारों ने दंगे, लिंचिंग और गरीबी दी

समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन बदले में क्या दिया? अखिलेश की ही सरकार में मुसलमान युवाओं को आतंक के नाम पर परेशान किया गया। मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग की घटनाएं पहली बार कब और किसके शासन में हुईं? मुजफ्फरनगर में भयावह दंगे कब हुए? किसके राज में मुसलमान अपना घरबार छोड़कर कैम्पों में भागे? अखिलेश की पूर्ण बहुमत सरकार में हुआ। मुसलमान कैसे फिर अखिलेश की सरकार पर भरोसा कर लेगा। एक बहुमत की सरकार चुप बैठी रही। मुसलमानों पर हमला करने वाले लोग कौन थे? क्या सपा ने यादवों को कभी सेकुलराइज किया? नहीं। उसने ऐसे यादव वोटबैंक को तैयार किया जिसका चरित्र मुस्लिम विरोधी है। यह रणनीतिक दबाव भी है कि मुसलमानों ने सपा को वोट नहीं दिया तो यादव भाजपा के साथ चला जाएगा। धर्म की अंधी राजनीति के लिए सपा-भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत है। अखलाक की लिंचिंग कहां हुई? अखिलेश ने क्या किया? मामले में संयुक्त राष्ट्रसंघ जाने का बयान देने वाले आजम खान ने सार्वजनिक रूप से बेबसी जताई थी।

मुसलमानों की वजह से है मगर जाती सिर्फ यादवों की वजह से हैं। सपा सरकार में जमीन कब्जाने, मारपीट, दबंगई के मामले ज्यादातर छोटी जातियों के साथ हुए और ज्यादातर मामलों में आरोप सपा के काडर पर ही आया।

अब यह प्रोपगेंडा है या सच, लेकिन सपा सरकार में जाति विशेष गुंडागर्दी, मुद्दा ना होते हुए भी हमेशा बड़ा मुद्दा बनती रही। योगी से पहले मायावती ने भी सिर्फ इसी मुद्दे पर भाजपा-सपा समेत सभी को रौंद दिया था और 2017 में अखिलेश की भयावह विदाई के पीछे भी यही मुद्दा बड़ा था। मोदी समेत भाजपा के नेता बार-बार भाषणों में इसका जिक्र बिना वजह नहीं कर रहे।

उदाहरण के लिए ओमप्रकाश राजभर ने भले ही अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया हो, मगर पूर्वी उप्र के इलाकों में राजभर, यादवों का सामजिक तानाबाना बहुत ठीक नहीं है। वैसे ही जैसे कभी ब्राह्मण-ठाकुरों के निशाने पर हुआ करते थे। दर्जनों जातियां सिर्फ निजी वजहों से चाहती हैं कि कोई आए पर अखिलेश नहीं। स्वाभाविक है कि यहां हिंदुत्व का शोर नहीं, विकास का मुद्दा नहीं और जाति के परंपरागत कागजी समीकरण भी नहीं दिखते जिसे भाजपा ने राज्य के पिछले तीन चुनावों में बेमतलब साबित कर दिया है। भाजपा के झंडे में जो गैर यादव ओबीसी जमावड़ा दिख रहा है उसे भले ही हिंदुत्व की शक्ल दी जाए मगर हकीकत में वह निजी जरूरतों के लिए डरी हुई कमजोर जातियों का जमावड़ा है। नरेंद्र मोदी, केशव मौर्य या भाजपा के अन्य गैर यादव ओबीसी चेहरों ने उसे हिंदुत्व का सैद्धांतिक जामा भर दिया है बस।

उप्र को लेकर दो बड़े सवाल इन दिनों चर्चा में है। एक तो ये कि उप्र में योगी-केशव मौर्य के होने के बावजूद भाजपा नरेंद्र मोदी को ही चेहरा क्यों बना रही है और दूसरा ये अब तक भाजपा, कांग्रेस पर हमलावर थी, मगर अयोध्या और काशी में सक्रियता दिखाने के बाद भाजपा के निशाने पर अखिलेश ही क्यों हैं? सपा नेताओं पर आयकर विभाग के छापे भी इसे पुख्ता करते हैं। भाजपा के इस मूव से तो यही आभास हो रहा कि उसकी सीधी टक्कर सिर्फ अखिलेश के साथ है। यह सच है कि सीधी लड़ाई में नुकसान भाजपा का ज्यादा है। अब सवाल है कि भाजपा जानबूझकर ऐसा नुकसान क्यों उठा रही है?

दरअसल, भाजपा का यह मूव चुनाव तक अपने उस जुटान को सुरक्षित करना है जो किसी भी सूरत में सपा का सरकार नहीं देखना चाहती। सपा नेताओं पर दबाव से जिसे दिली खुशी होती है। जो अतीक अहमद का मकान ढहाने पर खुश होता है। मुसलमान सपा के साथ एकमुश्त नहीं जा रहे लेकिन उनके एकमुश्त जाने के शोर से सपा की मजबूती का आभास ज्यादा होता है। यानी मुसलमानों की गोलबंदी। उप्र में ये संभावना जितनी गहरी नजर बनी रहेगी, भाजपा उतना ही मजबूत होगी।

दिल्ली से गोरखपुर तक इसीलिए सिर्फ मोदी के चेहरे को आगे किया जा रहा है। यह योगी बनाम मौर्य के झगड़े में पिछड़ा बनाम सवर्ण की लड़ाई को भी कमजोर करने के लिए है। चुनाव में मोदी के चेहरे का इस्तेमाल उन संकेतों में भी गिना जा सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि केशव मौर्य की ताजपोशी हो सकती है। या फिर योगी को दिल्ली में बड़ी जगह मिल सकती है। प्रधानमंत्री का पद भी। मोदी के चेहरे का इस्तेमाल इसलिए भी हो सकता है कि 2019 के बाद ऐतिहासिक काम मोदी ने किए लेकिन कोरोना महामारी ने सभी पर पानी फेर दिया। अर्थव्यवस्था संकट में दिखी। भला विकास और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय मोदी की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उप्र में एक रिकॉर्डतोड़ जीत का श्रेय मोदी की कप्तानी को देने से बेहतर उपलब्धि और क्या हो सकती है। उप्र में नरेंद्र मोदी ही अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा हैं। भाजपा के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित।

सपा ने मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाते हुए वोट लिया। हिस्सेदारी तो दूर की बात, कभी भी मुसलमानों को उनकी आबादी का आंकड़ा तक नहीं बताया। ऐसी चर्चा भी नहीं होने दी गई। जबकि इसके उलट सपा जातिवार गड़ना कराने के मुद्दे उठाती रहती है। हकीकत में सपा जाति जनगणना भी नहीं चाहती। मगर अन्य पिछड़ी जातियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए वह ऐसा ढोंग रचती है। यह रणनीति है। अगर जातिवार जनगणना हुई तो पोल खुल जाएगी कि उप्र में यादव समुदाय अपनी आबादी से ज्यादा सरकारी नौकरियों में है। पिछले 30 साल में उप्र में ओबीसी के नाम पर सपा की वजह से यादव समुदाय ने सबसे ज्यादा मलाई काटी है। इस समुदाय में आर्थिक प्रगति सरकारी नौकरियों और अपनी सरकार होने की वजह से आई, यह छुपी बात नहीं है। मुसलमान भी देख रहा है। पसमांदा मुसलमानों का विरोध करने वाले सपा ने कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरियां दीं? मुसलमानों को अपने अधिकार तक नहीं मालूम। पिछले 30 साल में ज्यादातर सपा-बसपा की सरकारें रहीं। मुसलमानों के वोट से सत्ता की मलाई बहुत खा चुके। अब यह सिलसिला बंद होगा।

● **रजनीकांत पारे**

संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सियासी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर सवाल पूछने वाले सांसद और जवाब देने वाले मंत्री क्यों गंभीर नहीं दिखे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सांसदों को सदन में हाजिर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन इसके उलट खुद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सांसद संसद में कम और चुनावी रण में ज्यादा दिखाई दिए। संसद के कैलेंडर को लेकर भी सियासी चर्चाएं शुरू हुई।

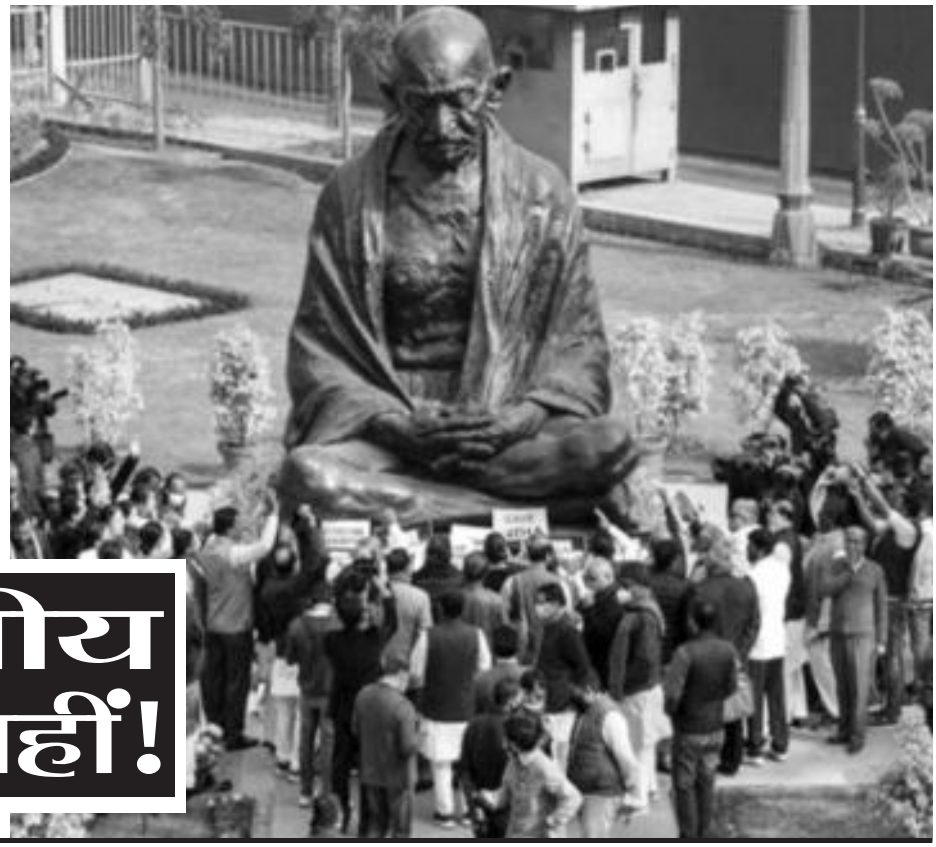

माननीय गंभीर नहीं!

संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपदेश भी काम नहीं आया। शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने की हिदायत दी थी, लेकिन हालात ढाक के तीन पात रहे। ऊपर से मजे की बात इस बार सदन में जो हुई उसे जानने के बाद कोई भी अपने दांतों तले अंगुलियां दबा ले। भाजपा सांसदों को उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहे। अधिकांश समय प्रधानमंत्री मोदी उप्र और उत्तराखंड में भाजपा के चुनाव प्रचार में बिजी रहे।

सबसे बड़ा मजाक तो सदन का तब बना जब प्रश्नकाल में सवाल पूछने वाले खुद 14 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। यहां तक की एक बार तो हद ही हो गई जब मुख्य सचेतक और सरकार के मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। सियासी जानकारों का कहना है कि उपदेश और आचरण में समानता होनी जरूरी है। साथ ही चुनावों को देखते हुए संसद का कैलेंडर जारी करने की भी चर्चा जोरों पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय दल की बैठक में सांसदों को जोरदार नसीहत दी थी। आपको यह भी बता दें कि पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के सांसदों को उपदेश दे रहे हैं कि संसद की कार्यवाही के दौरान उनको मौजूद रहना चाहिए। इसके बावजूद उनके सांसद नदारद रहते हैं तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने इस ओर सदन का ध्यान भी दिलाया।

कांग्रेस के सांसदों की मानें तो शीतकालीन सत्र के तीन हफ्ते में प्रधानमंत्री सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को सत्र की कार्यवाही में शामिल हुए थे। उसके बाद से एक भी दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। संसद के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उप्र में कई जनसभाएं कीं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड और गोवा में भी चुनावी जनसभा की। यानी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्यों का दौरा करने में

लोकसभा की सीटें बढ़ाने की सियासी चर्चाएं

देश की संसद की नई इमारत बन रही है, जिसमें पहले से ज्यादा सांसदों के बैठने की जगह है, सिर्फ इस आधार पर सियासी चर्चाओं ने जन्म ले लिया है कि क्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी? सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार इसका होमवर्क कर चुकी है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा सीटों की संख्या तय करने का आधार आबादी होगी। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। इस प्रक्रिया से देश में क्षेत्रीय असंतुलन आना तय है। विशेष सूत्रों की मानें तो हिंदी बैल्ट यानी उत्तर के राज्यों में सांसदों की सीटें बढ़ेंगी जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में सांसदों की सीटें बढ़ने की बजाय घट जाएंगी। वहीं बजट का आवंटन भी सांसदों की संख्या के हिसाब से होगा। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह काम आसान नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है! सियासी जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार अगर ये दांव चलती है तो इसकी वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य पिछड़ जाएंगे। पिछले दिनों दक्षिण भारत के सांसदों ने इसे लेकर चिंता भी जताई थी और उन्होंने आबादी के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रयास का विरोध करने का फैसला किया था।

ही व्यस्त रहे। वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी ही सदन से गायब रहे तो उनके साथ ही उनकी पार्टी के सांसद भी सदन से नदारद रहे। प्रश्न पूछकर भी भाजपा सांसद सदन से गैरहाजिर रहे तो कई बार मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी सदन में मौजूद रहने की जरूरत नहीं समझी। आपको ध्यान दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र के दौरान पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों को चेतावनी भी दी कि, 'वे खुद को बदलें नहीं तो बदल दिए जाएंगे' तब भी सांसदों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

संसद की गरिमा को लेकर 'माननीय' कितने गंभीर हैं इसकी बानगी यह है कि संसद के इस सत्र में जिस दिन कोरोना पर चर्चा होनी थी उस दिन चर्चा शुरू कराने के लिए कोरम पूरा नहीं हो रहा था। बाद में कोरम पूरा हुआ तो चर्चा शुरू हुई। इसी तरह आखिरी हफ्ते के पहले दिन सवाल पूछकर 14 सांसद नदारद थे। इस दिन सदन में 20 तारांकित प्रश्न थे और सबका मौखिक जवाब दिया जाना था लेकिन पूरक प्रश्न पूछने के लिए जिन सांसदों ने अपने नाम दिए थे उनमें से 14 सांसद गायब थे। बड़े मजे की बात यह है कि इनमें से 9 सांसद भाजपा के थे। इससे भी मजे की बात यह है कि लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह भी इनमें से एक थे। मतलब जिनकी जिम्मेदारी सदन में सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की थी वे खुद मौजूद नहीं थे। हालांकि तुरंत ही वे भागकर पहुंचे लेकिन तब तक उनका सवाल निकल गया था और स्पीकर ने उनको मौका नहीं दिया। इसी सत्र में यह भी हुआ कि राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये सदन का अपमान माना जाता है।

इन सबके साथ ही सियासी गलियारों में एक रोचक चर्चा यह है कि चुनावों को देखते हुए संसद का कैलेंडर तय किया जाना चाहिए। क्योंकि पार्टियों (खासकर भाजपा) के द्वारा चुनाव प्रचार में सांसदों की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो वो संसद में कैसे पहुंचेंगे? ध्यान रहे संसद के पिछले सत्र में भी इसी तरह हुआ था। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव चल रहे थे और प्रधानमंत्री सहित सत्तापक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद, नेता इन चुनावों में अपने को झोंके हुए थे। इसलिए सभी सांसदों ने मिलकर संसद सत्र जल्दी खत्म करने का आग्रह किया, जिसकी वजह से सत्र दो हफ्ते पहले खत्म कर दिया गया था।

आपको बता दें, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था और 8 अप्रैल तक चलना था लेकिन पार्टियों के आग्रह पर इसे दो हफ्ते पहले 25 मार्च को ही खत्म कर दिया गया। अब शीतकालीन सत्र में आने वाले उप्र सहित 5 राज्यों के चुनावों में सांसदों की प्रचार में ड्यूटी लगी हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि इसलिए अब समय आ गया है कि राज्यों में होने वाले चुनावों के हिसाब से सत्र का कैलेंडर बने ताकि सांसद प्रचार करने का ज्यादा जरूरी काम कर सकें।

भ्रष्टाचार हमारे समाज की ऐसी ही बीमारी है। पिछले 7 साल से इसका इलाज शुरू हुआ है। समय तो लग रहा है। रोगियों का कष्ट भी बढ़ रहा है। यह इसलिए हो पा रहा है कि गंगोत्री पारदर्शी है। समस्या उसके नीचे की है। भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं पूरी ताकत से लड़ रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए समय-समय पर नई-नई दवाओं का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे वातावरण में कई प्रश्न हैं, जिनके उत्तर की तलाश है। देश के एक वर्ग को ईमानदारी से इतना परहेज क्यों हैं या इसे यूं कहें कि भ्रष्टाचार से इतना प्रेम क्यों है? नोटबंदी, जीएसटी, बेनामी संपत्ति कानून जैसे भ्रष्टाचार रोकने के तमाम उपायों का विरोध हो रहा है। इस कड़ी में अब आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का मुद्दा जुड़ गया है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल की बात शुरू होते ही विपक्षी दलों को परेशानी क्यों होती है? खासतौर से कांग्रेस को।

विरोध की ओछी राजनीति

देश में विरोध की ओछी राजनीति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की और राफेल के मुद्दे पर चौकीदार चोर का नारा लगवाया। लोगों ने उसे एक कान से भी नहीं सुना। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों बोफोर्स के मुद्दे पर पूरे देश ने राजीव गांधी के बारे में वह नारा लगाया और क्यों मोदी के बारे में ऐसी बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं? भ्रष्टाचार बुरी चीज है, नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें अपने भाषणों में सभी नेता करते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर ही अपने वैभव का महल खड़ा किया है। कई लोग तो कार्रवाई के डर से देश छोड़कर बाहर ही बस गए हैं। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे जो लोग कानून को धता बताकर भाग गए, उन्हें वापस लाने का सारा इंतजाम हो चुका है। अब सरकारी बैंक से कर्ज लेकर प्राइवेट जेट खरीदने का समय चला गया है, क्योंकि जो खाता नहीं है, वह खाने भी नहीं देता है। यही सबसे विकट समस्या है कि कैसे इस न खाने न खिलाने वाले से छुटकारा मिले और खाने-खिलाने के पुराने दिन बहुरें।

चुनाव सुधार एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। बोगस वोटर और बोगस वोटिंग भारतीय चुनाव प्रक्रिया की बहुत पुरानी समस्या है। साल 2018 में चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रीय दल और करीब 34 क्षेत्रीय दलों के नेताओं की एक राय से मांग थी कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए। इससे बोगस वोटर की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर 2019 में अदालत का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सरकार के इस फैसले को सही ठहराया, बल्कि कहा कि भविष्य में सरकार को मतदाता सूची को आधार से जोड़ने पर विचार करना चाहिए। अब ऐसा हो रहा है तो विपक्ष को ऐतराज है।

दरअसल विपक्ष को हर उस काम से ऐतराज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करती है। उसे उस काम के गुण-दोष से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 7 साल से विरोधी पक्ष का अर्थ हो गया है, जो आंख बंद करके सतत् विरोध करे। संसद में विधेयक पेश हुआ तो उस पर चर्चा के लिए विपक्षी दल तैयार नहीं। बिना चर्चा के पास हो जाए तो यह सत्तारूढ़ दल की तानाशाही है। इस विधेयक पर संसद की विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति विचार कर चुकी है। वहां समस्या नहीं थी। पास हो गया तो समस्या है। पनामा पेपर्स में जब बालीवुड और उद्योगपतियों के नाम आए तो आरोप लगा कि सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही? जरूर मिलीभगत है। जांच शुरू हुई तो कपड़े फाड़ रहे हैं कि यह तो राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है।

● इन्द्र कुमार

उप्र में चलेगा भूपेश मॉडल

भाजपा शासनकाल में डॉ. रमन सिंह चाऊर वाले बाबा के नाम से प्रख्यात थे, और दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में भिलाई और रायपुर सहित कई नगर निगम चुनाव में भाजपा के मंसूबे पर पानी फेरते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रहते हुए बड़े ही हैरतअंगेज अंदाज में चुनाव जीता था, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपनी राजनीतिक हैसियत व रणनीति का लोहा मनवाया था।

नगरीय निकाय चुनाव में मिले ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि भूपेश बघेल ऐसे देदिव्यमान नक्षत्र हैं जो राजनीति के आसमान पर फिर से पूरे देश में कांग्रेस का उदय करने की क्षमता रखते हैं। कांग्रेस हाईकमान को भूपेश बघेल पर पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में वापसी में सबसे बड़ा योगदान होगा। जिसके लिए देशभर में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की शुरूआत हो चुकी है। जिसके सहारे कांग्रेस को देशभर में फिर से स्थापित करने में मदद मिलेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने भूपेश बघेल के प्रति विश्वास किया और बंपर समर्थन देकर पंजे पर मुहर लगाकर ऐतिहासिक जीत के साथ सारे रिकार्ड तोड़ दिए।

उसी रिकार्ड को जनता ने निकाय चुनाव में फिर से दोहराया है। 15 में से 14 निकाय जनता ने कांग्रेस की झोली में डालकर भूपेश बघेल के विकास मॉडल पर मुहर लगा दी है। भाजपा का साम्प्रदायिकता कार्ड कवर्धा मॉडल को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और भूपेश बघेल के विकास मॉडल पर भरोसा दिखाया। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 2004 से 2018 तक हुए नगरीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ ही जनादेश मिलता आया है। पर भूपेश बघेल ने इस परंपरा को तोड़ दिया है वहीं भाजपा ने कद्दावर नेताओ की फौज खड़ी कर दी थी। 15 दिन से एक ही स्थान पर भाजपा नेता बिरगांव के एक वार्ड में डेरा जमाए हुए भी थे, लेकिन जनता ने सर्वाधिक वोट उसी वार्ड के प्रत्याशी को देकर बता दिया कि चलेगा तो सिर्फ भूपेश मॉडल ही।

भाजपा के चाणक्य के मिथक को भूपेश बघेल ने तोड़ दिया। भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी भी छत्तीसगढ़ में डेरा जमाए रहे एक नगरीय निकाय में चार-चार लोगों को प्रभार दिया गया था जबकि भूपेश बघेल ने उस नगरीय निकाय क्षेत्र में क्षेत्र के विधायक या संगठन के लोगों को ही यह कार्य सौंपा था। 2004 से 2018 के दौर की बात करें तो कांग्रेस में अंतर्विरोध भी कम नहीं था बड़े-बड़े नेताओं का अपना गुट था, प्रथम पंक्ति के नेताओ की भी कमी थी उसके बावजूद भूपेश बघेल ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाते हुए कई नगर निगम और नगर पालिका सहित नगर पंचायतों में कब्जा जमाया था, जिसे उन्होंने आज भी कायम रखा, उस मिथक को ही तोड़ दिया जिसमें ये कहा जाता था कि सत्ता के खिलाफ जनादेश मिलता ही है। भूपेश सरकार का सीधा जनता से रिश्ता होना ही भूपेश बघेल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 2018 में कांग्रेस को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीन चौथाई बहुमत के साथ बंपर सफलता मिली थी।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही भूपेश बघेल ने चुनावी घोषणाओं पर अमल शुरू कर दिया। शपथ लेते ही किसानों की कर्ज माफी के आदेश पर हस्ताक्षर कर भूपेश सरकार ने इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ के काबिल नेताओं को दिल्ली की राजनीति में प्रभावी स्थान भी मिला था। रविशंकर शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, अरविंद नेताम, शिवेंद्र बहादुर सिंह जैसे नेताओ की दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ थी। उस परंपरा को छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल ने कायम रखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस हाईकमान ने असम चुनाव के बाद उप्र जैसे बड़े राज्य में होने वाले चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक बनाकर गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ काम करने का अवसर दिया है। भाजपा और उनके अनुषांगिक संस्थाओं ने छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को नहीं समझा। प्रदेश में कवर्धा घटना को काफी हवा दी गई, यहां के माहौल को साम्प्रदायिक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ की जनता पूरे देश में भोली-भाली जनता के रूप में जानी व पहचानी जाती है। यहां की जनता ने हिंदू-मुस्लिम पर ध्यान न देकर भूपेश सरकार के विकास कार्यों को ध्यान में रखकर वोट किया। सर्वधर्म समभाव की भावना वाली भूपेश सरकार ने सीधा प्रगाढ़ रिश्ता जनता से बनाया और 15 में से 14 निकाय को अपने झोली में डाल लिया। आज गांवों और शहरों में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के जरिए हो रही समृद्धि और खुशहाली को पूरा देश देखकर भूपेश मॉडल का अनुसरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ कर चुके हैं।

गौरतलब है कि भूपेश बघेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग खुद कर तीन सालों में बेमिसाल उपलब्धियां हासिल कीं। छत्तीसगढ़ में बह रही विकास की गंगा को देख जनता ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर भरोसा कर 2018 में दिए जनादेश को दोहरा दिया है। भूपेश बघेल ने आज साबित कर दिया कि भूपेश है तो भरोसा है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

दिग्गजों के घर में भी हारी भाजपा

यह चुनाव भाजपा के लिए कई चुनौती खड़ी कर गया है। भाजपा के दिग्गजों के घर में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह प्रेमनगर नगर पंचायत के चुनाव में सक्रिय रहीं, लेकिन भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस को एकतरफा बहुमत मिला है। राजनांदगांव नगर निगम के एक वार्ड में हुए उपचुनाव में भाजपा हार गई। यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ओर शहर जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के कुरुद विधानसभा में भी भाजपा हार गई। इसी तरह पीएचई मंत्री गुरु रुद्रकुमार अपने विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका जामुल में पार्टी को बढ़त नहीं दिला सके।

नंबरों से छेड़छाड़

महाराष्ट्र में कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक्स और भ्रष्टाचार के मुद्दे ने, विधानसभा के चालू सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया है और इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन, जहां राज्य सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, वहीं, इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में तीन सरकारी परीक्षाएं, पेपर लीक्स और नंबरों से कथित छेड़छाड़ के चलते, विवादों में घिर गई हैं। ये परीक्षाएं हैं अक्टूबर में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ग्रुप सी और डी परीक्षा, नवंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) और दिसंबर में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के लिए भर्ती परीक्षाएं।

पुणे साइबर पुलिस फिलहाल इन तीनों परीक्षाओं की जांच कर रही है, और उसने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद् (एमएससीई) आयुक्त तुकाराम सूपे और सुखदेव देरे शामिल हैं, जो 2017 तक एमएससीई आयुक्त थे। पुलिस ने एक निजी कंपनी जीए सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और अन्य कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसे 2021 में टेट और म्हाडा परीक्षाएं कराने का ठेका दिया गया था। जीए सॉफ्टवेयर को राज्य की पूर्व फडणवीस सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, लेकिन इस साल तुकाराम सूपे ने उसकी स्थिति पूरी तरह सामान्य कर दी। भाजपा अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है।

इधर परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते विवाद बना हुआ है, उधर उम्मीदवारों का मानना है कि उनका भविष्य अधर में लटक गया है। डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन (डीटीईडी) छात्र संघ अध्यक्ष संतोष मगर ने कहा, 'कुछ छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हो जाने के बाद, परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे छात्र कहते हैं कि हमने कड़ी मेहनत की है, लेकिन हो सकता है कि हम दोबारा परीक्षा पास न कर पाएं।'

महाराष्ट्र नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा- मुझे लगता है कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के तार, ऊपर मंत्रालय (सरकारी सत्ता की कुर्सी) तक जुड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र से बाहर फडणवीस ने कहा, 'अगर भर्ती घोटाले के तार मंत्रालय से जुड़े हैं, तो राज्य पुलिस अपनी जांच में निष्पक्ष नहीं रह पाएगी, और यही कारण है कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।' लेकिन, राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसने दावा किया है कि अनियमितताओं को वास्तव में उस समय से जोड़ा जा सकता है, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। सरकार ने अब निष्क्रिय हो चुके महापरीक्षा पोर्टल पर उंगली उठाई है, जिसे फडणवीस सरकार ने 2016 में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए शुरू किया था। ये पोर्टल भी अनियमितताओं के चलते विवादों में घिरा था, और पिछले साल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद उसे खत्म कर दिया गया था। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि इस साल भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं से निपटने के लिए वो आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बताया, 'सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे की जांच कर रही है, और उसने इन सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है।' इशारों-इशारों में उन्होंने कहा कि जो कंपनियां ये परीक्षाएं करा रही हैं, उन्हें लाने के लिए फडणवीस सरकार ही जिम्मेवार थी। उन्होंने महाराष्ट्र परीक्षा घोटाले और मप्र के व्यापमं घोटाले के बीच समानताओं की भी बात की, जहां उम्मीदवारों ने कथित रूप से रिश्वत देकर, नौकरियां और कॉलेज सीटें हासिल कर लीं थीं। भाजपा ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। लाखों छात्र रद्द की गईं या गड़बड़ी युक्त परीक्षाओं के बाद चकराए हुए हैं। 12 दिसंबर तक राज्य आवास मंत्री जितेंद्र अवहाद ने रात 1:24 बजे अपने ट्विटर पर ऐलान किया, कि म्हाडा परीक्षा जो उस सुबह आयोजित होनी थी, पेपर लीक होने के सबूत मिलने के बाद रद्द कर दी गई है। छात्रों ने उन्हें ट्विटर पर सीधे जवाब देते हुए, अपना रोष व्यक्त किया चूंकि वो अपने गृह क्षेत्रों से लंबा सफर तय करके परीक्षा केंद्रों तक आए थे। उसी दिन बसों की हड़ताल ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं थीं।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ग्रुप सी और डी के लिए भर्ती परीक्षाएं भी विवादों में घिरीं थीं। ये परीक्षाएं जो मूल रूप से सितंबर में होनी थीं, आखिर में 24 और 31 अक्टूबर को कराई गईं, चूंकि परीक्षा की जिम्मेदार निजी कंपनी ने कथित तौर पर समय रहते पर्याप्त तैयारियां नहीं की थीं। लेकिन, छात्रों का आरोप है, कि अंत में जब ये इम्तिहान कराए गए, तो इनमें साफतौर पर गड़बड़ियां थीं। बताया जाता है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कमजोर थी, और पेपर भी कथित तौर पर लीक हुआ था। एक नांदेड़ निवासी तानाजी तेलंगे (जो स्वास्थ्य विभाग की ग्रुप सी परीक्षा में बैठे थे) ने बताया कि उन्हें दो हॉल टिकट्स मिले थे। उन्होंने पूछा, 'दो हॉल टिकट्स देखकर में दुविधा में पड़ गया। उससे भी खराब ये कि वो टिकट मुझे पिछली रात 10 बजे मिले थे। इतना कनफ्यूजन था। जब हमारे यहां एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) है, तो ऐसी निजी कंपनियों की वैसे भी क्या जरूरत है?'

● **बिन्दु माथुर**

निजी कंपनियां ठीक से नहीं कर रही परीक्षाओं का प्रबंध

स्वास्थ्य विभाग और म्हाडा परीक्षाओं के एक उम्मीदवार मंगेश देशमुख ने भी कहा कि निजी कंपनियां परीक्षाओं का ठीक से प्रबंध नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने तीन एमपीएससी परीक्षाएं दी हैं, उनमें पुलिस मौजूद होती है जो सुरक्षा पर नजर रखती है। यहां मुझे कोई नजर नहीं आया। किसी ने मेरी पहचान नहीं पूछी। डर ये था कि किसी की जगह भी, कोई दूसरा व्यक्ति इम्तिहान देने जा सकता था।' 30 वर्षीय संजय चव्हाण ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के दो साल सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए लगातार पढ़ाई में लगा दिए थे। सबसे नजदीकी शहर औरंगाबाद से 150 किलोमीटर दूर एक गांव के निवासी संजय, मुश्किल से अपनी गुजर-बसर कर पा रहे हैं। उनका किसान परिवार कर्जों से जूझ रहा है, और वो भी कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरी की सदस्यता और किताबों के खर्च के लिए संजय भी अपने दोस्तों से पैसा उधार लेते हैं। नवंबर में जब वो टेट की परीक्षा देने गए तो उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, भले ही औरंगाबाद के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए, 2,000 रुपए खर्च करने पड़े हों।

राजपूताना शक्ति का शंखनाद

राजस्थान में चुनाव अभी पौने दो साल के बाद और लोकसभा चुनाव में लगभग ढाई साल बाद है। लेकिन राजपूत समाज ने अपनी शक्ति का शंखनाद कर लिया। राजस्थान के सबसे विराट कार्यक्रमों में शामिल राजपूत सम्मेलन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रदेश के ज्ञात इतिहास में राजपूतों की इतनी बड़ी रैली जयपुर में इससे पहले कभी नहीं हुई। खासकर क्षत्रियों के इतने बड़े कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में क्षत्राणियां भी इससे पहले कभी नहीं दिखी। पूरे प्रदेश सहित देश के विभिन्न प्रदेशों से इतने राजपूत जयपुर पहुंचे कि भवानी निकेतन का ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। वैसे तो इस तरह की रैलियों के निहितार्थ केवल राजनीतिक ही हुआ करते हैं, और प्रकट तौर पर भले ही यह रैली सिर्फ सामाजिक ताकत दिखाने की मंशा से हुई हो, मगर इसके राजनीतिक मायने न निकाले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता।

रजवाड़ी रियासतों के रेतीले राजस्थान में राजपूत सदा से रसूखदार रहे हैं, लेकिन भैरोंसिंह शेखावत और कल्याण सिंह कालवी के स्वर्ग सिधारने के बाद शिखर की उस राजनीतिक शून्यता को भरना इसलिए भी जरूरी लगने लगा है, क्योंकि बीते कुछ सालों में राजनीति और सरकार दोनों ही राजपूतों की पकड़ से कुछ छूटती सी जा रही हैं। सो, पूरे राजस्थान में चर्चा है कि आखिर यह रैली किसने करवाई और इतनी भीड़ क्यों व कैसे आई। हालांकि जानकारों के पास इसकी सूचनाएं और जानकारियां तो हैं, लेकिन इसके प्रमाण मिलना बाकी है, पर राजस्थान की राजनीति में 22 दिसंबर 2021 की राजपूतों की अब तक की यह सबसे बड़ी रैली एक रहस्य को समेटे हुए सबके सामने खड़ी हैं, जिसका हल सुलझना, समझना व संज्ञान में लेना राजनीति व राजनेताओं को जरूरी लगने लगा है।

कोई चाहे कितना भी कहे कि यह शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी राजनीति तो राजनीति होती है, वह कहीं से भी अपनी चमक दिखा ही देती है। फिर जब मंच पर केसरिया साफे में सारे नेता ही सजे हुए बैठे हों, तो राजनीति के रास्ते और आसान हो जाते हैं। आमतौर पर राजपूतों के तेवर आक्रामक माने जाते हैं, फिर भी यह रैली भले ही बेहद अनुशासित व शांत रही। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के लिए यह संदेश साफ था कि राजस्थान की धरती पर राजपूतों को हल्का मानकर राजनीति करने का छल अब नहीं चलेगा। और यह भी कि चुनावों में उनके सहयोग व समर्थन के बिना किसी भी राजनीतिक दल को कोई बहुत चमकदार नतीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान में राजपूत समुदाय की आबादी भले ही 7 से 8 फीसदी के बीच है, लेकिन 20 फीसदी विधानसभा सीटों पर राजपूत समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है। सन् 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में राजपूतों की जनसंख्या 37.4 लाख थी, जिसके बारे में अब राजपूतों का दावा है कि राजस्थान में कुल 45 से 50 लाख लाख राजपूत हैं।

मतलब राजस्थान की कुल जनसंख्या में 7 से 8 प्रतिशत राजपूत हैं। आजादी के बाद सन् 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कुल 160 सीटों में 54 सीटों पर राजपूत विधायक थे। पिछली बार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 26 विधायक थे और 2018 के चुनाव में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में यह संख्या 21 रह गई हैं। दरअसल, राजपूत समाज सिर्फ अपने वोट बैंक की वजह से ही नहीं बल्कि चुनाव में अन्य जातियों पर भी तगड़ा असर रखने और वोट दिलवाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। राजपूतों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए मौका निकाला अपने सामाजिक संगठन श्री क्षत्रिय युवा संघ के 75वें स्थापना दिन का, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी अनुशासित सामाजिक एकजुटता दिखाकर स्पष्ट ताकत का संदेश दे दिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी शुभकामनाएं इस रैली को प्रेषित की, तो राजस्थान के सभी बड़े-बड़े राजपूत नेताओं सहित जयपुर के कई नेता अपनी-अपनी विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद शुद्ध सामाजिक धारा का बहाव देखने पहुंचे थे। रैली के मंच से आजाद भारत की एकता व अखंडता में राजपूतों के योगदान की ताकत को याद दिलाते हुए राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने जब कहा कि राजपूतों का यह इतिहास है कि देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजपूतों ने अपने राजपाट सौंप दिए थे, तो संदेश साफ था कि लोकतंत्र में भी राजपूतों की हिस्सेदारी मजबूत ही रहनी चाहिए। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि क्षत्रिय वास्तव में एक संस्कार है, और राजपूत अपने विचार व व्यवहार से सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज है। हालांकि शेखावत ने यह कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचारियावास ने नसीहत दे डाली कि अगड़ी जातियों के आरक्षण के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो सराहनीय कार्य किया है, वही काम केंद्र को भी करना चाहिए। तो, क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह की इस घोषणा ने राजपूत समाज के दिल की हालत जाहिर कर दी कि राजपूत अपना गुस्सा पीना और सहना सीखें। मतलब कि गुस्सा तो है, लेकिन उसे रोकना भी है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

राजनीतिक पुनरुत्थान और सामाजिक एकता का संदेश

माना जा रहा है कि बदले हुए माहौल में अपनी सियासी ताकत जुटाने के लिए राजपूतों की अब तक की यह सबसे बड़ी पहल है। वैसे तो निश्चित रूप से इस रैली का कोई साफ तौर पर राजनीतिक संदेश नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि इसके पीछे कोई सियासत अवश्य है या फिर राजपूत समाज ने अपनी मजबूत पहचान की पुनर्स्थापना के लिए और अपनी ताकत के लिए एकजुटता दिखाई है। तो, सत्ता में अपने राजनीतिक पुनरुत्थान और सामाजिक एकता का संदेश देने में तो यह रैली सफल रही, फिर भी देखते हैं, राजस्थान की राजनीति में यह रैली आने वाले वक्त में क्या असर दिखाती है। वैसे, राजपूतों की ताकत के बारे में बहुत सारे किस्से कहे जाते हैं, ज्यादातर सच और कुछ कल्पित भी, लेकिन सारे ही किस्सों में उनकी बहादुरी का जिक्र जरूर होता है। सो, इस रैली को भी उनकी बहादुरी के प्रदर्शन के नजरिए से देखना पाप नहीं होगा। फिर, राजपूतों ने भले ही रैली के अपने इस शक्ति प्रदर्शन को सामाजिक एकता का नाम दिया हो, लेकिन राजपूतों की इस रैली ने जाट, मीणा व गुर्जर संगठनों को भी जातीय ताकत के प्रदर्शन का रास्ता जरूर दिखा दिया है। राजस्थान गवाह है कि राजपूत सदा-सदा से राजपाट के केंद्र में रहे हैं, सो इस रैली से राजनेता हैरान हैं और राजनीति परेशान है। लेकिन राजनीति और राजनेताओं के इस हाल से राजपूत खुश हैं, क्योंकि राजनीति आखिर किसी दूसरे को परेशानी में डालने का ही तो दूसरा नाम है। फिर राजपूतों से ज्यादा राजनीति कोई और क्या जानेगा?

अखिलेश की तीन रणनीति

अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी (सपा) उप्र में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरकर आई है। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक सत्ता की गद्दी से उतारने के लिए यह पार्टी तीन सूत्रीय रणनीति पर काम कर रही है। सपा की रणनीति का पहला सूत्र ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करना है जो चुनाव जीत सकें और भरोसे के हों। इसके लिए तीन कसौटियां तय की गई हैं। विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार की लोकप्रियता, क्षेत्र के मतदाताओं में जातियों का समीकरण और पार्टी के प्रति निष्ठा। अखिलेश यादव ने यह रणनीति मप्र और कर्नाटक में चुनाव के बाद हुए सियासी खेल के मद्देनजर अपनाया है, जहां भाजपा ने विपक्षी विधायकों का सामूहिक दल-बदल कराकर अपनी सरकार बना ली थी। सपा में अब उम्मीदवारों की निष्ठा केवल पार्टी में से नहीं मापी जा रही है बल्कि अखिलेश यादव के प्रति भी निष्ठा होनी चाहिए। इस निष्ठा वाली कसौटी ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे नेताओं को परेशान कर दिया है, जिन्होंने अपनी जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) बनाई है और सपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। लंबे समय से मुलायम सिंह यादव के करीबी होने के बावजूद राजा भैया अखिलेश यादव का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अगस्त में बताया था कि वे ऐसे उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए हैदराबाद की दो सर्वे एजेंसियों की सेवाएं ले रहे हैं। उम्मीदवारी की जांच करने के लिए पार्टी ने उनसे अर्जी और अपना बायोडाटा भेजने को कहा है। लेकिन वर्तमान विधायकों से ऐसी मांग नहीं की गई है, यानी उनमें से ज्यादातर को दोबारा टिकट दिया जा सकता है।

सपा की रणनीति का दूसरा सबसे अहम सूत्र है अति पिछड़ी जातियों (मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स) के मतदाताओं को अपने पक्ष में करना। है क्योंकि उप्र में किसी पार्टी की जीत पक्की कराने में इन जातियों के मतदाताओं का बड़ा हाथ होता है क्योंकि वे किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं। ऊंची जातियों के मतदाता भाजपा के, जाटव-हरिजन बसपा के, और यादव सपा के पक्के वोटर्स माने जाते हैं। पहले, एमबीसी मतदाता बसपा के मजबूत समर्थक माने जाते थे, मगर 2014 के बाद वे भाजपा के साथ हो गए। इस बार सपा उन्हें रिझाने की पूरी कोशिश में जुटी है। इसके लिए सपा ने तीन रणनीति बनाई है। पहली, यादव और मुसलमान ही पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष और महासचिव हुआ करते थे। एक पद पर कोई यादव नेता होता, तो दूसरे पद पर मुसलमान नेता को दिया जाता था। फिर बताया गया है कि अति पिछड़ी जाति के नेताओं को जगह देने के लिए अखिलेश यादव ने यह नीति बदल दी है। सपा ने दूसरी रणनीति छोटी 'यात्राएं' निकालने की बनाई है। प्रदेश में नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव अभियान शुरू करने से बहुत पहले ही सपा के संजय चौहान, नरेश उत्तम पटेल, इंद्रजीत सरोज, मिठाईलाल भारती, केशव देव मौर्य जैसे नेताओं ने प्रदेश के कई हिस्सों में यात्राओं का आयोजन शुरू कर दिया था। अंतिम रणनीति पिछले दो दशकों में उभरीं अति पिछड़ी जातियों में उभरी छोटी-छोटी पार्टियों से चुनावी गठबंधन करने की है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन इस चुनावी रणनीति का ही एक उदाहरण है।

सपा की रणनीति का तीसरा सूत्र है- ज्यादा से ज्यादा आरक्षित सीटों को जीतना। पार्टी इन सीटों पर पहले इसलिए ध्यान नहीं देती थी क्योंकि ऐसी सीटें बसपा के मजबूत गढ़ होती थी। बसपा के कमजोर पड़ते ही भाजपा उन पर मजबूत दावेदार बन गई। वास्तव में, आरक्षित सीटों को जीतने के मामले में भाजपा ने भारी बढ़त ले ली। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 85 में से 75 आरक्षित सीटें जीत ली थी। अब ज्यादा से ज्यादा इन सीटों को जीतने के लिए सपा, बसपा के प्रभावशाली नेताओं का 'आयात' कर रही है। आज तक सपा ऐसे कई बसपा नेताओं को अपने पाले में ले आई है। इनमें प्रमुख नाम हैं- मिठाई लाल भारती, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, तिलक चंद्र अहिरवार, केके गौतम, सर्वेश आंबेडकर, महेश आर्य, योगेश वर्मा, अजय पाल सिंह जाटव, वीर सिंह जाटव, फेरान लाल अहिरवार, रमेश गौतम, विद्या चौधरी, अनिल अहिरवार, सीएल पासी, आदि। ये नेता बसपा में विधायक, सांसद, मंत्री और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी रह चुके हैं। सपा ने इन नेताओं को आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ाने की योजना बनाई है। पहले, सपा इन सीटों पर अधिकतर गैर-जाटव-हरिजन उम्मीदवारों को खड़ा किया करती थी। लेकिन अब भाजपा ने यह रणनीति अपना ली है। इसलिए सपा इन सीटों पर जाटव-हरिजन उम्मीदवारों को खड़ा करने पर मजबूर हो गई है। बसपा पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए इसके नेता अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए पाला बदलने को बेताब हैं। इसके साथ ही सपा ने मिठाई लाल भारती के नेतृत्व में बाबासाहब अम्बेडकर वाहिनी का भी गठन किया है जिसकी मदद से अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ सके।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

सपा की रणनीति के लिए चुनौतियां

सपा को अपने उपरोक्त रणनीति के लिए तीन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली यह कि पार्टी संगठन कभी कैडर आधारित नहीं रहा, वह संरक्षण और नेटवर्क वाली पार्टी रही है। मुलायम सिंह और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव का स्थानीय नेताओं का एक बड़ा नेटवर्क था। ऐसा अखिलेश यादव के साथ नहीं है। दूसरे, भाजपा की तरह सपा के पास हर चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के जातीय और सामुदायिक समीकरण का विस्तृत डाटा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से उसे व्यावहारिक तरीके से टिकट वितरण और चुनावी रणनीति बनाने में दिक्कत होती है। तीसरे, अखिलेश यादव की पिछली सरकार के कुछ फैसले सपा के लिए भारी पड़ रहे हैं, खासकर एससी-एसटी कर्मचारियों को पदावनत करने और उनके कल्याण की विशेष योजनाओं को बंद करने का फैसला। बसपा के जाटव-हरिजन मतदाताओं को नुकसान करने के लिए अखिलेश यादव ने 2012 में सत्ता में आने के बाद एससी-एसटी कर्मचारियों को पदावनत करने और उनके कल्याण की विशेष योजनाओं को बंद करने का फैसला किया था। लेकिन इस फैसले ने गैर-जाटव-हरिजन एससी-एसटी मतदाताओं को भी नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने जातीय प्रतिद्वंद्विता के चलते सपा को वोट दिया था। सो, वे भाजपा की तरफ मुड़ गए। यह मुद्दा एससी-एसटी बुद्धिजीवियों की उस बैठक में भी उठा, जिसे अखिलेश यादव ने आयोजित किया था। जिस पर अखिलेश यादव ने यह वादा किया कि अगर वे सत्ता में आए तो 'सुधार के उपाय' करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, यह नहीं बताया?

बिहार में टकराव

बिहार में बहार है, 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही ये नारा बदल चुका है, अब तो लगता है जैसे नारा होना चाहिए- बिहार में बवाल है। नौबत ये आ चुकी है कि एनडीए के भीतर संघर्ष का नया दौर बिहार में शुरू हो चुका है। न जाने ऐसे कितने मुद्दे हो गए हैं जिनको लेकर भाजपा और जदयू आमने सामने होकर दो-दो हाथ करने लगे हैं। अभी संसद में बिहार सरकार के कामकाज को लेकर भाजपा और जदयू के सांसद आपस में भिड़े ही, जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला तो मुकाबले में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह खड़े हो गए। हालांकि, ललन सिंह का भी लहजा शिकायती ही था, तेवर भी कोई नरम नहीं थे।

हरियाणा की तरह खुले में नमाज से लेकर बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की डिमांड तक एक जैसी तकरार देखने को मिल रही है और मौका देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़े ही सख्त लहजे में रिएक्ट कर रहे हैं। यही नहीं भाजपा को घेरने वाले जातीय जनगणना के मुद्दे पर तो लगता है जैसे वो विपक्ष से हाथ मिला चुके हों। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के बयानों से भी लगता है जैसे भाजपा से पूछे बगैर वो किसी खास मुद्दे पर अकेले फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन भाजपा कोटे से बने मंत्री तो कहने भर के रह गए हैं। नीतीश कुमार के अफसरों के आगे भाजपा के मंत्री मन मसोस कर रह जाते हैं। क्योंकि आदेश मानने की कौन कहे, अफसर तो जैसे भाजपा के मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते।

बिहार की उपमुख्यमंत्री रेनू देवी को लेकर नीतीश कुमार का जो रिएक्शन आया है, वो तो काफी अजीब लगता है। क्या नीतीश कुमार किसी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और फिर से एनडीए छोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? आखिर बिहार में ये कौन सी बहार आई है जो बवाल मचाए हुए है?

हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें विकास के तमाम पैमानों पर फिसड्डी बताया गया था। रिपोर्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीतीश सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति आयोग को पत्र लिख दिया। पत्र के जरिए बिहार को विशेष दर्जे वाली नीतीश कुमार की पुरानी मांग दोहराई गई है। लेकिन जदयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव की बात भाजपा कोटे से उपमुख्यमंत्री रेनू देवी काट देती हैं और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होती। रेनू देवी को लेकर नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है, वैसा पहले भी कम ही सुनने को मिला है। चुनावों के दौरान होने वाली बयानबाजी को छोड़े दें तो भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से तो नीतीश कुमार के मुंह से ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली हैं।

बिहार के विशेष दर्जे को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री रेनू देवी खुद ही पूछने लगती हैं, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? बिहार में जो बड़े-बड़े पुल पुलिया और सड़क बन रहे हैं, उसका पैसा तो केंद्र सरकार ही दे रही है... विशेष दर्जा कहां महत्व रखता है... विशेष दर्जे के तहत जो पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार हमें दे रही है। रेनू देवी की बातें सुनकर तो लगता है जैसे नीतीश कुमार को आग लग जाती है और भड़ास निकालने का बहाना ढूंढने लगते हैं। रेनू देवी का बयान याद दिलाते ही नीतीश कुमार आपे से बाहर हो जाते हैं, उपमुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता... वो आएंगी तब हम उनसे पूछेंगे। नीति आयोग को जो पत्र लिखा गया है वो सरकार की तरफ से हैं... ये किसी मंत्री की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से लिखा गया है, उनको नहीं पता होगा तो बता देंगे।

आरजेडी छोड़कर भाजपा में आए और पिछली मोदी सरकार में मंत्री रहे राम कृपाल यादव भरी संसद में नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर देते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराए जाने वाले काम पर भाजपा सांसद का सवाल होता है, अब तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ है जबकि बाकी राज्य आगे हैं? सवाल भाजपा के सांसद पूछते हैं और जवाब भी भाजपा के वही मंत्री देते हैं जो खुद भी बिहार से आते हैं और नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं- गिरिराज सिंह। आंकड़ों के जरिए साबित करने लगते हैं कि नीतीश सरकार लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रही है। काउंटर अटैक के लिए जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार खड़े होते हैं और गिरिराज सिंह से पूछने लगते हैं कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ टारगेट पूरे करने को लेकर वो कोई मीटिंग भी किए हैं क्या? कौशलेंद्र के सवाल पर गिरिराज सिंह के जवाब के बाद जदयू अध्यक्ष ललन सिंह मोर्चा संभालते हैं, केंद्र के साथ-साथ बिहार में भी एनडीए सरकार चला रहा है। आप बिहार से हैं... मैं बिहार से हूं... आपने कभी राज्य सरकार और अधिकारियों के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए कभी बैठक बुलाई क्या? ललन सिंह के सवाल का भी गिरिराज सिंह जवाब देते हैं, लेकिन बिहार की 'तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में' वाली स्थिति की भी झलक दिखाई देती है, साफ-साफ समझ आ जाता है कि बिहार में सरकार जैसे भी चल रही हो, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।

● **विनोद बक्सरी**

भाजपा मंत्रियों की बातें अफसर सुनते नहीं

हाल ही में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने नौकरशाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। हुआ ये कि एक ही समय मंत्री जीवेश मिश्रा और पटना के डीएम की गाड़ी एक चौराहे पर पहुंची और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया। अगर सिर्फ मंत्री की गाड़ी को रोका होता तो भी शायद वो गुस्से पर काबू कर लेते, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी इसलिए रोक दी जाती है क्योंकि पटना के डीएम को रास्ता देना होता है। मंत्री का पाइंट इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि वो विधानसभा ही जा रहे होते हैं, वाकये को लेकर बवाल मच जाता है। जीवेश मिश्रा को तो सड़क पर सबके सामने हुई एक घटना को लेकर शिकायत का मौका भी मिल जाता है और जोर-शोर से वो अपनी बात उठाते हैं, लेकिन भाजपा कोटे के उनके साथी मंत्री तो बस मन मसोस कर रह जाते हैं। अनौपचारिक बातचीत में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके दिल की बात यूं ही जबान पर आ जाती है, हमारी हैसियत तो एक क्लर्क का ट्रांसफर कराने लायक भी नहीं है।

शी जिनपिंग का सपना नहीं हो पाएगा पूरा

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू सत्ता पर बड़ी तेजी से अपनी पकड़ को और मजबूत बना रहे हैं। इसके साथ ही वह चीन की बहुप्रचारित व्यापक शक्ति के प्रदर्शन में भी जुटे हैं। चीनी तिकड़में जितनी आक्रामक हो रही हैं, रणनीतिक विस्तार के लिए बीजिंग की महत्वाकांक्षाएं उतनी ही जटिल होती जा रही हैं। शी दुनिया को यही जताना चाहते हैं कि महाशक्ति के रूप में अंतत: चीन का उदय हो चुका है, परंतु दुनिया की दिलचस्पी इसमें अधिक है कि यह उभार किस प्रकार हो रहा है?

कुछ दिन पहले ही चीन ने आसियान देशों के साथ संवाद संबंधों के तीन दशक पूर्ण होने पर एक विशेष वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें शी ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को आश्वासन देने का प्रयास किया कि चीन अपने छोटे पड़ोसी देशों को कभी परेशान नहीं करेगा। सम्मेलन में उन्होंने जोर देकर कहा, 'चीन हमेशा से आसियान का अच्छा पड़ोसी, मित्र और सहयोगी था, है और रहेगा।' चीनी राष्ट्रपति यह जताने में लगे थे कि चीन आसियान की एकता और स्थायित्व का हिमायती होने के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसकी व्यापक भूमिका का समर्थन भी करता है। चूंकि चीन ने आसियान देशों को कोरोना संकट से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन और टीके उपलब्ध कराए थे, इसलिए जब उनके साथ तीस वर्षों के कूटनीतिक एवं आर्थिक रिश्तों का जश्न मनाने का मौका हो तो उस अवसर पर डराने-धमकाने जैसे मुद्दों की चर्चा बेमानी लगती है। इसके बावजूद सच यही है कि उसके सभी रिश्तों में दादागिरी-दबंगई का भाव है। आसियान देश भी छिटपुट तरीकों से उससे छुटकारे की फिराक में हैं।

आसियान नेता चीन के इस दबाव में नहीं झुके कि म्यांमार सैन्य तानाशाही के मुखिया को सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए और म्यांमार को एक गैर-राजनीतिक प्रतिनिधि भेजने पर बाध्य किया जाए। सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन की महत्ता को भी रेखांकित किया गया। इनमें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (1982) को सम्मान के साथ-साथ दक्षिण चीन सागर में मुक्त आवाजाही और उसके ऊपर से उड़ानों को अनुमति देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। यह हिंदू-प्रशांत को लेकर आसियान के नजरिए के अनुरूप ही है, जिसका एक भौगोलिक इकाई के रूप में चीन लगातार विरोध करता आया है। इस क्षेत्र में चीन को लेकर उसके कुछ निकट सहयोगियों के नरम रवैये का जमीनी स्तर पर शायद ही कुछ असर दिखे।

शी का एजेंडा उजागर हो रहा

घरेलू मोर्चे पर शी जिनपिंग एक सम्राट के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। हाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक प्रस्ताव में उनके तीसरे पंचवर्षीय कार्यकाल को औपचारिक स्वीकृति दे दी गई। उन्हें कार्ल मार्क्स और माओत्से तुंग जैसे समाजवादी विचार के दिग्गज प्रवर्तकों की पांत में रखा जा रहा है। सत्ता की ताकत से वह चीन में अपने विरोधियों को हाशिए पर धकेल रहे हैं, परंतु चीनी सीमा से बाहर उनकी शक्ति अभी भी मान्यता की प्रतीक्षा में है। यदि चीनी शक्ति का उद्देश्य निर्विवाद वैश्विक नेता के रूप में उभरना है तो पिछले कुछ समय के दौरान विभिन्न मोर्चों पर उसकी जो गतिविधियां देखने को मिली हैं, उनसे शी को अपना वैश्विक एजेंडा पूरा करना मुश्किल होगा। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन शी का एजेंडा उजागर तो हो रहा है और यह तय है कि निरंकुश ताकत उनके व्यापक लक्ष्य की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होगी।

दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता निरंतर जारी है। छल-प्रपंच से जुड़ी अपनी तिकड़मों के जरिए वह विवादित जल क्षेत्र में अपने हवा-हवाई दावों को दोहरा रहा है। उसकी इस रणनीति के खिलाफ पीड़ित देशों के पास अभी तक कोई कारगर तोड़ नहीं। विवादित क्षेत्रों में चीन सैन्य दस्तों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि इलाकों पर कब्जे के ऐसे निर्लज्ज प्रयासों के खिलाफ आसियान देशों को एक संयुक्त मोर्चा बनाना मुश्किल पड़ रहा है। जिस दिन शी कह रहे थे कि चीन छोटे पड़ोसी देशों को तंग नहीं करेगा, उससे कुछ दिन पहले ही उनके तटरक्षक दस्ते विवादित जल क्षेत्र में फिलीपींस सेना की आपूर्ति से जुड़ी नौकाओं की राह रोकने में लगे थे। वे जहाजों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे। जहां फिलीपींस ने सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया, वहीं अन्य देशों ने मौन रहना ही मुनासिब समझा।

जहां तक इस प्रकार के छद्म युद्ध की बात आती है तो चीन ताइवान के खिलाफ अपनी इस मुहिम को मुखरता से आगे बढ़ाता दिखता है। पिछले कुछ दिनों में ताइवान के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में चीनी वायुसेना के विमानों ने बार-बार घुसपैठ की है। यह इलाका ताइवान नियंत्रित प्रतास द्वीप के निकट है। यह न केवल ताइवान की रक्षा पंक्ति की परीक्षा लेने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसके माध्यम से अमेरिकी सहयोग की सीमा-रेखा को भी परखा जा रहा है। ताइवान स्ट्रेट में तनाव भड़काने के इस खतरनाक खेल में बीजिंग इस क्षेत्र में सुरक्षा साझेदार के रूप में वाशिंगटन की साख को चुनौती दे रहा है। कई देशों में कोरोना के नए प्रतिरूप ओमिक्रोन की दस्तक के साथ दुनिया को इस चीनी वायरस से मुक्ति मिलने की हाल-फिलहाल कोई राह नहीं दिख रही है। उसे देखते हुए मूल कोरोना वायरस के उद्गम को लेकर चीन की भूमिका एक बड़ी बहस का बिंदु बनी हुई है। ऐसे में कोरोना को लेकर चीन की शुरुआती प्रतिक्रिया पर एक तरह से निशाना साधते हुए अमेरिका ने ओमिक्रोन की त्वरित पहचान और दुनिया के साथ उसकी जानकारी साझा करने पर दक्षिण अफ्रीका की भूरि-भूरि प्रशंसा करने में देरी नहीं की।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की प्रतिक्रिया से यह प्रत्यक्ष साबित होता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी विज्ञानियों द्वारा ओमिक्रोन की तत्काल पहचान और वहां की सरकार द्वारा उससे संबंधित जानकारियों को तुरंत साझा करने में प्रदर्शित की गई पारदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि यह विश्व के लिए एक मिसाल बननी चाहिए। उन्होंने चीन का नाम भले न लिया, लेकिन उनका संकेत स्पष्ट था, क्योंकि चीन कोरोना के उद्गम को लेकर पारदर्शिता का परिचय देने में नाकाम रहा। यह पहलू निकट भविष्य में चीन को लेकर वैश्विक नजरिए को आकार देने में प्रभावी भूमिका निभाता रहेगा।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पुरानी भूल दोहरा रहा अमेरिका

कई व्यक्तियों की भांति कुछ राष्ट्र भी अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। वे बार-बार भूलों को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। अमेरिका इसका उदाहरण है। 16 दिसंबर को भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर बांग्लादेश में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। जब इसकी राजकीय तैयारियां जोरों पर थीं, तब अमेरिका ने वर्चुअल लोकतंत्र सम्मेलन में बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया। अमेरिका ने आतंक के प्रमुख गढ़ पाकिस्तान को निमंत्रण भेजा। हालांकि चीनी टुकड़ों पर पल रहे पाकिस्तान ने इस आयोजन से किनारा किया। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर भी अमेरिका ने चीन, रूस, म्यांमार सहित जिन देशों के 10 संगठनों और 15 व्यक्तियों को प्रतिबंधित सूची में डाला, उसमें बांग्लादेश का अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के सात पूर्व और वर्तमान अधिकारी भी शामिल रहे।

बांग्लादेश 18 करोड़ की आबादी वाला एक मुस्लिम बहुल देश है। इसका संविधान इस्लाम प्रदत्त है और दावा करता है कि यहां सभी गैर इस्लामी मजहबों के अनुयायियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस पर कई अवसरों पर प्रश्नचिन्ह लग चुका है, क्योंकि घोषित इस्लामी इकोसिस्टम में गैर मुस्लिमों के प्रति सहिष्णुता और बराबरी की भावना का पनपना काफिर-कुफ्र अवधारणा के कारण असंभव है। इसी कारण दुर्गापूजा के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ ने कुरान के अपमान का बहाना बनाकर चुन-चुनकर अनगिनत हिंदुओं और मंदिरों पर हमले किए। इसमें कई की मौत भी हो गई। इससे पहले इसी वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी उन्मादी भीड़ ने कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया था। क्या अमेरिका के बांग्लादेश विरोधी आचरण का कारण बांग्लादेश की उपरोक्त घटनाएं हैं? यदि ऐसा होता तो अमेरिका ने लोकतंत्र सम्मेलन में पाकिस्तान को आमंत्रित क्यों किया? इसी तरह मानवाधिकार हनन के मामले में उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? पाकिस्तान में हिंदू-सिख 1947 में 15-16 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत से कम रह गए हैं। यहां आए-दिन गैर मुस्लिम युवतियों का जबरन मतांतरण बाद निकाह करा दिया जाता है, बचे-कुछ मंदिर-गुरुद्वारों पर हमले होते हैं और ईशनिंदा के नाम पर भीड़ द्वारा आरोपित की हत्या कर दी जाती है।

अमेरिका ने जिस प्रमुख बांग्लादेशी अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लगाया, उसने हालिया हिंदू-विरोधी दंगों पर काबू पाने के साथ जिहादी कट्टरवाद-आतंकवाद की कमर तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पिता शेख मुजीबुर्रहमान की भांति पंथनिरपेक्षता की पक्षपोषक हैं। इसी कारण कट्टर बांग्लादेशी उन्हें मुर्तद (इस्लाम त्यागने वाला) मानते हैं। वहां के विपक्षी दल-बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और हिफाज-ए-इस्लाम जैसे कट्टरपंथी समूह इस्लाम में पंथनिरपेक्षता का विरोध करते हैं। यही कारण है कि जब बीएनपी सत्ता में होती है, तब वहां हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार के मामले बढ़ जाते है। इस पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा आरएबी पर कार्रवाई से वहां खालिस शरीयत के पक्षधर फिर से एकजुट होंगे, जो हसीना सरकार, हिंदू-बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों और भारत के लिए ठीक नहीं। भारत को इससे चिंतित होना चाहिए।

बांग्लादेश की इस्लामी पार्टियों को भारत-हिंदू विरोधी चिंतन की प्रेरणा इस्लामी आक्रांताओं, उनके विषैले दर्शन से मिलती है। जब दिसंबर 1971 में भारतीय नेतृत्व ने पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से निपटने के लिए सैन्य विकल्प चुना, तब अमेरिका के तत्कालीन प्रशासन ने पाकिस्तान के सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना जंगी जहाज तैनात कर दिया। चीन भी तब भारत विरोधी नीतियों के कारण पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। आज वही अमेरिका बांग्लादेशी आरएबी पर प्रतिबंध लगाकर शेख हसीना सरकार की आतंकवाद विरोधी नीतियों को कुंद करने का प्रयास कर रहा है। स्पष्ट है विश्व के किसी भी मामले में अमेरिकी उपचार बीमारी से अधिक घातक सिद्ध हुआ है। ऐसी ही गलती अमेरिका अफगानिस्तान के मामले में भी कर चुका है। 1980 के आसपास जिन मुजाहिदीनों को अमेरिका ने पाकिस्तान-सऊदी के सहयोग से सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के लिए खड़ा किया और उन्हें हथियार-पैसे दिए, वह 1994 से तालिबान बनकर क्षेत्रीय शांति-सुरक्षा को गंभीर चुनौती दे रहा है। यही नहीं, 2001 में 9/11 आतंकी हमले के बाद जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ा, जिसमें उसके 7,000 से अधिक सैनिक तालिबानी गोली का शिकार बने, उसी तालिबान को अच्छे-बुरे में बांटकर उसने समझौता कर लिया।

● **कुमार विनोद**

पाक की फिर मदद शुरू की

अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान के लिए मदद शुरू कर दी है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए खतरनाक है। यह ठीक है कि सभी जिम्मेदार देशों की विदेश-नीति में अपना हित सर्वोपरि होता है, किंतु उन्हें श्रेष्ठ जीवंत जीवन मूल्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। अमेरिका जहां सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है, वहीं भारत इस संदर्भ में सबसे बड़ा देश है। जैसे आज इन दोनों देशों में एक स्वाभाविक सहयोग है, वैसा दशकों पहले होना चाहिए था, किंतु अमेरिका ने अपने विशुद्ध हितों के लिए सोवियत रूस से शीतयुद्ध की आड़ में आतंकवाद के कारखाने पाकिस्तान का सामरिक-आर्थिक समर्थन किया और आज भी स्थिति अधिक बदली नहीं है। अमेरिका फिर वैसी ही गलती दोहरा रहा है। उसके द्वारा आरएबी पर प्रतिबंध लगाना और पाकिस्तान को लोकतंत्र मानना, इसका प्रमाण है।

लड़कियां नापते दूल्हे राजा..!

जब कभी 16 साल की एक लड़की अपने सपनों में दूल्हे के साथ खुद को पाती है, एक गोरेपन की क्रीम न जाने क्यों उसके चेहरे पर प्रश्नचिन्ह बनकर चिपक जाती है। कोई अपने आप को तयशुदा लहंगे में फिट करने के लिए सपने में भी मीठा खाने से घबराती है, तो कोई खुद को पतला करने के लिए 3 महीने के लिए जिम की फीस चुकाती है। कभी किसी को शरीर पर अतिरिक्त उभार लाने के लिए पैडेड कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है तो कोई रोज झड़ते बालों के लिए घरेलू नुस्खे अपनाती है। किसी का कद कम तो मुश्किल, किसी की मुश्किल ही यही कि वो है लड़कों जितनी लंबी। ऐ खुदा, बार-बार क्यों इतने इम्तिहान है सजाता? एक ही सांचे से लड़कियां क्यों नहीं बनाता?

कहिए जी, देश बदल रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। वाकई, बदल तो रहा है लेकिन उन लोगों का क्या कीजिएगा जो अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं। मुश्किल ये है कि बदली सोच वाले तो उंगली पर गिनने लायक हैं और जिन पर है पिछड़ी सोच का साया उनकी संख्या है ज्यादा। ये एक मेट्रीमोनियल साइट पर पूरे होशो हवास में दिया गया विज्ञापन है। जिसमें कहा गया है कि लड़की अलां दर्जे तक पढ़ी, फलां गुणों से भरी होनी चाहिए। गुणों की इस फेहरिस्त में शामिल है- सुंदर चेहरा, गोरा रंग, दुबली लड़की, पारंपरिक सोच के साथ एकदम सही नाप में मॉर्डन विचारधारा, आदि। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लड़के ने इसके आगे जाते हुए लड़की के ब्रा साइज, कमर के नाप और पैरों के साइज को भी तयशुदा पैमाने के हिसाब से होने की मांग की है। इतना ही नहीं लड़का चाहता है कि लड़की मैनीक्योर-पैडीक्योर किए रहे, उसका ड्रेसअप 80 प्रतिशत कैजुअल और 20 प्रतिशत फॉर्मल हो और इससे भी आगे इस तरह की बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं लिखा जा सकता। किसी ने इन जनाब को ये नहीं कहा है कि सिंड्रेला की खोई जूती की तरह ये भी इंच टेप लेकर निकल पड़ें।

देशभर में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपनी बेटियों को नापने के लिए इनके आगे बिछा देंगे। हालांकि इस विज्ञापन को लेकर कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है और खुद उस मेट्रीमोनियल ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का और ऐसे लोगों को अपने मंच से हटाने का वादा भी किया है। बहरहाल सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं? क्या हमारे ही समाज से आते हैं? जवाब है हां, ये लोग हमारे ही आसपास मौजूद लोग हैं जो इसी सोच के साथ जीते हैं और इसी सोच को बढ़ावा देते हैं। तयशुदा पैमाने के हिसाब से दुल्हन ढूंढने वाला यह भारत का अकेला लड़का नहीं है। ऐसे लोग भरे पड़े हैं। उससे भी ज्यादा गलत यह है कि अब भी लड़कियों को भी इसी सोच के साथ बड़ा किया जाता है।

अगर आपको लगता है कि टीवी में दिख रही, शहरों में बड़ी कंपनियों में काम कर रही, यूट्यूब के चैनल्स में ग्लैमर के साथ पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात कहती लड़कियों का क्या? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कुल लड़कियों का मुट्ठीभर भी नहीं है। उस पर इनमें से भी अधिकांश लड़कियां इसी सोच के साथ बड़ी की जाती हैं कि उनका दिखना उनके टिकने से ज्यादा जरूरी है।

पिछले दिनों एक मनोरंजक कार्यक्रम के बीच में आए विज्ञापन ने इस विश्वास को और भी बढ़ाया। इस विज्ञापन में एक गोरी, छरहरी लड़की फोन पर बात करते हुए एक गाड़ी में आकर बैठती है और कहती है ड्राइवर फलां जगह चलो। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है-अरे सॉरी, मैं समझी मेरी टैक्सी है और लड़का मुस्कुराहट के साथ अतिरिक्त विनम्रता के साथ अपना पोर्टफोलियो परोसते हुए कहता है-वैसे तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं लेकिन आपके लिए टैक्सी ड्राइवर भी बन सकता हूं। अब यहां तक भी ठीक था लेकिन फिर आता है वह ब्रांड जो लड़की को और आकर्षक बनाने का दावा करता है, क्योंकि उसके बिना तो लड़का, लड़की की तरफ देखता भी क्यों भला? मतलब अगर आप आकर्षक नहीं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं ही मिलने का रे बाबा।

इसी के साथ एक युवती की बात याद आती है। जिसके माता-पिता 19 की उम्र में उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री से ज्यादा उसकी शादी के लिए आतुर थे। मुश्किल ये थी कि बच्ची का वजन अधिक था और तमाम दहेजी प्रलोभनों के बावजूद लड़की का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा था। आखिर घर वालों ने जबरदस्ती उस लड़की को जिम जॉइन करवाया और बाहर के सारे खाने पर सख्ती से रोक लगा दी। और जिम के पहले दिन ही घर के बाहर अपनी टू व्हीलर स्टार्ट करते हुए, लड़की ने रोते-रोते कहा-बस ये शादी तक के लिए छोड़ रही हूं। इसके बाद मुझे समोसा खाने देना।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

बाजार तय कर रहा है लड़की का फिगर

बाजार में मौजूद तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक अपने शौक से रूप निखारने के लिए उपयोग में लाए जाएं तो फिर भी जायज लगते हैं। लेकिन अगर इनका उपयोग जबरन का नियम बन जाए तो ये बोझ हो जाते हैं। केवल कॉस्मेटिक्स ही क्यों, आजकल बाजार में शेपवेयर के नाम पर शरीर के तमाम हिस्सों को उभारने वाले साधन मिल रहे हैं और इससे भी बात न बने तो सर्जरी का ऑप्शन भी है। बस आपकी जेब में दम होना चाहिए, फिर तो काली लड़की को गोरा दिखाना और मोटी लड़की का वजन घटाना बाजार खूब जानता है। तो जब तक इस बाजार के भाव बढ़ने वाले हैं ये बाजार भी जिंदा रहेगा।

निरंतरं वर्द्धताम्

श्रीमद्भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि के संपूर्ण आध्यात्मिक पक्षों का समावेश किया गया है। श्रीमद्भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। श्रीमद्भागवत गीता सिखाती है कि मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और धर्म का पालन किस तरह करना चाहिए। गीता का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। विश्व का कोई भी देश मात्र आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से उन्नत नहीं हो जाता। जब तक कि वह आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से सबल नहीं हो, उसकी प्रगति अधूरी ही है। वर्तमान में भारत के पास सब क्छ छ है, परंतु क्रमशः नई पीढ़ी जिन पर राष्ट्र के उत्थान की महान उत्तरदायित्व है, उनमें नैतिक और चारित्रिक बल की कमी सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगचर हो रही है। अतः भारत देश की युवा पीढ़ी को चरित्रवान बनकर नैतिक एवं आदर्श नेतृत्व प्रदान करना ही होगा। भगवद्गीता के इस हीरे जैसे अमृत मंत्र को युवा पीढ़ी ने अपने अवचेतन मन मे आजीवन अंगीकार करना ही है कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, उसी को अन्य मानव भी अनुसरण करते हैं। अपने आचरण से ऐसे मूल्य स्थापित करने चाहिए जिनसे अन्य लोग प्रेरणा ले सकें।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।

इस दिव्य मंत्र का विवेचन को अपने अवचेतन मन में आत्मसात करें। यह निश्चित रूप से स्वभाव सिद्ध है कि श्रेष्ठ महापुरुष ही अनुवर्तन-पालन के श्रेष्ठ निर्धारक होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने धर्म योग के अनुपालन के लिए महापुरुषों को अग्रसर होने के लिए विशेष प्रेरणा- संदेश दे रहे हैं। हे अर्जुन! ज्ञान के माध्यम आत्म स्वरूप को प्राप्त महापुरुष के लिए यद्यपि कर्म सापेक्ष नहीं है, तथापि अपने पीछे वाले अनुवर्ती जनों के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्मों का आचरण संसार में करना ही चाहिए, जिसे देखकर अन्य उर्ध्वगामी मुमुक्षुजन कर्म करने में प्रवृत्त होंगे, क्योंकि अभी जो अद्यात्म मार्ग के पथिक हैं, एतदर्थ उनके लिए कर्म का पालन अनिवार्य है। उन कर्म समूहों में कुछ कर्म के स्वरूप को देखकर भयभीत न हो जाएं। आगे श्रेष्ठ महापुरुष को देखकर निर्भीक कर्म के अनुगामी बनें। इसीलिए महापुरुषों को शास्त्र विहित श्रेष्ठ कर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे महापुरुषों के अनुगामी, अनुयायी अद्यात्म मार्ग के पथिकों को संबल साधन की सुप्रेरणा मिले- सद्कर्म के अनुपालन की शक्ति का संचरण संवर्द्धन सुनिश्चित हो। इसीलिए महापुरुषों को सद्कर्म पालन का भगवान श्रीकृष्ण का निर्देश है। इसके होने से संसार में कर्म स्वरूप के प्रवर्तन की निरंतरता अक्षुण्ण रहेगी। इसी अक्षुण्णता के लिए ही महापुरुषों को श्रेष्ठ गुणों का आचरण करना ही चाहिए।

मानव जीवन विकास के लिए ही प्राप्त है। नित्य निरन्तर शास्त्रानुमोदित विकास के लिए यत्न करने वाला मनुष्य ही सदा के लिए शुभकारक तथा सुखी रहता है।

स्वदोषदर्शनं पुण्यं, प्रभुकृपावलम्बनम्।
स्वहित यत्नस्तु, जीवनोद्धारसाधनम्।।

अर्थात्- अपने दोषों का दर्शन पुण्यकर्म है। इसके साथ प्रभुकृपावलम्बन, स्व हिताय संपूर्ण यत्न जीवन विकास साधन है।

मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास- जिस विकास में प्रेय और श्रेय की प्राप्ति की सुनिश्चितता अग्रसर हो, उसके लिए भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ होने की सुप्रेरणा दी गई है। स्थितप्रज्ञ मानव को ही 'मुनि' श्रेष्ठ शब्द से भगवान श्रीकृष्ण ने प्रतिस्थापित किया है। इसका लक्षण इस निम्न शब्द परिधि में अग्रसर किया है। यथा सभी प्रकार के दुखों के संजोग में मन कभी भी उद्विग्न न हुआ हो।

संपूर्ण इंद्रियों के विषय सुख संयोग के प्राप्ति होने पर भी उन सुखों की प्राप्ति के लिए वासना न रहे और जिनके मन में राग भय क्रोध का निवर्तन हो चुका है अर्थात् मन राग भय क्रोध से निवृत्त हो चुका है। इन उदात्त उच्च गुणों युक्त महामानव ही स्थितप्रज्ञ मुनि होते हैं। ऐसे महापुरुष-महामानव-स्थितप्रज्ञ मानव द्वारा लिए गए निर्णय सदैव ही सफल होते हैं- अक्षुण्ण होते हैं-आत्म कल्याणकारी होते हैं। ऐसे मानव अपना हित करते हुए संपूर्ण संसार के लिए हितकारक होते हैं। ऐसे महामानव ही ईश्वर के प्रिय पात्र भी होते हैं। इसी उत्कृष्ट परिधि में मानव और समाज को अवस्थित करना होगा, तभी भारत राष्ट्र संसार के विश्व गुरु की महत- सारस्वत गरिमा को प्राप्त करेगा।

वस्तुतः आत्मा केंद्रित मन होना चाहिए, परंतु संसार संबंध के कारण मन संसार रत रसिक हो गया है और वह दसों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों का नियंत्रक बन गया है, जिसके कारण से वह आत्मा को अधीन करने का प्रयास किया है। यही आत्म हानि का मुख्य कारण है। इस हानि से त्राण- रक्षा के लिए भगवान कृष्ण का अमूल्य निर्देश है- मन से आत्मा का उद्धार करो। मन से आत्मा को पीड़ित-अवसाद ग्रस्त मत करो। जो मन संसार का साथ देता है, उसी से अवसाद-तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे संसारासक्त मन से आत्मा को पीड़ित-व्यथित-अवसाद ग्रस्त मत करो। शरीर के बाहर संसार में शत्रु मित्र का निर्धारण मत करो। शरीर के बाहर संसार में शत्रु मित्र का निर्धारण महा भ्रम है। हे मानव! तेरे मन के भीतर ही शत्रु मित्र का जो प्रवाह चल रहा है, उसे पहचानो।

आत्मानुकूल जो शुद्ध पवित्र विश्व बंधुत्व व परहित का मन है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। इसका विस्तृत अर्थ यह है कि धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकल, वेद के अनुकूल, उपनिषद् के अनुकूल जो मन चलता है, सदव्यवहार करता है, यही मन सच्चा मित्र है। मित्र दो शब्दों से बना है 'मि' और 'त्र'। 'मि' अर्थात- मिलकर जो सब तरह से 'त्र' त्राण करे-रक्षा करे, वही मित्र होता है। वह सच्चा मित्र धर्मानुकूल मन ही होता है और धर्म के जो प्रतिकूल है, वही मन तुम्हारा शत्रु है। यहां धर्म से शास्वत धर्म परमात्मा को लेना चाहिए अर्थात् परमात्मा के प्रतिकूल मन ही आत्मा का शत्रु है। इसी परमात्मा के अनुकूल मन को करने के लिए श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता अमृत का संचार किया। तब 18 अध्याय सुनने के पश्चात ही अर्जुन ने अपना मन धर्म के अनुकूल कर लिया।

● **ओम**

धर्म

साहब अपनी पत्नी पर झल्ला रहे थे। वे कह रहे थे, 'मैडम, जल्दी करिए। सुलेमान ड्राइवर कब से आकर बैठा हुआ है। क्या हमें मंदिर नहीं जाना? क्या हम आरती के बाद जाएंगे?'

पत्नी अपने काम में लगी रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया।

तभी साहब को खयाल आया कि आज तो रमजान की आखिरी नमाज है और उसका वक्त भी हो चला है। वे फौरन बाहर निकले और सुलेमान से कहा, 'तुम गाड़ी लेकर फौरन मस्जिद चले जाओ। हम मंदिर बाद में जाएंगे।'

सुलेमान ने कहा, 'साहब, पहले मंदिर ही चलते हैं। मैं मस्जिद बाद में चला जाऊंगा।'

मगर साहब नहीं माने। उन्होंने सुलेमान को प्यार से डांटते हुए कहा, 'आज तुम्हारी आखिरी नमाज है। जाओ, पहले उसे अदा कर आओ।'

सुलेमान गाड़ी लेकर चला गया। मगर जल्दी ही लौट आया। साहब ने पूछा, 'क्या तुम मस्जिद नहीं गए?'

'साहब, पास वाली मस्जिद में ही नमाज पढ़ आया। अब जल्दी मंदिर चलिए। आरती शुरू हो रही होगी,' सुलेमान ने कहा।

इस बीच साहब की पत्नी तैयार हो चुकी थी। सभी गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ चल पड़े। साहब और उनकी पत्नी खुश थे कि सुलेमान ने उनकी आरती का बड़ा खयाल रखा। उधर सुलेमान भी बड़ा प्रसन्न था कि साहब की मदद से आज आखिरी नमाज अदा हो गई।

- ज्ञानदेव मुकेश

ज्ञान-धारा

एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा- 'भगवन! जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे बैठते हैं और आप ऊंचे आसन पर बैठते हैं, ऐसा क्यों?' भगवान बुद्ध बोले- 'ये बताओ कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर पिया जाता है या नीचे जाकर?' आनंद ने उत्तर दिया- 'झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है। अत: उसके नीचे जाकर ही पानी पिया जा सकता है।' भगवान बुद्ध ने कहा- 'तो फिर यदि प्यासे को संतुष्ट करना है तो झरने को ऊंचाई से ही बहना होगा न?' आनंद ने 'हां में उत्तर दिया।' यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले- 'आनंद! ठीक इसी तरह यदि तुम्हें किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही प्राप्त कर सकते हो और तुम्हें देने के लिए दाता को भी ऊपर खड़ा होना होगा। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो तो तुम एक ऐसे सागर में बदल जाओगे, जो ज्ञान की सभी धाराओं को अपने में समेट लेता है।'

- अनाम

घरघराहट

इस बंद घर की
सारी खिड़कियां खुली हैं
पर खिड़कियों में
न चिड़ियां हैं, न हवा
न चांद की कंदील,
न सूखे पत्तों का दिठौना
इतिहास तो है
हर आले और चौखट में घर की
लेकिन कमरों का कोई आगत नहीं
एक बदरंग पत्थर पर
उत्कीर्ण एक नंबर भी है
और नाम मेरा
एक आईना है इसके आंगन में
चुपचाप बिसूरता
एक आंसू-सा है कुछ खारा
धुंधला रहा और चीरता
एक शब्द है इस घर की निस्तब्धता में
धीरे-धीरे भरे गले से घरघराता
शायद, विदा
शायद, अम्मी
शायद, कहां
धुआं
वह होगी अब पंद्रह सोलह बरसों की
जाने कितने सपनों में जगी
किसी सड़क पर जल्दी-जल्दी चलती
या बैठी कोई पुस्तक पढ़ती
कितनी मेधावी थी
जब वह मेरी मां थी
भले आठ जमात पढ़ी थी!
इसीलिए उसको अब
मैं याद नहीं करती।
कितने दु:ख थे उसके
कितने अपनों ने उसे दिए
फिर भी वह नाराज नहीं थी,
बस दिए की बुझती बाती-सी
राख भरी थी
मेरी मां मरी नहीं थी!

- डॉ. सुनीता जैन

बेवजह विवाद!

तानाशाही खत्म होनी ही थी

चयनकर्ताओं का यह सोचना सही हो सकता है कि रवि शास्त्री और कोहली, दो लोगों की तानाशाही खत्म होनी ही थी। इसके अलावा, कोहली ने जब टी-20 की कप्तानी छोड़ दी तो सफेद गेंद से खेले जाने दोनों फॉर्मेट के लिए दो कप्तान रखने का कोई अर्थ नहीं रह गया। कोहली का फॉर्म भी गड़बड़ हो गया, तो उन्हें बैटिंग की अपनी जबरदस्त प्रतिभा पर देने की जरूरत बढ़ गई। वैसे भी, अब वे 30 से ऊपर की उम्र में पहुंच गए हैं। हम यह सब मान लेते हैं। एकमात्र सवाल, जिसका कोई जवाब नहीं है और न कोई मान्य जवाब हो सकता है, यह है कि क्या यह सब इतने खराब तरीके से करना जरूरी था? सभी फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल कप्तान को खारिज करना? यह डालमिया-बिंद्रा-श्रीनिवासन-पवार-ठाकुर युग की वापसी नहीं है। वे उस दौर में लौट गए हैं जब बोर्ड बिशन सिंह बेदी या मोहिंदर अमरनाथ को मनमाने तरीके से अपमानित करता था या कोई विजय मर्चेन्ट एक युवा मंसूर अली खान पटौदी को बेआबरू करके, बिना कोई कारण बताए कप्तान के पद से हटा देते थे।

भारतीय क्रिकेट और विवादों का रिश्ता शायद ही कभी टूटता है। इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि अधिकतर विवादों की वजह पराजय और बेइज्जती हुआ करती थी। 14 मार्च 2001 तक ऐसा ही होता था, जब सौरभ गांगुली की टीम में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड ने पूरे दिन बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया को आखिरी क्षणों में चमत्कारी जीत दिलाने का आधार तैयार किया था। इसके बाद, खासकर टेस्ट क्रिकेट में भारत के वर्चस्व के दो दशक का युग शुरू हुआ। भारत का उत्कर्ष इतनी तेजी से हुआ कि उसके बाद उसने ग्रेग चैपल के बदनुमा दौर को नाक-भौं सिकोड़ते हुए न सही, आराम से परे धकेल दिया। बीच में महेंद्र सिंह धोनी आए लेकिन समय के साथ विराट कोहली ही गांगुली के सच्चे उत्तराधिकारी साबित हुए। यह गली-मोहल्ले के क्रिकेट की आक्रामकता वाला, उज्जड कहे जाने पर गर्व करने वाला और ऑस्ट्रेलियाइयों को उनके ऑस्ट्रेलियाइपन में मात देने वाला क्रिकेट था।

यह भी एक विडंबना है कि जिन शानदार लोगों ने भारतीय क्रिकेट को ऐसे गौरवपूर्ण शिखर पर पहुंचाया वे ही अब उसे उस शिखर से नीचे धकेलते दिख रहे हैं। गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, द्रविड कोच हैं, लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख हैं और सर्वविजेता टेस्ट कप्तान कोहली अब निशाने पर हैं। इस मुकाम पर हम कैसे पहुंच गए, यह क्रिकेट नाम की सबसे धर्मनिरपेक्ष भारतीय आस्था के बड़े-से-बड़े पंडित या आयातुल्ला के लिए भी समझ पाना मुश्किल है और तमाम क्रिकेटप्रेमी तो नाराज हैं ही। पहली बात तो यह है कि यह करोड़ों लोगों की भ्रामक मगर मर्मस्पर्शी धारणा को चुनौती दे रहा है। अब तक लोग यही मानते रहे कि भारतीय खेलों, खासकर क्रिकेट के साथ सबसे बुरी बात यह है कि खेलों के तमाम संगठनों की बागडोर गैर-खिलाड़ियों के हाथ में है। पहली बार हमने बागडोर एक आला और काफी हद तक समकालीन क्रिकेटर के हाथ में सौंपी। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी नाव भारतीय क्रिकेट के लिए आखिरी मोर्चे, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने वाली थी कि उसमें छेद हो गया।

हाल के वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो और इंग्लैंड में एक सीरीज जीत चुका है, जबकि घर आने वाली टीमों पर झाड़ू फेरता रहा है। वेस्टइंडीज अब टॉप टीम नहीं रह गई है, न्यूजीलैंड का हम अक्सर दौरा करते रहते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हम सीरीज नहीं जीत पाए हैं। फिलहाल दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट नस्लवादी विवाद, खिलाड़ियों के चोटिल होने, और प्रतिभा पलायन आदि के मिलेजुले असर के कारण संकट में है। कोहली के खुशमिजाज साथी यात्रियों के लिए इस अंतिम गढ़ को फतह करने का यह सुनहरा मौका है। लेकिन, बीसीसीआई ने क्या किया? टीम के रवाना होने से एक सप्ताह पहले कोहली पर हमला कर दिया, इसके बाद भी उन्हें और तरह से शर्मसार किया। शुरू में 'दोस्ताना' मीडिया में अटकलों और अफवाहों को बढ़ावा दिया गया, जिनमें से कुछ तो बिलकुल गलत थीं। इनमें सबसे बेतुकी फैलाई गई कि कोहली ओडीआई सीरीज इसलिए नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि उसी दौरान उनकी बेटी का जन्मदिन पड़ेगा।

सूत्रों के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि कोहली ने बोर्ड को ऐसी कोई बात नहीं कही। बोर्ड के 'सूत्रों' का जवाब यह था कि ठीक है, उन्होंने हमसे वैसा कुछ नहीं कहा होगा लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम अपने कुछ करीबी दोस्तों से इस बात का जिक्र किया था। अब, हम यह नहीं कह सकते कि बोर्ड ड्रेसिंग रूम में होने वाली बातचीत को गुप्त रूप से सुनने के यंत्र रखता है या नहीं, या खिलाड़ियों के फोन में पेगासस खूफिया यंत्र लगाता है या नहीं। लेकिन उसे कोहली से बात करने से कौन रोक रहा था? तथ्यों और तारीखों पर गौर करने से पता चलता है कि जिसने भी सफाई देने की कोशिश की उसे पूरी बात नहीं पता थी। बेटी का जन्मदिन ओडीआई सीरीज के बीच नहीं पड़ता था बल्कि तब पड़ता है जब कोहली, अगर फिट रहे और टीम के लिए चुने गए तब, अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। बोर्ड के जहीन लोग ऐसी गलती कैसे कर बैठे? क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया।

दुखद बात यह है कि टीम के चयनकर्ता और बोर्ड यह तर्क पेश कर सकते हैं कि कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान नहीं बने रह सकते। कोहली ने यह घोषणा करके उनके लिए दरवाजा खोल दिया था कि अब वे टी-20 टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। तब चयनकर्ताओं का यह तर्क ठीक हो सकता है कि सफेद गेंद से खेले जाने दोनों फॉर्मेट, टी-20 और ओडीआई के लिए साझा कप्तान रखना महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की छोटी-सी दुनिया में अलग-अलग कप्तान रखने का ही चलन है, सिवाय न्यूजीलैंड और अब तक भारत के, क्योंकि केन विलियमसन और कोहली अपने कद, सभी फॉर्मेट में शानदार निजी प्रदर्शन और अपनी टीम के प्रदर्शन के कारण निर्विवाद अगुवा बने।

● आशीष नेमा

जिंदगी के उतार-चढ़ाव को सीरियसली नहीं लेतीं चित्रांगदा

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की हालिया रिलीज फिल्म बॉब बिस्वास रही है। इसमें उनका किरदार बॉब बिस्वास की वाइफ का था, जो साधारण-सी बंगाली क्रिश्चन औरत है। वो बैंक में काम करती है, जहां पर उसका बॉस उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में घर और ऑफिस को मैनेज करती चित्रांगदा सिंह का बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान चित्रांगदा ने फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर की।

चित्रांगदा ने फिल्म के खाली समय को लेकर कहा- हम लोग जब शूट नहीं कर रहे होते थे, तब अभिषेक बच्चन अपनी कहानियां सुनाते थे। उनके फादर अमिताभ बच्चन इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके पास बहुत किस्से-कहानियां होते हैं। वो सुनाते भी बड़े दिलचस्प तरीके से थे, जिसे सुनकर हम सबको बड़ा मजा आता था। वो बता रहे थे कि कैसे खुदा गवाह, सहित तीन फिल्में एक साथ मुकुल आनंद शूट कर रहे थे। इन तीनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन थे। वो बताते थे कि कैसे बिग बी एक के बाद एक फिल्म की शूटिंग करने जाते थे। जब भी मैं अपनी शूटिंग के बारे में सोचती हूं, तब मुझे ये किस्से याद आते हैं। ऐसे किस्से हमें कभी पढ़ने को नहीं मिलते हैं।

जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा- सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई भी आऊंगी। जब लाइफ में उतार-चढ़ाव आता है, तब मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती हूं। बैक सपोर्ट के लिए फैमिली सबसे बड़ी ताकत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखते हैं, जिनकी लाइफ में भी उतार-चढ़ाव आए हैं। मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेती हूं। डायरेक्शन में हाथ आजमाने के सवाल पर चित्रांगदा ने कहा- डायरेक्शन के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं है। आगे क्या होगा, इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती हूं। अभी तो बतौर एक्टर मुझे बहुत सारा काम करना है। अच्छे लोगों के साथ काम करूं, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।

गोविंदा ने 21 साल की उम्र में साइन कर डाली थीं 49 फिल्में

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। गोविंदा की मानें तो उनकी मां कभी नहीं चाहती थीं कि वे एक्टर बनें। गोविंदा के अनुसार, मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे, जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा- तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा। फिर एक दिन मैंने मां से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ-साथ मुझसे कहा- नो शराब, नो सिगरेट। यदि तुम ट्राय करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। गोविंदा ने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। फिल्म का नाम था हत्या (1988)। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया था कि 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थीं।

जब पत्रकार ने मां के सामने सारा के झूठ का किया था पर्दाफाश

एक्ट्रेस सारा अली खान ने एक खुलासा किया कि एक जर्नलिस्ट ने मुझे मां अमृता सिंह के सामने एक्पोज कर दिया था। सारा ने कहा, एक बार मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उनको बोला मैं अपने पड़ोसी के घर पर हूं, लेकिन मैं लोकल ट्रेन पकड़ कर एलफिंस्टन रोड चली गई थी। सारा ने कहा कि एलफिंस्टन रोड पर मैं एक और दोस्त से मिलने गई है। हालांकि जब मम्मी ने अगले दिन मुझसे पूछा तो मैं अपनी कहानी पर अड़ी रही थी। सारा ने आगे कहा कि असल में मम्मी को किसी पत्रकार ने फोन किया और बोला, अमृता जी, आपने अपनी बेटी इतनी अच्छी परवरिश करी कि वह लोकल ट्रेन से सफर करती है...। दरअसल, अपनी फिल्म अतरंगी रे के प्रमोशन के दौरान द कपिल शर्मा शो में सारा अली खान ने ये बातें कहीं। कपिल ने सारा से पूछा कि क्या आखिरी बार उसने अमृता को झूठ बोला था कि वह कहां है या क्या कर रही है। सारा ने जवाब में कह उसके बाद भी लेकिन फोटोज अब तक नहीं छपीं। गौरतलब है कि 1991 में शादी करने के बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह ने साल 2004 में तलाक ले लिया था। तलाक के बाद दोनों बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम की कस्टडी अमृता को मिली थी।

लोकतंत्र का चुनावी महाभारत

जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, कुछ नेताओं की जुबान कुछ अधिक ही लंबी हो जाती है। पहले के समय में इसकी नाप-तौल हो जाया करती थी कि किस नेता की जुबान डेढ मीटर की है और किसकी ढाई मीटर की है? अब यह जान पाना बहुत ही मुश्किल हो चला है। असली चेहरों की पहचान कठिन है। कोरोना के भय ने मुंह ही नहीं, नाक तक को मास्क से ढक रखा है। कहते हैं कि महाभारत में इसी गफलत के चलते बेचारा जयद्रथ मारा गया था। श्रीकृष्ण ने सूर्य को अपने चक्र रूपी मास्क से ढक दिया था। आज भी चुनाव में अपने विरोधी को गच्चा देने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। 'अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो वा' वाली युक्ति लगानी पड़ती है। जिस अभिमन्यु को हराना होता है, उसे महारथी और बाहुबली के विरुद्ध टिकट थमा दिया जाता है।

चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। यह दीगर बात है कि कभी किसी ने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को बिगुल बजाते हुए नहीं देखा होगा। आज की नई पीढ़ी ने तो बिगुल ही नहीं देखा है। यह संग्रहालय में मिलता है। जो भी चुनाव हारता है, उसको कम से कम पांच बरस का अज्ञातवास भोगना अनिवार्य है। इन दिनों वे इस पर गहन मंथन कर रहे हैं कि आगे किस प्रकार के मुद्दे उछाले जाएं।

ऐसे ही एक दल की बैठक में एक नेता ने कतिपय नए और भ्रामक नारे गढ़ने का काम एक खास दस्ते को सौंपने की जानकारी दी। दूसरे ने बताया कि किन-किन इलाकों के बाहुबली बराबर उसके संपर्क में हैं और वे सब इस समर की हवा को कैसे उनके पक्ष में करेंगे। एक अन्य असहनीय और विवादमूलक मुद्दों के अग्निबाण छोड़ने की सलाह दे रहा है। पार्टी प्रमुख को उनकी यह समर-नीति पसंद आ रही है। वैसे भी इस समय प्रत्येक प्रत्याशी की सत्यवादी की तुलना में सत्तावादी छवि का होना ही श्रेयस्कर है।

यह लोकतंत्र का चुनावी महाभारत है। यहां कौरव और पांडव दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। उनकी दशा चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु जैसी ही हो रही है। इस महासमर में सप्तम द्वार को भेदने की जुगत लगाई जा रही है। दुर्योधन के बोल बिगड़े हुए हैं। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने में तनिक संकोच नहीं कर रहा है। चाचा, ताऊ, पिता, मामा, बुआ, फूफा, दीदी, बहन सभी आमने-सामने हैं। अजरुन भ्रमित हैं। सहदेव की सहनशक्ति जवाब दे रही है। शकुनि की बिछाई बिसात के आगे युधिष्ठिर की चालें बेमानी नजर आ रही हैं। श्रीकृष्ण मौन हैं।

वैसे तो इसे आप सरसरी तौर पर एक धर्मयुद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी एक आचार संहिता लागू होती है, किंतु यह भी देखा जा रहा है कि कई योद्धा अधर्म युद्ध पर भी आमादा हैं। समूचे समर क्षेत्र में धर्म और जातियों के ध्रुवीकरण का फ्लू संक्रामक रूप से पसर चुका है। इस रोग के निराकरण का यक्षप्रश्न अनुत्तरित है। इस महाभारत में बहुत सारे भीष्म पितामह भी हैं, किंतु दलगत हितों के चलते उन्होंने अपने मुंह पर टेप चिपका लिए हैं।

सभी वीर योद्धा प्रत्याशी, जिन्हें चुनावी महाभारत का अनुभव और दक्षता, दोनों ही प्राप्त हैं, अपनी वाकपटुता और वादों के अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर चुनाव के मैदान में जिधर से भी मौका पा रहे हैं, उधर से प्रहार कर रहे हैं। उनके समर्पित कार्यकर्ता भी अपने-अपने महारथियों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपने को पांडव और विपक्षी को कौरव सिद्ध करने पर उतारू हैं। चुनाव की हांडी में प्रचार की मथानी चल रही है। इसके चलते हस्तिनापुर के वोटर का दिमाग दही हो गया है। वह तय नहीं कर पा रहा है कि किस पक्ष को विजय का मक्खन खिलाए और किस को अंजुरी भर छाछ देकर टरका दे।

मेरे मित्र चिड़चिड़े लाल को भरोसा है कि उनका गठबंधन इस बार परिवर्तन लाकर मानेगा। मैंने उससे कहा, 'प्यारे भाई, तुम कितनी भी उछलकूद कर लो, यह चुनावी महाभारत है इसलिए इसमें विजय उसी की होगी, जो धर्म के साथ रहेगा। अधर्मधारी की पराजय एक युगसत्य है, जिसके दृष्टांत सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मिलते हैं। फिर इस कलियुग ने ऐसा कौन-सा घनघोर पाप किया है? इस युग में भी धर्मधारकों की विजय सुनिश्चित है।'

● **सूर्यकुमार पांडेय**

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17088

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687